राष्ट्रीय संस्करण

कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला
>> 12

वर्ष 10 अंक 37

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शनिवार, 18 जुलाई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

यात्रा

प्रकृति का साक्षात्कार, बस्तर यात्रा को बनाएगा यादगार

जगदलपुर : घाटी की सर्पीली सड़कें, बादलों से घिरा हिल स्टेशन, झरने और प्राचीन शैलचित्र इस सफर को बनाते हैं खास। ● पेज-7

संपादकीय

बार-बार के चुनावी भंवर से निकले देश : 'एक देश-एक चुनाव' को किसी दलगत राजनीति के चश्मे से देखने के बजाय इसे राष्ट्र-निर्माण के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

डा. रामानंद शर्मा का आकलन।

अतिवाद की हदों को पार करता स्त्रीवाद : जिस अमेरिका और यूरोप से स्त्रीवादी का विचार चला था, वहां की महिलाएं ही अब इस पर सवाल उठाने लगी हैं। **क्षमा शर्मा** की टिप्पणी। ● पेज-8

विमर्श

विपरीत स्थितियों में स्पेस स्टार्टअप्स क्रांति : स्पेस टेक स्टार्टअप्स पर वैश्विक निवेशक पिछले पांच साल में 6,100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुके हैं। **राहुल लाल** का विश्लेषण।

विपक्ष ने एनडीए को दे दिया खुला मैदान : बिहार की एनडीए सरकार के लिए यह सुखद है कि उसे विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ रहा है। **अरुण अशेष** की डायरी। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

जोश नई राहों का

नए अवसरों के निर्माता बनें युवा

मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी अनुशासन ● पेज-13

भाजपा के टिकट पर रास के लिए निर्विरोध चुने गए सुखेदु, सुष्मिता व प्रकाश पेज>>4

नागरिक ठिकानों पर और तेज हुए अमेरिका-ईरान के हमले पेज>>11

चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ऐसा करने वाला पांचवां देश बना भारत

सुधीर तंवर ● जागरण

- प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी, स्वदेशी तकनीक से किया गया तैयार, नहीं छोड़ेगी धुआं

10 डिब्बों वाली ट्रेन में 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल-सेल प्रणाली से बनेगी बिजली

89 किमी के ट्रैक पर पहले चरण में होगा परिचालन, दो घंटे में यह दूरी करेगी करेगी तय

हरियाणा के जींद में शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र >>

जींद : स्वच्छ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए शुक्रवार को देश ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से जींद-सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन 'मेक इन इंडिया' अभियान का सफल उदाहरण है। भारतीय तकनीक से डिजाइन की गई यह ट्रेन स्वच्छ, टिकाऊ और भविष्य की रेल तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जींद-सोनीपत के बीच यात्रा दो घंटे में पूरी होगी।

इस मौके पर मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को गति देने के साथ देश को हरित रेल तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य प्रदूषण को जीरो तक लाने का है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध के चलते निर्मित स्थिति में होर्मुज की प्रासंगिकता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस समुद्री रास्ते से भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और किसानों के लिए खाद मंगवाता है, वह कई माह से प्रभावित हैं। हार्मुज आए दिन बंद कर दिया जाता है। अगर साल 2014 से पहले ऐसी स्थिति आती तो रेलवे का काम ठप हो गया होता, क्योंकि 2014 में हमारी अधिकतर ट्रेनें सिर्फ डीजल से संचालित थीं। अगर डीजल आना बंद हो गया होता तो बदतर स्थिति हो जाती। (पेज-3 भी देखें)

रेल मंत्री ने कहा- मैं इंजीनियरों को सेल्यूट करता हूं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब दुनिया के उन चुनींदा देशों में शामिल हो गया, जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी तकनीक उपलब्ध है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल व डीजल की जरूरत नहीं है। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व इंजीनियरों को सेल्यूट करता हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को बाद में दिल्ली तक विस्तार देने की योजना है।

तो 300 साल लग जाते रेलवे के विद्युतीकरण में

मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी। 2014 तक 90 साल में पूरे देश में रेल नेटवर्क का सिर्फ 30% ही विद्युतीकरण हो पाया था। 70% ट्रेनें डीजल से चलती थीं। जिस गति से 90 साल में 30 प्रतिशत काम हुआ, उसे 100 प्रतिशत होते-होते 300 साल लग जाते। हालांकि, बीते 12 सालों में देश के करीब 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बावजूद भी देश की रेल रुकी नहीं है। इस अवसर पर मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष की मौजूदगी में राज्य के विकास से जुड़ी करीब 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास व लोकार्पण किया।

'आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, तो डाक्टर कहलाने का हक नहीं'

नई दिल्ली : गाजियाबाद में दुष्कर्म की शिकार चार वर्षीय बच्ची को चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराने वाले दो निजी अस्पतालों और उनके डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते, तो आपको डाक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इलाज नहीं मिलने से बच्ची की मौत हो गई थी। (पेज-2)

विस्तारा ने जज का टिकट दूसरे को बेचा, लगा 1.10 लाख का जुर्माना

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 10 हजार रुपये मुकदमे में लगा खर्च शामिल है। यह राशि शिकायतकर्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार वासनीकर को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। एयरलाइंस ने 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया तो इस राशि पर सात% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। (पेज-5)

मतदाता सूची में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता : सुप्रीम कोर्ट

बिहार के मामले में स्पष्ट किया जा चुका है, नागरिकता तय करना आयोग का अधिकार नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बंगाल एसआइआर में अपीलों पर सुनवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी
- याचिका में आरोप- जिन लोगों के नाम काटे गए, उन्हें सरकारी योजनाओं से किया जा रहा वंचित

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने से नागरिकता खत्म नहीं हो जाती। बिहार एसआइआर मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें साफ किया गया था कि नागरिकता तय करने का आखिरी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर किसी का नाम नागरिकता पर संदेह के कारण हटता है, तो उसे नागरिकता कानून के तहत फैसले के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए और जब तक ऐसा नहीं होता, नागरिकता का दर्जा बना रहता है। चुनाव आयोग का नियंत्रण मतदाता सूची पर होता है, उसमें वह किसी को शामिल नहीं करने का फैसला कर सकता है। नागरिकता का दर्जा मामले में चुनाव आयोग कोई संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है। इस बारे में कानून में कोई भ्रम नहीं है।

बंगाल एसआइआर में अपीलों पर सुनवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने ये मौखिक टिप्पणियां कीं। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही थी। याचिकाओं में अपीलीय ट्रिब्युनल की सुनवाई प्रक्रिया को बेहतर बनाने के संबंध में कई मांगें की गई हैं। सुनवाई के दौरान जब एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने अपीलीय ट्रिब्युनलों में निपटारे की धीमी गति का मुद्दा उठाया और कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अभी भी 34 लाख अपीलें लंबित हैं। अभी तक लगभग 38,000 अपीलें ही निपटाई गई हैं और उनमें लगभग 70 प्रतिशत अपीलें मंजूर हुई हैं। शंकर नारायण ने कहा कि अपीलें लंबित रहने के बावजूद बंगाल सरकार ने मतदाता सूचियों से हटाए गए लोगों को पीडीएस और अन्नपूर्णा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने के लिए अधिसूचना जारी की हैं। ऐसे लोगों को जाति प्रमाणपत्र भी नहीं दिए जा रहे हैं। इन्हीं दलीलों को सुनकर जस्टिस बागची ने कहा कि बिहार एसआइआर के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है, बल्कि जब किसी व्यक्ति को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची से हटाया जाता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह उसकी नागरिकता का दर्जा तय करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे।

विसवार ब्योरे की मांग पर आयोग व बंगाल सरकार से जवाब तलब

कोर्ट ने याचिका में आपत्तियों और दावे के विधानसभावार मांगे गए आंकड़ों पर बंगाल सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में बंगाल एसआइआर प्रक्रिया से जुड़े विधानसभावार आंकड़ों की मांग की गई थी। इसमें फार्म-6 और 7 की संख्या के साथ ट्रिब्युनल के सामने अपील के लंबित रहने और निपटारे से जुड़ी जानकारी भी शामिल है।

अचल संपत्ति का दस्तावेज नहीं हो सकता नागरिकता का प्रमाण : हाई कोर्ट पेज>>5

तय समय पर ही होंगे विधानसभा चुनाव, जनगणना नहीं बनेगी बाधा

शोभित श्रीवास्तव ● जागरण

- निर्वाचन आयोग ने कहा- चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया, जरूरत पड़ने पर बदलेगा जनगणना कार्यक्रम
- अगले वर्ष खत्म हो रहा उप्र, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर की विधानसभाओं का कार्यकाल

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इन्हें तय समय सीमा के भीतर कराना अनिवार्य है। ऐसे में जनगणना का कार्यक्रम चुनाव में बाधा नहीं बनेगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई, 2027 तक है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं का कार्यकाल 28 मार्च, 2027 से पहले समाप्त हो जाएगा। परंपरागत रूप से इन राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च के दौरान कराए जाते रहे हैं। इस बार चुनावी कार्यक्रम को लेकर संशय इसलिए पैदा हुआ क्योंकि केंद्र ने एक से 28 फरवरी, 2027 के बीच जनगणना के तीसरे चरण का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस चरण में गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की गणना करेंगे। ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं के एक साथ होने को लेकर सवाल उठ रहे थे।

इस संबंध में चुनाव आयोग का कहना है कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, जबकि जनगणना कानूनी प्रक्रिया है। संवैधानिक दायित्व को प्राथमिकता दी जाएगी और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग के इस रुख से साफ संकेत मिला है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय समय पर कराने की तैयारी है। यदि जरूरत पड़ी तो जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

एसआइआर पर लोगों को विश्वास, बढ़ा मतदान इसका स्पष्ट संकेत : ज्ञानेश पेज>>5

ई-20 ईंधन विवाद में आया नया मोड़ ब्लेंडिंग है समस्या या मिलावटी ईंधन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मिलावटी ईंधन का असर-वाहनों में सल्फर व क्लोरीन की मात्रा बढ़ी

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के हालिया फैसले ने ई-20 को लेकर चल रहे विवाद को नया आयाम दे दिया है। आयोग ने एक शिकायतकर्ता को ई-20 अनुकूल न होने वाली कार देने के मामले में मारुति सुजुकी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह पहला मौका है जब किसी न्यायालय ने माना कि आटो कंपनियां ग्राहकों को ई-20 चालित वाहनों की पूरी जानकारी नहीं दे रही हैं। मारुति सुजुकी ने इस फैसले पर कहा है कि मामला ईंधन में मिलावट का है।

दैनिक जागरण ने इस बारे में विभिन्न कार कंपनियों से बात की है तो उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ महीनों में सर्विस सेंटर पर मिलावटी ईंधन से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। उनका कहना है कि ई-20 पेट्रोल से माइलेज में जरूर थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ई-10 से चल रहे वाहनों में भी इंजन की शिकायत नहीं है।

एक प्रमुख कंपनी के अधिकारी ने कहा-हमें पता चल रहा है कि कई वाहनों में सल्फर और क्लोरीन की अधिकता पाई जा रही है, जिससे इंजन, फ्यूल लाइन और रबर कंपोनेंट खराब हो रहे हैं। यह ईंधन की गुणवत्ता खराब होने की वजह से हो सकता है। ई-20 में मिश्रित एथनाल भी रबर के पुर्जों को नुकसान पहुंचाता है।

ई-20 के लिहाज से तैयार नहीं 78 प्रतिशत वाहन पेज>>10

लद्दाख में रचा गया इतिहास, भारत के पहले जियोथर्मल कुएं तैयार

जम्मू : लद्दाख के पुगा में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुएं तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित इन कुओं का लोकार्पण किया। (पेज-5)

ट्रेन टिकट न होने से खारिज नहीं हो सकता दुर्घटना का मुआवजा दावा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के बारे में अहम फैसला दिया है। कहा है कि पीड़ित को मुआवजा देने से सिर्फ इसलिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृत यात्री के पास ट्रेन का टिकट नहीं मिला। लाभकारी कानूनों की व्याख्या शाब्दिक नजरिया अपनाने के बजाय उद्देश्यपूर्ण व उदार तरीके से की जानी चाहिए। (पेज-6)

हटाए गए गोलछा, अनुराग को दिल्ली पुलिस की कमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 1994 बैच के आइपीएस हैं अनुराग कुमार, करीब 20 वर्ष से थी आइबी में तैनाती

पुलिस मुख्यालय में अनुराग कुमार (बाएं) को बेटन सौंप कर चार्ज देते सतीश गोलछा। सौजन्य :दिल्ली पुलिस >>

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा को शुक्रवार को नाटकीय अंदाज में हटाकर यूटी काडर के 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को नया आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। अनुराग कुमार करीब 20 वर्षों से दिल्ली पुलिस से बाहर प्रतिनियुक्ति पर आइबी में तैनात थे।

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुराग कुमार को उनके मूल काडर में वापस भेजने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें पुलिस आयुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। अगले दिन उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। वह दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त हैं। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, यूटी काडर के 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी सतीश गोलछा को कोई भनक भी नहीं थी कि उन्हें शुक्रवार को पद से हटा दिया जाएगा। यही वजह है कि शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे वह और दिल्ली पुलिस के तकरीबन सभी विशेष आयुक्त, राष्ट्रपति भवन के पास स्थित रिज इलाके में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

पद से हटाए जाने की जानकारी इंटरनेट मीडिया से मिली पेज>>2

रणनीति

मानसून सत्र शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, अमित शाह भी रहे मौजूद, विधायी कार्य के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा, परिसीमन विधेयक की संभावनाओं को लेकर भी विमर्श

विपक्षी वार की धार कुंद करने के लिए एकजुट राजग तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

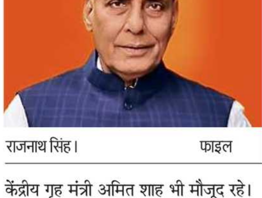

राजनाथ सिंह। फाइल

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र से लेकर अब तक देशभर में ऐसे कई घटनाक्रम हो चुके हैं, जिन्हें मुद्दा बनाकर विपक्ष सदन में गरजने और सरकार पर बरसने के लिए कमर कसे है, ऐसे में सत्ता पक्ष ने भी विपक्षी वार की धार कुंद करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई राजग मंत्रियों की बैठक में सत्र के लिए प्रस्तावित विधायी कार्यों के साथ-साथ ऐसे संभावित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि प्रत्येक विषय पर राजग का प्रतिउत्तर तार्किक हो, साथ ही सभी घटक दलों की एकजुटता का संदेश भी जाए।

राजग के बढ़ रहे कुनबे और परिसीमन विधेयक पर विपक्षी खेमे के कुछ दलों के बदले रुख के मद्देनजर आगे की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।

यूं तो संसद के प्रत्येक सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अपनी तैयारी करता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो देशभर में चर्चा के केंद्र में रहे हैं और विपक्ष को इन्हें मजबूती से उठाने का अवसर भी मिला है। मसलन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी भले ही ट्रस्ट के कुप्रबंधन का परिणाम है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा नीट-यूजी में गड़बड़ियों को लेकर लगातार हमलावर रहे विपक्ष को जंतर-मंतर पर शुरू हो चुके सोनम वांगचुक के अनशन ने नई ऊर्जा दी है। ई-20 ईंधन पर फैले असमंजस पर सवाल उठना लगभग तय है। सरकार मानकर चल रही है कि विपक्ष इन विषयों को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहेगा, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि आवश्यक विधेयकों को पारित कराया जाए। निस्संदेह सामान्य विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार के पास बहुमत है।

परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए सरकार के पास अभी दो-तिहाई बहुमत नहीं है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस और आप जैसे विपक्षी दलों में टूट के बाद जिस तरह कुछ अन्य दलों का रुख बदला है, उसने सरकार को संभावनाओं की राह दिखाई है। उल्लेखनीय है कि अब तक परिसीमन का खुलकर विरोधी करने वाला द्रमुक ने हाल में बयान दिया है कि वह कांग्रेस से दूर रहेगी और परिसीमन विधेयक को देखने के बाद उस पर निर्णय करेगी। विपक्षी गठबंधन में रहते हुए एनसीपी (एसपी) की नेता सुप्रिया सुले ने भी विधेयक देखने के बाद निर्णय की बात कहकर नरम रुख के संकेत दिए हैं। बताते हैं कि राजग बैठक में इस पर भी चर्चा हुई और कहा गया कि इन दलों का स्पष्ट रुख सामने आने के बाद इससे संबंधित रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नए प्रयोगों और भावनात्मक नामकरण के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में अब नया निर्णय सामने आया है। बताते हैं कि राजग ने संसदीय दल की बैठक का नाम अब 'मंगल मिलन' कर दिया है। इस नाम के साथ पहली बैठक 21 जुलाई को सुबह 9.30 बजे संसद भवन में होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी राजग सांसदों को संबोधित भी करेंगे।

कूनो नेशनल पार्क में चीतों को खिलाए गए भ्रष्टाचार के बकरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर

मटन खरीद में बकरों का वजन 70 से 90 किलो तक बताकर वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों के भोजन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शिकायत की गई है कि मटन खरीद में भ्रष्टाचार किया गया है। चीतों को खिलाने के लिए 70 से 90 किलो के बकरों की खरीद दर्शायी गई, जबकि आमतौर पर बकरों का वजन इतना नहीं होता। बता दें कि भारतीय वयस्क बकरों का औसत वजन 30 किलो से 65 किलो के बीच होता है।

मामले की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से की गई है। शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता मोहम्मद चीनी कुरैशी व दौलतराम गुप्ता ने कहा है कि चीतों के लिए बकरे के मीट के टेंडर 421 रुपये प्रति किग्रा में हुए हैं, जबकि उसकी खरीद 700 रुपये प्रति किलो तक बिना किसी टेंडर के की गई। जिस बकरे का वजन 20-30 किग्रा है, उसे कूनो प्रबंधन ने 70-90 किग्रा वजन के हिसाब से दर्शाया। यही नहीं पिछले दिनों वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने भी चीतों के मेडिकल रिकार्ड, ट्रैंक्युलाइजेशन और मटन खरीद से जुड़ी जानकारी के संबंध में आरटीआइ एक्ट के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय महत्व का विषय बताकर जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने प्रोजेक्ट के शुरुआती दो वर्ष में ही चीतों को 110 बार ट्रैंकुलाइज किए जाने पर भी सवाल उठाए थे।

2026 -27 के लिए डा. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय के 23 यूजी पाठ्यक्रमों की 1194 सीटों के लिए अब तक 14,758 पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं, स्नातकोत्तर (पीजी), पीएचडी और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आइटीईपी) में भी सीटों की तुलना में कई गुना अधिक आवेदन आए हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार, 18 जुलाई, 2026

आज का मौसम

शनिवार को बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान। 20 से 30 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
18 जुलाई	37.0	29.0
19 जुलाई	37.0	28.0
नोएडा		
18 जुलाई	38.0	28.0
19 जुलाई	37.0	28.0
गुरुग्राम		
18 जुलाई	37.0	29.0
19 जुलाई	35.0	28.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

किशोरी को छत से फेंकने के मामले में आरोपित गिरफ्तार

गाजियाबाद: कौशांबी थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पड़ोसी मुस्लिम किरायेदार द्वारा 15 वर्षीय किशोरी को चौथी मंजिल से धक्का देकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित शाहनवाज उर्फ शानू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ की धाराओं को हत्या की धाराओं में बदलाव कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद किशोरी के शव को शुक्रवार को स्वजन को सुपुर्द कर दिया गया। (जासं)

तहव्वुर की कूलर देने की मांग पर विचार करें जेल प्रशासन: कोर्ट

नई दिल्ली: पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआइए कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश के आरोपित तहव्वुर राणा की ओर से तिहाड़ जेल में कूलर उपलब्ध कराने की मांग पर जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया। राणा ने भीषण गर्मी और सेल में खराब स्वच्छता का हवाला देते हुए कोर्ट में आवेदन दिया था। (जासं)

शरजील की याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इन्कार के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। (जासं)

किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा फसल मुआवजा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले वर्ष अगस्त व सितंबर में हुई अधिक वर्षा और खेतों में जलभराव के कारण 4442.41 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए, दिल्ली सरकार ने करीब 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृति दी है। प्रभावित किसानों के बैंक खाते में मुआवजे की राशि भेजी जाएगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि के वितरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा कि सरकार दिल्ली के किसानों की हरसंभव सहायता को तैयार है। अधिक वर्षा के कारण किसानों को जो भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, यह सहायता राशि उनके घावों पर मरहम लगाने का एक प्रयास है। सीएम ने कहा कि सहायता राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो उस भूमि के पंजीकृत या मालिक हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शानदार रिकार्ड देख अनुराग को मिली अहम जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के जासूसी और सुरक्षा विशेषज्ञ (स्पाई चीफ) के रूप में उनके तीन दशक के शानदार ट्रैक रिकार्ड को देखते हुए सरकार ने उन्हें दिल्ली की कानून-व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अनुराग के आने से माना जा रहा है दिल्ली पुलिस की छवि अधिक पेशेवर बन सकेगी। शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुराग कुमार को कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल करीब पांच साल बाकी है। ऐसे में आयुक्त के पद पर उन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है।

अनुराग कुमार के पास पुलिसिंग और प्रशासन का करीब 32 साल का लंबा अनुभव है। अनुराग ईमानदार व स्वच्छ छवि के आइपीएस अधिकारी जाने जाते हैं। वह मूलरूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं। पिता इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। दिल्ली पुलिस में वह पहले सदर बाजार सबडिवीजन के एसीपी रहे। उसके बाद उत्तर-पूर्वी जिले में एडिशनल डीसीपी और फिर उत्तरी जिला के डीसीपी रहे हैं। इसके बाद लंबे समय के लिए वह प्रतिनियुक्ति पर आइबी में चले गए थे। वहां करीब 20 साल तक अलग-अलग पदों पर रहे।

आइबी में रहते हुए वह जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के मामले देख रहे थे। इन्हें आइबी में स्पेशल डायरेक्टर बनने के बाद कुछ साल के लिए विदेश भी भेजा गया था। अनुराग ने बीई की डिग्री हासिल की है। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2010 में 'सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक' और 2016 में 'विशिष्ट सेवा के लिए, राष्ट्रपति पुलिस पदक' से सम्मानित किया जा चुका है।

- आइबी में करीब 20 साल तक अलग-अलग पदों पर रहे अनुराग कुमार
- अनुराग कुमार ने बैचलर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है

पुलिस मुख्यालय में आयुक्त का पदभार ग्रहण करते अनुराग कुमार। सौजन्य: दिल्ली पुलिस

आज पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

देश की राजधानी की कमान संभालने के साथ ही अनुराग कुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। इसके सामने व मुख्य प्राथमिकताओं में राजधानी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, संगठित अपराध पर नकेल कसने, साइबर क्राइम से निपटने, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी तैयारियों को पुख्ता करने और वीआइपी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। दिल्ली के हर जिले में खुले साइबर थानों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पनपने की शिकायतें मिलती रही हैं। आयुक्त को साइबर थानों के हालात को ठीक करना होगा। पदभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को आयुक्त अनुराग कुमार ने सभी विशेष आयुक्तों के साथ मुलाकात की और उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर संक्षिप्त चर्चा की। शनिवार को उन्होंने दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ पहली बैठक बुलाई है जिसमें सभी विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल रहेंगे।

पद से हटाए जाने की जानकारी इंटरनेट मीडिया से मिली

प्रथम पृष्ठ से आगे

पौधारोपण के बाद जब गोलछा पुलिस मुख्यालय के लिए रवाना हुए तब रास्ते में उनकी नजर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे गृह मंत्रालय के एक आर्डर पर पड़ी, जिसमें उन्हें पद से हटाने और अनुराग कुमार को नया आयुक्त बनाने की बात कहा गई थी।

पद से हटाने का आदेश देखकर आयुक्त समेत सभी अधिकारी पहले उसकी सत्यता के बारे में इधर-उधर फोन घुमाकर पता करने लगे। इसी बीच गोलछा पुलिस मुख्यालय में अपने कार्यालय में पहुंचे। कुछ ही देर में उन्हें आधिकारिक रूप से जानकारी दे दी गई और अनुराग कुमार को चार्ज देने का निर्देश मिला। आयुक्त को इतना भी समय नहीं मिला कि वह किसी अधिकारी से किसी मसले पर आखिरी बार बातचीत कर सकें। डेढ़ घंटे के अंदर 11:45 बजे अनुराग कुमार बिना किसी सुरक्षाकर्मी के अपनी निजी होंडा सिटी कार से मुख्यालय पहुंच गए। उनकी कार में कोई स्टार या आइबी का स्टिकर नहीं लगा था। नए आयुक्त के मुख्यालय पहुंचने की सूचना मिलने पर तमाम अधिकारी तुरंत नीचे पोर्च में पहुंच चुके थे। उनसे हाथ मिलाने के तुरंत बाद अनुराग कुमार 17वीं मंजिल पर पहुंच गए और कार्यभार ग्रहण कर लिया।

गोलछा को एजीएमयूटी भेजा: आदेश में गोलछा (1992 बैच) को एजीएमयूटी कैडर में भेजने को कहा गया है। उन्हें पिछले साल 22 अगस्त को पुलिस आयुक्त बनाया गया था। वह 11 माह तक आयुक्त रहे। सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2027 को होनी है।

'अगर आप ड्यूटी नहीं निभाते, तो डाक्टर कहलाने का हक नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ▶ दुष्कर्म व हत्या के मामले में डाक्टरों को लगाई फटकार

इलाज नहीं करने वाले दोनों अस्पतालों को निर्देश, पीड़ित परिवार को दें मुआवजा

प्रतीकात्मक

- निजी अस्पतालों ने बच्ची को भर्ती करने से कर दिया था मना
- गाजियाबाद पुलिस की "अनिच्छा" पर शीर्ष कोर्ट ने सवाल उठाए

नई दिल्ली, प्रेट्र: गाजियाबाद में दुष्कर्म की शिकार चार वर्षीय बच्ची को चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराने वाले दो निजी अस्पतालों और उनके डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते, तो आपको डाक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इलाज नहीं मिलने से बच्ची की मौत हो गई थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अस्पतालों से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश ने डाक्टरों से कहा, "अगर आपमें संवेदनशीलता होती, तो आपके यहां सुविधा नहीं होने पर भी आप बच्ची को दूसरे अस्पताल ले जाते... आपने उसकी अनदेखी की क्योंकि वह गरीब थी? वह आपकी फीस नहीं दे सकती थी?" अगले हफ्ते इस मामले की फिर सुनवाई होगी।

इस साल 16 मार्च को बच्ची को चाकलेट दिलाने के बहाने एक पड़ोसी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता ने उसे ढूंढा और उसे बेहोश व खून से लथपथ पाया। परिवार उसे दो निजी अस्पतालों में ले गया, जहां उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। फिर उसे गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस मामले में एफआइआर दर्ज करने और जांच करने में गाजियाबाद पुलिस की "अनिच्छा" पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इलाज से इन्कार करने वाले दोनों निजी अस्पतालों (खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ मरियम अस्पताल) को भी उन पर लगे आरोपों के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। पीठ बच्ची के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं। याचिका में मांग की गई थी कि मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआइटी) या सीबीआइ से कराई जाए। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित पुलिस थाने के एसएचओ, दोनों अस्पतालों और एडीशनल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए थे। माना जा रहा है कि इसके जरिये सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टरों को सख्त चेतावनी दी है।

आइटीओ पर ही बनेगा दिल्ली सरकार का ट्विन टावर सचिवालय

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

- जारी होगा ग्लोबल टेंडर, एक छत के नीचे आएंगे सरकार के सभी विभाग
- आयकर भवन की 4.5 एकड़ जमीन से परियोजना को मिलेगा विस्तार

30 से 35 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग को स्काइवाक से जोड़े जाने की भी योजना

दिल्ली सरकार का ट्विन टावर सचिवालय आइटीओ पर ही बनेगा बनेगा। सरकार आइटीओ पर प्रस्तावित नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए जल्द ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ट्विन टावर सचिवालय परियोजना का उद्देश्य राजधानी के अलग-अलग स्थानों पर चल रहे सरकारी विभागों को एक ही परिसर में लाना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना के लिए आइटीओ पर लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के अलावा सड़क के पार कर सामने के हिस्से में पुराने आयकर भवन की लगभग 4.5 एकड़ भूमि भी परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके एवज में आयकर विभाग को नए सचिवालय परिसर में करीब 10 लाख वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र दिया जाएगा, जहां वह कार्यालय संचालित करेगा।

वर्तमान में मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सचिवालय की विभिन्न मंजिलों से कामकाज कर रहे हैं, जबकि कई विभाग राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। प्रस्तावित नया सचिवालय इस व्यवस्था को बदल देगा। पीडब्ल्यूडी भवन, विकास भवन और आयकर विभाग की उपलब्ध भूमि को मिलाकर 30 से 35 मंजिला आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग विकसित की जाएगी। विकास मार्ग के दोनों ओर स्थित भवनों को स्काईवाक से जोड़ा जाएगा। परिसर में पर्याप्त पार्किंग, अत्याधुनिक कान्फ्रेंस और सेमिनार हाल सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

आइटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय। जागरण

विभिन्न विकल्पों पर विचार के बाद आइटीओ को इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। निर्माण कार्य के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा, ताकि देश-विदेश की प्रमुख निर्माण कंपनियां अपनी आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता के साथ इसमें भाग ले सकें। **-प्रवेश वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री**

अल फलाह चेयरमैन की अंतरिम जमानत खारिज, सशर्त कस्टडी पैरोल मिली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: लाल किला के सामने हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। हालांकि, अदालत ने जवाद को 21, 23 और 25 जुलाई को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक के लिए कस्टडी पैरोल पर पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि वह अपनी पत्नी के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे। अंतरिम जमानत की मांग को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि रिकार्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पेश किया गया कि याची की पत्नी की तबियत बिगड़ सकती है या कोई आपातकालीन स्थिति जैसी बात है, बल्कि स्वास्थ्य सुधार रहा है।

पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत के पर सिद्दीकी के भागने का खतरा हो सकता है और रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यह कोर्ट याचिकाकर्ता की पत्नी की मेडिकल स्थिति के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों की गंभीरता, प्रकृति, कार्यवाही की स्थिति, उन्हें सौंपी गई भूमिका और उनके ओहदे को देखते हुए जमानत देने से जुड़े नियमों को केवल मानवीय आधार पर कम नहीं किया जा सकता।

एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा में लदी सरिया पीछे कार में घुसी, चालक की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- एवीएल सोसाइटी के पास नो एंट्री में घुसे ई-रिक्शा से तेज रफ्तार में आई टैक्सी कार भिड़ गई

द्वारका एक्सप्रेसवे पर एवीएल सोसाइटी के पास हादसे के बाद गाड़ी में घुसा सरिया। जागरण

द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दोपहर दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा हो गया। सेक्टर-37 थाना क्षेत्र की एवीएल सोसाइटी के पास नो एंट्री में घुसे सरिया लदे ई-रिक्शा से पीछे से तेज रफ्तार में आई टैक्सी कार उससे भिड़ गई। टक्कर से ई-रिक्शा पर लदी सरिया कार के अंदर घुस गई और चालक की गर्दन तोड़ते हुए पिछले हिस्से से पार हो गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, सफेद रंग की ह्युंडई औरा कार शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम की तरफ से दिल्ली की तरफ मेन कैरेजवे पर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब कार ओवरटेक करने वाली लेन से गुजर रही थी, तभी उसकी टक्कर सरिया लदे ई-रिक्शा से हो गई। ई-रिक्शा पर पिछले हिस्से में निकली करीब 10 फीट लोहे की सरिया गाड़ी की विंड शील्ड को तोड़कर अंदर घुस गई और चालक के गले पर लगकर पीछे वाला शीशा तोड़कर बाहर निकल गई। हादसे में चालक की गर्दन टूट गई। कार में पिछली सीट पर बैठी महिला सदमे में आ गई और बेहोश हो गई। उसे एंबुलेंस से निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने मृत चालक की पहचान मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के मोहम्मदपुर नवादा गांव निवासी 30 वर्षीय शिवेंद्र कुमार के रूप में की है। वह गुरुग्राम के खांडसा गांव में किराये से रहते थे और ओला उबर में टैक्सी चलाते थे।

बदला लेने के लिए दुष्कर्म के बाद की थी यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या, चार्जशीट में बर्बरता की कहानी

कैलाश हिल्स दुष्कर्म व हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- टेबल लैंप से हमला कर तोड़ी थी नाक की हड्डी, हाथ-पैरों को नोंचा, केबल से घोंटगला

973 पन्नों की चार्जशीट में 82 गवाहों के बयान, मामले में आज साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई

आरोपित राहुल मीणा। फाइल

अमर कालोनी थाना क्षेत्र स्थित कैलाश हिल्स में आइआरएस अधिकारी की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में 86 दिन बाद पुलिस ने आरोपित राहुल मीणा के खिलाफ 973 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। घर के बाहर छिपाकर रखी एक अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल करके घुसे आरोपित ने टेबल लैंप से हमला कर युवती की नाक तोड़ दी थी। हाथ-पैरों को अनगिनत बार नोंचा। इतने से भी मन न भरा तो मोबाइल चार्जर के केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी।

आरोपित आइआरएस अधिकारी का पूर्व घरेलू सहायक था, जिसे फरवरी में ही गलत व्यवहार और वित्तीय हेराफेरी के कारण निकाल दिया गया था। हालांकि, तब पुलिस ने बदला लेने वाली थ्योरी से इनकार कर दिया था। जबकि दैनिक जागरण ने घटना के समय ही नौकरी से निकाले जाने की बात को यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ हुई हैवानियत की वजह बताई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब चार्जशीट में भी इसकी पुष्टि हुई है। आरोपित बदला लेने के लिए ही अलवर से कैलाश हिल्स आया था।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही आइआइटी स्नातक पीड़िता को 22 अप्रैल की सुबह जिम से घर लौटने के बाद उसके माता-पिता ने कैलाश हिल्स स्थित आवास में मृत पाया था। आरोपित ने दुष्कर्म व हत्या के बाद घर से सात लाख की नकदी चुराई, पीड़िता के भाई के कपड़े पहने और फरार हो गया था।

घरेलू सहायक, ड्राइवर व सुरक्षा कर्मियों के लिए बयान

जांच टीम के मुताबिक आरोपित सुबह 6:39 बजे घर में घुसा था और सीसीटीवी कैमरों में सुबह 7:20 बजे वह घर के सामने वाली सड़क पर कंधे पर बैग लटकाए आराम से जाता हुआ कैद हुआ। एक सुरक्षा गार्ड व एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है, पर वह गोलमोल जवाब देकर वहां से चला गया। इन दोनों को मामले में गवाह के रूप में दर्ज किया गया है। टीम ने पड़ोसी, सुरक्षा कर्मी, घरेलू सहायक, श्रमिक, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, आटो-रिक्शा ड्राइवर, ड्राइवर व प्रमुख सीन के पास मौजूद अन्य लोग के बयान लिए हैं।

सीट आवंटन के बाद कालेजों में बढ़ी हलचल, हेल्पडेस्क पर पहुंच रहे विद्यार्थी

डीयू दाखिला

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

18 जुलाई तक पूरी होनी है पहली सूची पर दाखिला प्रक्रिया

- कालेजों में आनलाइन के साथ आफलाइन हेल्पडेस्क सक्रिय

डीयू की पहली सीट आवंटन सूची जारी होने के बाद शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के कालेज परिसरों में हलचल शुरू हो गई। सुबह से ही छात्र-छात्राएं अभिभावकों के साथ कालेज पहुंचने लगे। किसी को यह जानना था कि सीट स्वीकार करने के बाद अगला कदम क्या होगा, तो कोई दस्तावेज सत्यापन, फीस जमा करने और विषय चयन को लेकर जानकारी लेने आया। सूची जारी होने के बाद कालेजों में आफलाइन हेल्पडेस्क भी शुरू कर दिए गए हैं, जहां दिनभर आवाजाही बनी रही।

कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आनलाइन हेल्पडेस्क और काउंसलिंग नंबर पहले ही सक्रिय थे। जो छात्र कालेज आकर जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए आफलाइन हेल्पडेस्क भी शुरू हो चुके हैं, जहां दाखिला कमेटी के सदस्य और छात्र स्वयंसेवक नए विद्यार्थियों और अभिभावकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए जाते छात्राएं। चंद्र प्रकाश मिश्र

दाखिला प्रक्रिया, तकनीकी दिक्कतों और फीस भुगतान आदि के अलावा हेल्पडेस्क पर कालेज शुरू होने, ओरिएंटेशन कार्यक्रम, छात्रावास, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कालेज प्रशासन का कहना है कि कई बार आनलाइन प्रक्रिया को लेकर विद्यार्थी और अभिभावक दुविधा में रहते हैं। उन्हें शंका का समाधान करने के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं।

'गैर जिम्मेदार पत्रकारिता को नहीं बना सकते हैं ढाल'

सख्त टिप्पणी

प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए नियम बनाने की जरूरत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया जोर, दो आरोपितों को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म के तेजी से बढ़ने के कारण मीडिया के एक बड़े हिस्से के अनियमित और असंगठित होने पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेस की आजादी पर सख्त टिप्पणी की है।

न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि प्रेस की आजादी का इस्तेमाल गैर जिम्मेदार पत्रकारिता या ऐसी सामग्री फैलाने के लिए ढाल के तौर पर नहीं किया जा सकता, जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करे। प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए ऐसे नियम बनाने की जरूरत है, जो जवाबदेही, कानून का सम्मान और नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखें। पीठ ने कहा कि मीडिया को यह समझना चाहिए कि जनमत बनाने की उसकी ताकत के साथ संयम, निष्पक्षता और जिम्मेदारी बरतने का कर्तव्य भी जुड़ा होता है।

पीठ ने कहा कि हाथ में मोबाइल व माइक लेकर खुद को रिपोर्टर बताने वाले लोगों का आक्रामक तरीके से नागरिकों के सामने माइक्रोफोन लगाकर तुरंत जवाब मांगना और फिर उनके चुप रहने पर इसे सवालों से बचना कहना आम बात हो गई है। अदालत ने यह टिप्पणी दो आरोपितों आबिद अली और फुरकान को जमानत देते हुए की। आरोपितों पर जुलाई-2025 में सीमापुरी की एक अनधिकृत कालोनी में यूट्यूब चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रहे दो फ्रीलांसरों के साथ मारपीट करने का आरोप है। पीठ ने कहा कि चुनिंदा रिपोर्टिंग, सनसनीखेज खबरें या बिना पुष्टि किए आरोप लगाकर समाज को बदनाम करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही चिंताजनक है। ऐसे व्यवहार से सामाजिक विभाजन हो सकता है और सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि विधायिका एक उपयुक्त नियामक ढांचा बनाने पर विचार करे, जो प्रेस की आजादी को बनाए रखते हुए, पेशेवर जवाबदेही व नैतिक मानकों के साथ जनहित का सम्मान सुनिश्चित करे। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसका साथी इलाके में पूजा-स्थल से जुड़ा एक वीडियो रिकार्ड कर रहे थे। इस बात से स्थानीय लोग नाराज हो गए थे। यह घटना लोगों के गुस्से का नतीजा थी। इसमें वर्तमान आरोपितों की भूमिका स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आरोपितों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

थर्ड-पार्टी आडिटर देंगे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इमारतों और परिसरों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (एफएसए) जारी करने वाले थर्ड-पार्टी फायर सेफ्टी आडिटर्स के पंजीकरण और पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने आवेदन मांगते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हाल के महीनों में राजधानी में हुई कई बड़े अग्निकांड विशेषकर हौज रानी स्थित होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत के बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। पिछले महीने अधिसूचित डीएफएस संशोधन नियम-2025 के तहत अब योग्य और अनुभवी फायर सेफ्टी आडिटर्स को अधिकृत किया जाएगा।

डूसू चुनाव में प्रिंटेड पोस्टर-बैनर पर रोक, नियम तोड़ने पर रद होगा नामांकन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एमसीडी के विज्ञापन बोर्डों पर भी नहीं किया जा सकेगा किसी प्रकार का चुनावी प्रचार

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को निष्पक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रचार-प्रसार को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्राक्टर कार्यालय में डूसू पदाधिकारियों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में चुनाव प्रचार के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे।

प्राक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान कैंपस और उसके आसपास किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वाल आफ डेमोक्रेसी पर हाथ से बनाए गए पोस्टर ही लगाए जा सकेंगे। दीवारों पर ब्लाक प्रिंटिंग, स्प्रे पेंटिंग या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि एमसीडी के विज्ञापन बोर्डों पर भी किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एमसीडी आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

हाइड्रोजन ट्रेनः स्वदेशी तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बनाते हैं इसे खास

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से जींद-सोनीपत मार्ग पर चलने वाली इस देश की पहली पर्यावरण-अनुकूल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही भारत हाड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका। यह ट्रेन आखिर इतनी खास क्यों है आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन

दुनिया भर में जो हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं, वे आमतौर पर दो से चार डिब्बों की होती हैं। लेकिन भारत की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 डिब्बों की है, जिसमें लगभग 2,600 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। यह इसे सबसे लंबी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेनों में से एक बनाती है।

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक

इसे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) और अन्य भारतीय संगठनों ने मिलकर पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और तैयार किया है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है।

देश का सबसे बड़ा रिफ्यूलिंग स्टेशन

ट्रेन को लगातार ईंधन मिलता रहे, इसके लिए हरियाणा के जींद में देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। यहां एक बार में 3,000 किलो हाइड्रोजन सुरक्षित स्टोर की जा सकती है।

जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद

भारत इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया के उन गिने-चुने चार-पांच देशों में शामिल हो गया है, जो हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। यह न केवल भारत के नेट-जीरो यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन पहाड़ी और ऐतिहासिक रूटों के लिए भी वरदान साबित होगी, जहां बिजली के खंभे और तार लगाना मुश्किल काम है।

सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम

हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए भारतीय रेलवे ने इसकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी हैः

मल्टी-लेयर सेंसर: ट्रेन और रिफ्यूलिंग प्लांट में अत्यधिक संवेदनशील हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, स्मोक और हीट डिटेक्टर्स लगाए गए हैं।

आटोमैटिक कट-आफ: अगर कहीं भी गैस का जरा सा भी रिसाव महसूस होता है, तो सिस्टम बिना किसी इंसानी मदद के तुरंत हाइड्रोजन की सप्लाई को खुद-ब-खुद बंद कर देता है।

लगातार वेंटिलेशन: ट्रेन में हवा का बहाव लगातार बनाए रखने की व्यवस्था है ताकि यदि बहुत मामूली रिसाव हो भी, तो वह गैस हवा में मिलकर तुरंत उड़ जाए और किसी दुर्घटना का कारण न बने।

ट्रेन इसलिए है खास

यह ट्रेन केवल पर्यावरण के अनुकूल ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर के रेल नेटवर्क में अपनी विशेष पहचान रखती है।

बेहद शक्तिशाली इंजन

ट्रेन में 3,200 हार्सपावर (एचपी) का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। डिजाइन स्पीड 110 किमी/घंटा है। फिलहाल 75 किमी2/घंटा की स्पीड चे चलाया गया।

नहीं होता है कोई प्रदूषण

इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। फ्यूल सेल में रासायनिक प्रक्रिया के बाद उप-उत्पाद के रूप में केवल भाप और गर्मी निकलती है।

ऐसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन

हाइड्रोजन से बिजली बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया और हाइड्रोजन का स्टोरेज-

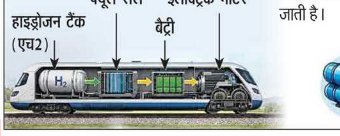

हाइड्रोजन स्टोरेज: सबसे पहले हाइड्रोजन भारी दबाव के साथ (350 बार) पर विशेष टैक में भरी जाती है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल: इसके बाद हाइड्रोजन विशेष टैंक से फ्यूल सेल को भेजी जाती है।

रासायनिक प्रतिक्रिया: फ्यूल सेल में हाइड्रोजन हवा में मौजूद आक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है। इससे बिजली और पानी बनता है।

बनती है बिजली: फ्यूल सेल में प्रतिक्रिया बिजली पैदा करती है। इसी बिजली से ट्रेन चलती है।

बैट्री में स्टोर होती है बिजली: पैदा होने वाली बिजली का एक हिस्सा बैट्री में स्टोर होता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।

चलती है इलेक्ट्रिक मोटर: फ्यूल सेल और बैट्री से मिलने वाली बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है।

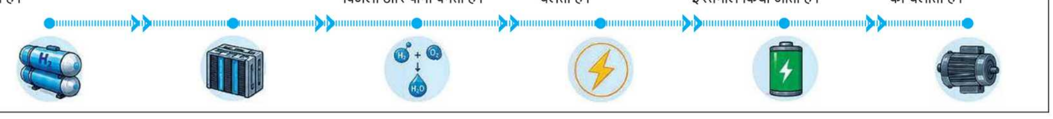

जागरण रिसर्च

'कट्टर ईमानदार' ही हैं 'कट्टर बेईमान' : मोदी

पीएम ने जालंधर से 5,470 करोड़ की रेल व सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया

जालंधर छावनी व देश के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन

- छेहर्टा से चलने वाली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
- पीएम के पंजाब दौरे के दौरान राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा कार्यक्रम में

दिनेश कुमार • जागरण

जालंधर: पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को पंजाब दौरे पर सख्त तेवर में दिखे। जालंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा, पार्टी के जो नेता खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, असल में वे कट्टर बेईमान हैं। बढ़ते अपराध, नशे और गैंगस्टरवाद पर नकेल कसने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। कहा, प्रदेश में अब बदलाव की जरूरत है, जो सिर्फ भाजपा ही ला सकती है। ज्ञात हो, प्रधानमंत्री के पंजाब के दौरे के दौरान राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि न तो उनका स्वागत करने पहुंचा और न ही कोई कार्यक्रम में शामिल हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर छावनी में 5,470 करोड़ रुपये की लागत वाली रेल व सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके बाद पंजाब के इतिहास का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि एक समय था जब शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के शासन में पंजाब में खुशहाली, सुरक्षा और सद्भाव था, लेकिन आज यहां कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कब, कहां, किस दिशा से गोली चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कारोबारियों से आए दिन रंगदारी मांगी जा रही है, जिससे यहां व्यापार-कारोबार करना मुश्किल हो गया है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं और पंजाब के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में दंगों के मामले में कट्टर बेईमान पार्टी के एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया, लेकिन वे सुबूतों के आधार पर दिए फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों पर हमले के मामले में गुजरात में भी इनके विधायक को सजा सुनाई गई है। पंजाब में जिसे मंत्री बनाया, उसे भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लांड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं और एक विधायक रिश्वत लेता पकड़ा गया। पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, फिर भी पंजाबियों तक हर योजना पहुंचाने का प्रयास रहता है, लेकिन यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। 12 वर्ष में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपये भेजे गए, लेकिन उन्हें सही जगह खर्च नहीं किया गया। पंजाब के नाम पर कर्ज लेकर सरकार चला रहे लोग उस पैसे पर मौज कर रहे हैं और बजट ब्याज चुकाने में लग रहा है। पंजाब सरकार केंद्र की योजनाओं पर अपना लेबल लगाकर प्रचार कर रही है।

जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते। विजय शर्मा

हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी, यहां सिर्फ धोखा

कृषि प्रधान प्रदेश, जहां 70 से 80 % आबादी खेती पर निर्भर है, के किसानों के प्रति सम्मान को दर्शाते हुए हरे रंग की पगड़ी पहनकर मंच पर आए मोदी ने कहा,यहां के किसानों व नौजवानों में बहुत क्षमता है। दोनों मिलकर पंजाब का तेजी से विकास कर सकते हैं, पर इसके लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। पड़ोस में हरियाणा है, जहां 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है, जबकि पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा मिल रहा है।

'चंडीगढ़ पीजीआइ में खुलेगा एमबीबीएस कालेज'

पीजीआइ चंडीगढ़ में एमबीबीएस कालेज खोला जाएगा। जल्द ही इसकी कक्षाएं शुरू होंगी एमडी, एमएस डिग्री कर विशेषज्ञ डाक्टरों संग एमबीबीएस से जूनियर डाक्टर भी पीजीआइ देगा। यह घोषणा मोदी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कालेज में आयोजित कार्यक्रम में 4700 करोड़ रुपये की नौ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के दौरान की। उन्होंने रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर यह परियोजनाएं जनता को समर्पित की।

मंच पर पीएम से मनीष तिवारी की नजदीकी, दोनों के बीच चर्चा ने छेड़ी नई बहस

बलवान करिवाल • जागरण

- पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर हाईकमान से नाराजगी जता चुके हैं सांसद मनीष तिवारी
- प्रधानमंत्री भाषण खत्म कर जाने से पहले मनीष तिवारी से मिले, हाथ मिला पूछा हाल

चंडीगढ़: पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को पंजाब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। समारोह में स्टेज पर मात्र पांच ही कुर्सियां लगाई गई थीं, जिसमें से एक पर चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बैठे थे। समारोह में पीएम से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मनीष तिवारी को पूरा महत्व दिया। मोदी ने तो यहां तक कहा 'लोक सभा में हमारे साथी मनीष तिवारी'। समारोह खत्म होने के बाद पीएम खुद मनीष तिवारी के पास रुके। उनसे हाथ मिलाया। कुछ समय तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद से ही तिवारी के भाजपा के साथ मधुर संबंधों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। चर्चा इसलिए भी क्योंकि पहले कई कार्यक्रमों से तिवारी ने दूरी बनाए रखी थी। फिर चाहे तीन कानूनों की शुरुआत का कार्यक्रम हो या 24 घंटे पानी की परियोजना।

यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिन पहले ही पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंतर्कलह व पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष बनाने की बजाए कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने व पंजाब कांग्रेस में तवज्जों नहीं दिए जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी नाराजगी दिखा चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, 'काबिल होना ही अपने आप में एक बड़ी कमी है। काश मेरे पास लोगों व संस्थाओं की असुरक्षा की भावना दूर करने का कोई तरीका होता। कांग्रेस ने गत 45 वर्षों में मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने भी पूरी जवानी पार्टी की सेवा में समर्पित कर दी। किस्मत को कौन टाल सकता है। जो होना है, वह तो होकर रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंच से जाते समय कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से मिलते हुए।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के अनुरोध की कर रहे समीक्षा: भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत ने शुक्रवार को कहा कि ढाका की ओर से बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए किए गए अनुरोध की अभी समीक्षा की जा रही है। ज्ञात हो, हिंसक छात्र आंदोलन के चलते पांच अगस्त, 2024 को हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार अपदस्थ हो गई थी। वह तभी से भारत में हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिसमें कहा गया है कि हसीना अवामी लीग को पुनर्जीवित करने के लिए बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। जायसवाल ने कहा, "हमें प्रत्यर्पण के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अनुरोध की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इसमें कानूनी पहलू शामिल हैं।" गत सप्ताह 78 वर्षीय हसीना के करीबी सूत्रों ने बताया था कि पूर्व पीएम स्वेच्छा से स्वदेश लौटने की योजना बना रही हैं ताकि वह अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर सकें। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवंबर में ढाका के एक विशेष न्यायालय ने हसीना को उनकी अनुपस्थिति में कथित मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ढाका नई दिल्ली से उन्हें प्रत्यर्पित करने का आग्रह कर रहा है।

भारत की हाई स्पीड ट्रेन से शुरू होगा बुलेट ट्रेन का पहला सफर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विदेश मंत्रालय ने कहा-2027 में शुरू होगा पहले खंड का परिचालन
- जापान की ई-10 सीरीज ट्रेनें 2030 के शुरुआत में उपलब्ध होंगी

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले चरण में जापान की अगली पीढ़ी की ई-10 शिंकानसेन ट्रेन का इंतजार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 में परियोजना के पहले खंड का परिचालन भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से शुरू होगा। जापान की ई-10 सीरीज ट्रेनें 2030 के शुरुआत में उपलब्ध होंगी, क्योंकि उनका विकास व परीक्षण जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच पहला परिचालन खंड 15 अगस्त 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इसके बाद शेष हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा।

दरअसल, जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने इंटरनेट मीडिया पर परियोजना में देरी को लेकर भारतीय पक्ष पर सवाल उठाए थे। विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा, वह वास्तविक तथ्यों से काफी अलग है। दोनों देश इस परियोजना पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और काम तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। भारत- जापान के बीच परियोजना को लेकर वार्ता सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रही है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड 2027 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसी कारण दोनों देशों ने आपसी सहमति बनाई है कि परियोजना की शुरुआत भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से की जाए, ताकि बुलेट ट्रेन सेवा समय पर शुरू हो सके। बाद में ई-10 सीरीज ट्रेनें उपलब्ध होने पर उन्हें इस कोरिडोर में शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सिग्नलिंग व अन्य तकनीकी उपकरणों की खरीद इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की गई है। इस संबंध में जापान की ओर से कोई अलग प्रस्ताव नहीं मिला था। परियोजना का क्रियान्वयन दोनों देशों के साझा लक्ष्य, यानी बुलेट ट्रेन सेवा जल्द शुरू करने, के अनुरूप आगे बढ़ रहा है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत शुक्रवार को जारी निर्माण कार्य का हवाई दृश्य। एएनआइ

राष्ट्रपति मुर्मु मोल्दोवा, नार्थ मैसेडोनिया और रोमानिया का करेंगी दौरा

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, नार्थ मैसेडोनिया, रोमानिया की राजकीय यात्रा करेंगी। यात्रा का मकसद इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुर्मु की इन तीन देशों की यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज ने कहा, "इन तीन देशों की यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा व नार्थ मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।" साथ ही, मुर्मु की रोमानिया यात्रा तीन दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछली यात्रा 1994 में हुई थी। उन्होंने कहा कि इन तीन देशों की यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाती है और इस क्षेत्र के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

30 दिन तक जेल में होने पर सीएम, पीएम को हटाने पर गठित जेपीसी ने टाली रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रिया और ओवैसी ने की थी रिपोर्ट में असहमति दर्ज करने की मांग
- समिति अध्यक्ष ने और अधिक विचार-विमर्श की जरूरत बताई

किसी भी आरोप में 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में 31वें दिन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के स्वतः पदमुक्त होने के प्रविधान वाले विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अंतिम समय में अपनी रिपोर्ट टाल दी है। अंतिम रिपोर्ट पर मुहर लगाने के लिए शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में और अधिक विमर्श कर सहमति बनाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने जेपीसी का बहिष्कार कर रखा है, पर राकांपा (शरद पवार) की सुप्रिया सुले और एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी इसमें शामिल हैं।

पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध को देखते हुए विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी विधेयक में कुछ संशोधनों के साथ रिपोर्ट तैयार करने में जुटी थी। इन संशोधनों का मसौदा सदस्यों को भेज दिया गया था और शुक्रवार को इन पर मुहर लगने की उम्मीद थी पर बैठक में सुप्रिया सुले और ओवैसी ने अपनी असहमति को इसका हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इसे देखते हुए समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने और विमर्श की जरूरत बताते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया रोक दी।

अपराजिता सारंगी। फाइल

समिति का सुझाव-हटाने के बजाय निलंबित किया जाएः समिति की रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया था कि यदि पीएम,केंद्रीय मंत्री व सीएम गंभीर अपराधों के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाने के बजाय कानूनी कार्यवाही के नतीजे तक निलंबित किया जाए। यदि ऐसे व्यक्ति बरी हो जाते हैं या तय अवधि के भीतर अभियोजन आगे नहीं बढ़ता है, तो पद पर स्वतः बहाली का प्रविधान हो।

मानसून सत्र में विधेयक पेश होने की उम्मीद कम : माना जा रहा था कि जेपीसी की रिपोर्ट आने पर सरकार इसे इसी मानसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पास कराने के लिए भी लोस व रास में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती। सरकार की प्राथमिकता में वैसे भी महिला आरक्षण व परिसीमन बिल है, जिसके लिए विपक्षी सदस्यों की जरूरत पड़ सकती है। जेपीसी के नए फैसले के बाद विधेयक के मानसून सत्र में पेश होने की उम्मीद कम हो गई है।

नई व्यवस्था

अब देश की जनता भी करेगी सरकारी कार्यों की निगरानी

जी-रामजी योजना में जनता सूचना बोर्ड और सोशल आडिट से बढ़ेगी जवाबदेही, हर कार्यस्थल पर लगाया जाएगा यह बोर्ड, परियोजना संबंधी सभी जानकारी होगी

अरविंद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली: मनरेगा में फर्जी कार्यों, कागजी प्रगति और भुगतान में तमाम गड़बड़ियों पर नियंत्रण के लिए विकसित भारत जी-रामजी योजना में निगरानी व्यवस्था को अभेद्य बनाया गया है। निगरानी का जिम्मा अब सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास ही नहीं होगा, बल्कि गांव के लोग भी सीधी नजर रख सकेंगे। काम और हिसाब-किताब में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए तीन स्तर पर निगरानी व्यवस्था की गई है।

सरकार के साथ-साथ जनभागीदारी को भी पहले से ज्यादा तत्पर किया गया है। हर कार्यस्थल पर जनता सूचना बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर योजना की लागत, स्वीकृत राशि, कार्य दिवस-अवधि और अन्य जरूरी सूचनाएं सार्वजनिक होंगी। सोशल आडिट और डिजिटल रिकार्ड के आधार पर ग्रामीण स्वयं भी जांच सकेंगे कि काम सही तरीके से हो रहा या नहीं। पैसों की लूट तो नहीं हो रही।

प्रतीकात्मक

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जनता सूचना बोर्ड है। काम की जानकारी सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। बोर्ड पर साफ-साफ लिखा होगा कि अमुक परियोजना पर कुल कितना खर्च होना है, शासन से परियोजना के लिए कुल कितनी राशि मंजूर हुई है, काम कब शुरू हुआ और कब पूरा होना है। साथ ही कितने मजदूरों ने काम किया और कुल कितने मानव-दिवस भी बताना पड़ेगा। इससे ग्रामीणों को जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर बोर्ड पर सौ मजदूरों के काम करने का उल्लेख है, लेकिन गांव के लोगों को पता है कि वास्तव में इतने मजदूर काम पर नहीं आए हैं तो वे तुरंत सवाल उठा सकेंगे। इसी तरह अगर किसी परियोजना को कागजों में पूरा दिखा दिया गया है, जबकि जमीन पर काम अधूरा है तो उसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी।

सोशल आडिट की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी, लेकिन इस बार उसे प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल रिकार्ड भी जोड़ा गया है। सोशल आडिट का मतलब है कि ग्रामसभा, ग्रामीण एवं स्वतंत्र सोशल आडिट टीम मिलकर जांच करेंगे कि स्वीकृत कार्य वास्तव में हुआ या नहीं। मजदूरी सही लोगों को मिली या नहीं और खर्च का रिकार्ड वास्तविक स्थिति से मेल खाता है या नहीं।

पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन कई बार रिकार्ड की जांच में समय लगता था। अब उपस्थिति, भुगतान और कार्य प्रगति का डिजिटल रिकार्ड होने से मिलान करना आसान होगा। अगर किसी मजदूर के नाम पर भुगतान दिखाया गया है या किसी कार्य को पूरा बताया गया है तो उसकी पुष्टि रिकार्ड और मौके की वास्तविक स्थिति से जल्दी की जा सकेगी। इससे गड़बड़ियों का पता लगाने में कम समय लगेगा।

फर्जी भुगतान, गलत मस्टर रोल या अधूरे कार्यों जैसी शिकायतों की जांच अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगी। अगर नई व्यवस्था गंभीरता से लागू की जाती है और सूचना बोर्ड नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं तो विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ सकती है। फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम होगी और धन का उपयोग सार्थक तरीके से हो पाएगा।

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

403 सीटों पर उप्र का विधानसभा चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)। बिहार के हाजीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण शनिवार, 18 जुलाई, 2026

राजनीतिक दलों की बिसात पर 'राम', इंटरनेट मीडिया पर छिड़ा महासंग्राम

चढ़ावा चोरी प्रकरण के सहारे भाजपा के हिंदुत्व की धार कमजोर करने में जुटी सपा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

अखिलेश यादव

योगी आदित्यनाथ। फाइल

अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभु श्रीराम और उनके मंदिर का मुद्दा राजनीतिक दलों की रणनीतियों के केंद्र में आ गया है। चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उनकी कोशिश हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को कमजोर करने की है, जिसके सहारे वह पिछले एक दशक से चुनावी लाभ हासिल करती रही है। वहीं, भाजपा एक रणनीति के तहत सपा पर उसके ही इतिहास के सहारे पलटवार कर रही है। भाजपा नेता कारसेवकों पर गोली चलवाने जैसे मामले याद दिला रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल के पुराने वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें मंदिर आंदोलन के दौरान सपा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख है। चढ़ावे मामले में भाजपा को घेरने वाले गीत, वीडियो, एआइ वीडियो आदि भी खूब प्रसारित हो रहे हैं और इंटरनेट मीडिया पर नैरेटिव की जंग जोरों से चल रही है।

भाजपा को हिंदुत्व की पिच पर ही चुनौती देने की रणनीति पर सपा पहले से काम कर रही है। महाकुंभ आयोजन के बाद से अखिलेश यादव लगातार सनातन सम्मान से जुड़े हर मुद्दे पर मुखर हैं। चढ़ावा चोरी का मामला उन्होंने सबसे पहले उठाया था। इसके बाद जनभावनाएं मुखर होती देख सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा पर सनातन आस्था के साथ विश्वासघात के आरोप लगाए जा रहे हैं और सपा खुलकर राम और सनातन में अपनी आस्था दर्शा रही है। इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए सपा प्रमुख ने 'क्या फिर से चले गए वनवास' वीडियो गीत अपने एक्स हैंडल पर साझा किया था। इंटरनेट मीडिया पर चढ़ावा चोरी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे के दौरान उनके स्वागत में हनुमान की प्रतिकृति के नृत्य करने के मीम और एआइ वीडियो के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। इसके जवाब में भाजपा भी सपा को रामद्रोही करार दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेता मंदिर आंदोलन के दौरान सपा के विरोध की याद दिला रहे हैं। मुलायम सरकार में कारसेवकों पर गोली चलवाने का मामला उठा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही, इंटरनेट मीडिया पर हिंदुत्व पर सवाल उठाते सपा के वीडियो आदि साझा हो रहे हैं। इनमें मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव के वीडियो भी हैं।

हाल ही में लखनऊ सहित कई शहरों में कारसेवकों पर गोली चलाने और हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाने जैसे मुद्दों पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पोस्टर लगाकर सपा के हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए गए थे। इनमें 'दिल में बाबर, मुंह में राम' लिखे पोस्टर भी शामिल थे। मंदिर आंदोलन के इतिहास के चलते नैरेटिव की इस लड़ाई में सपा के सामने चुनौती भाजपा से ज्यादा दिखती है। हालांकि पार्टी का मानना है कि उस पर हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप तो हर चुनाव में लगते रहे हैं। ऐसे में वह भाजपा पर हमले जारी रखेगी। इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण और सपा प्रमुख के अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दर्शन करने के बाद इस रणनीति को और धार मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सपा और भाजपा के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर यह राजनीतिक लड़ाई जमीन से लेकर इंटरनेट मीडिया तक पर अभी और तेज ही होगी।

भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए पूरा तंत्र जिम्मेदार : राहुल गांधी

- सरकार की रीति-नीति पर साधा निशाना
- कहा, सरकारी नौकरियों तक पहुंच का रास्ता पेपरलीक और परीक्षा में धांधली के कारण हुआ बाधित

देहरादून में शुक्रवार को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में अपनी बात रखते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक के पूरे तंत्र जिम्मेदार ठहराया है। कोचिंग सेंटर से लेकर परीक्षा केंद्र, पेपर सेंटर, माफिया व वेंडर, एनटीए और मंत्रालय के लोग इसमें शामिल हैं।

उन्होंने शुक्रवार को देहरादून के रेसकोर्स स्थित सनातन धर्म इंटर कालेज बन्नू के मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार के अवसर सीमित कर दिए हैं। सरकारी नौकरियों तक पहुंच का रास्ता पेपर लीक तथा परीक्षा में धांधली के कारण बाधित हुआ है। राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, केवल युवाओं के भविष्य को लेकर है। उन्होंने कहा कि हर साल हिंदुस्तान में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के मेधावी छात्र-छात्राएं कठिन परिश्रम के बल पर सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, लेकिन पेपर लीक ने उनकी उम्मीदों को आघात पहुंचाया है। "चोर दरवाजे" से केवल एक प्रतिशत युवाओं को लाभ मिलता है, जबकि 99 प्रतिशत ईमानदार और मेहनती युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

राहुल ने चार युवाओं को मंच पर बुलाकर उनसे बात की। युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अपने अनुभव साझा किए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले दस वर्षों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। उन्होंने हाल ही में आत्महत्या करने वाली नीट अभ्यर्थी रिया थापा के पिता राजेश थापा को भी मंच पर बुलाया। राहुल ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बिहार में अपमान से आहत राजद प्रदेश प्रवक्ता ने दिया त्यागपत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : लगभग 20 वर्षों से राजद से जुड़े रहे प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। गुरुवार को उन्होंने इसकी मौखिक घोषणा की और शुक्रवार को लिखित में पार्टी नेतृत्व को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। आरोप यह कि पिछले सात-आठ माह से पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव तक से गुहार लगाकर थक गए, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। पांच-छह दिन पहले भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से मेल-मिलाप के बाद मृत्युंजय पर पार्टी के कुछ नेताओं की भृकुटियां टेढ़ी हो गई थीं। उन्हें टीवी आदि पर राजद का पक्ष रखने से मौखिक रूप से मना किया गया। इससे आहत मृत्युंजय मान रहे कि राह अलग कर लेना ही उचित रहेगा। बहरहाल पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने फोन कर मृत्युंजय को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने का सुझाव दिया है। मृत्युंजय का कहना है कि वस्तुतः राजद में निष्ठावान-समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान ही नहीं। ऐसे में वहां बने रहने का कोई तुक नहीं। तेजस्वी कुछ ऐसे अभिमानी लोगों से घिर गए हैं, जो राजद को भीतर-ही-भीतर खोखला कर रहे।

मृत्युंजय तिवारी।

'मेरे क्षेत्र में बिना बताए कोई पार्टी नेता आया तो उसका मुंह काला कर दूंगा'

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा

- मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबंदी फिर आई सामने, विधायक ने संगठन पर लगाया उपेक्षा का आरोप

भेरू सिंह परिहार बापू

सुसनेर विधानसभा सीट से विधायक हैं भेरू सिंह परिहार, पार्टी छोड़ने से किया इन्कार

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबंदी फिर सामने आई है। सुसनेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भेरू सिंह परिहार बापू ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर के कुछ बड़े नेता कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहते। उन्हें के इशारों पर जिला संगठन काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिना बताए कोई बाहरी पार्टी नेता आया तो मुंह काला कर से उसे बाहर निकालेंगे।

जिला मुख्यालय पर आयोजित दिशा समिति की बैठक में पहुंचे विधायक परिहार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के हालिया आगर दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। कार्यक्रम से पहले उन्होंने अजय सिंह से फोन पर संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिला। इस दौरान विधायक ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि "आगे से मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई नेता बिना बताए आया तो उसका मुंह काला कर विधानसभा से बाहर निकालूंगा।" विधायक ने आरोप लगाया कि समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। यदि संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने पार्टी छोड़ने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया।

भाजपा के टिकट पर राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सुखेंदु, सुष्मिता व प्रकाश

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- राज्यसभा से इस्तीफे के बाद तीनों हाल ही में भाजपा में हुए हैं शामिल
- बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई पांच

सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश चिक बड़ाइक और सुष्मिता देव। फाइल

तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक शुक्रवार को बंगाल से भाजपा के टिकट पर निर्विरोध राज्यसभा (रास) के लिए चुने गए। रास उपचुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफिसर ने शाम को राज्य विधानसभा में तीनों को निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व कई विधायक उपस्थित थे। उपचुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के बाद बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। फिलहाल बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के दो सदस्य प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा हैं।

बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की करारी हार के बाद तीनों ने पिछले महीने रास की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। इस्तीफे के करीब एक माह बाद तीनों गत नौ जुलाई को कोलकाता में भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा ने उसी दिन तीनों को उनके इस्तीफे के चलते बंगाल से खाली हुईं रास की तीन सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। उनके भाजपा में शामिल होने से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था।

कोयल मल्लिक को भी राज्यसभा भेज सकती है भाजपा : बांग्ला अभिनेत्री कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद उनके भी भाजपा के टिकट पर दोबारा राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हैं। कोयल मार्च में ही तृणमूल के टिकट पर निर्वाचित हुई थीं और गुरुवार को इस्तीफा देने के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बंगाल चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी।

'उद्धव को विरोध प्रदर्शन के दौरान ही याद आते हैं प्रभु राम और हनुमान'

- महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं हुए थे शामिल
- उनका 'राम रक्षा आंदोलन' अपनी पार्टी को बचाने की एक कोशिश : नवनीत राणा

संजय शिरसाट। फाइल

छत्रपति संभाजीनगर, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) पर तीखा हमला किया। कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भगवान श्रीराम और हनुमान केवल विरोध प्रदर्शन के दौरान ही याद आते हैं। उनकी यह टिप्पणी राममंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर उद्धव की शिवसेना द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर थी।

भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी इस मुद्दे पर ठाकरे पर निशाना साधा। दावा किया कि उनका 'राम रक्षा आंदोलन' अपनी पार्टी को बचाने की एक कोशिश है। छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बात करते हुए शिरसाट ने कहा कि निमंत्रण मिलने के बाद भी उद्धव अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए थे। इससे पता चलता है कि उद्धव को भगवान राम और हनुमान केवल विरोध प्रदर्शन के दौरान ही याद आते हैं।

उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया, जब पूर्व सांसद राणा को कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 2022 में ठाकरे के मुंबई स्थित आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। राकांपा (शरद चंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार और राजग के बीच बातचीत का हवाला देते हुए, उन्होंने राज्य की राजनीति में "बदलाव" का भी संकेत दिया।

कोलकाता एयरपोर्ट परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की घोषणा के बाद पीछे हटे सिद्दीकुल्ला

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- बंगाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी है
- सिद्दीकुल्ला ने विरोध मेंम वहां नमाज पढ़ने की घोषणा की थी

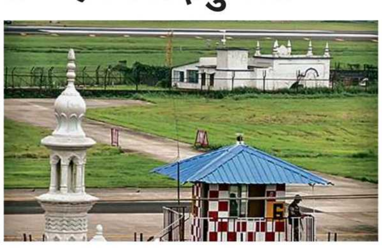
कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित बांकड़ा मस्जिद। एएनआइ

कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित बांकड़ा मस्जिद (गौरीपुर जामा मस्जिद) में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के अपने घोषित कार्यक्रम से बंगाल के पूर्व मंत्री व पश्चिम बंगाल जमीयत-ए-उलेमा हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी पीछे हट गए। परिसर पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद घोषणा की कि आज कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने फैसला बदलने का कारण नहीं बताया। शुक्रवार को मस्जिद वाले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों व केंद्रीय बल के जवानों की तैनाती की गई थी।

मालूम हो कि बंगाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी है। सिद्दीकुल्ला ने इसका विरोध करते हुए वहां शुक्रवार को नमाज पढ़ने की घोषणा की थी। स्थानीय मुस्लिमों से हवाई अड्डे के सात नंबर गेट पर एकत्र होने का आह्वान किया था। साथ ही राज्य के करीब एक करोड़ मुस्लिमों से बंगाल सरकार के इस निर्णय के विरोध में काला बैज पहनकर नमाज पढ़ने की अपील की थी। सिद्दीकुल्ला ने दावा किया था कि एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई है। दरअसल, कोलकाता एयरपोर्ट परिसर से करीब 136 वर्ष पुरानी बांकड़ा मस्जिद को स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। इसी के तहत मस्जिद में नमाज पढ़ने और वहां आने-जाने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। दमदम एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं। मुख्य रनवे से बड़े विमानों का संचालन होता है, जबकि दूसरा रनवे अपेक्षाकृत छोटा है, उसी के निकट यह मस्जिद स्थित है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद की मौजूद स्थिति विमान संचालन के लिहाज से जोखिम पैदा करती है। दूसरे रनवे के विस्तार का कार्य भी लंबे समय से प्रभावित है। कई दशकों तक इस पर चर्चा के बाद अब मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

फडणवीस को मिल सकती है राष्ट्रीय भूमिका : संजय राउत

नागपुर, प्रेट्र : शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि यदि आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य दोनों जगह कैबिनेट में फेरबदल होता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जा सकते हैं और राज्य में उनकी जगह भाजपा का कोई मंत्री ले सकता है। वह नागपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। वह यहां शिवसेना (यूबीटी) के 'राम रक्षा आंदोलन' से पहले शहर के दौरे पर आए थे। राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) ने अयोध्या राम मंदिर में चंदे की चोरी के खिलाफ 18 जुलाई को नागपुर में राम रक्षा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित इस तरह के सभी संगठनों को निमंत्रण भेजा गया है। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से अनुरोध किया है कि यदि वह स्वयं नहीं आ सकते हैं तो अपना प्रतिनिधि भेजें। इसी तरह भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है।

टैक्स चोरी के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री के भाई पर चावल घोटाले का दाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट

- मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री रामकिशोर नानू कावरे के भाई पर एसआइटी का शिकंजा
- हर्ष राइस मिल पर चावल घोटाले व पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश के चावल घोटाले में परसवाड़ा से विधायक रहे पूर्व राज्यमंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर नानू कावरे के भाई कुमार कावरे पर एसआइटी का शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी हर्ष राइस मिल पर चावल घोटाले का दाग लग गया है। सूत्रों के अनुसार, एसआइटी को साक्ष्य मिले हैं कि एफसीआइ गोदाम से छिंदवाड़ा एथनाल प्लांट के लिए जारी हुआ फोर्टिफाइड चावल कावरे की राइस मिल में भी खपाया गया। बता दें कि कुमार कावरे की दो अन्य कंपनियों पर डेढ़ करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था।

बता दें कि जनवरी में राज्य जीएसटी की टीम ने इसी हर्ष इंडस्ट्री (कंस्ट्रक्शन कंपनी) के आंवलाझरी स्थित कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके 20 दिन बाद ही टेकाड़ी स्थित हर्ष राइस मिल पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने मौके पर जांच भी की। अब यह फोर्टिफाइड चावल घोटाले के चलते विवाद में है। इस बारे में कुमार कावरे और उनके बिजनेस पार्टनर विनोद शर्मा व कावरे परिवार के अन्य सदस्यों से एसआइटी ने विस्तृत पूछताछ की है। कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा को घेरा है।

हर्ष राइस इंडस्ट्री का बोर्ड। नईदुनिया

डेढ़ करोड़ की गड़बड़ी मिली थी

15 जनवरी को राज्य जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो टीम ने कावरे की हर्ष इंडस्ट्री के साथ वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में छापा मारा था। तीन दिन तक दस्तावेजों की जांच चली। दोनों कंपनियों में टैक्स के 1.51 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मिली और इतनी ही राशि दोनों फर्मों से सरेंडर कराई गई। वहीं तीन फरवरी को भोपाल एनजीटी सेंट्रल बोर्ड के आदेश पर एक टीम ने हर्ष राइस मिल की जांच की थी। आरोप लगे थे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई, मिट्टी का अवैध खनन किया गया, पेड़ काटे गए, नाले पर कब्जा किया गया। हालांकि अधिकारी को वहां कोई गंभीर उल्लंघन नहीं मिला।

नई बहस

अभिनेता ने कहा- फिल्म बनाते समय हममें से कोई वांगचुक के बारे में नहीं जानता था, राजनीतिक दलों ने आड़े हाथों लिया, कहा- सरकार के डर से स्पष्ट रुख नहीं अपना रहे

आमिर बोले-'3 इडियट्स' वांगचुक पर आधारित नहीं, सियासत गर्माई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

हुसैन दलवई। फाइल

बालीवुड अभिनेता आमिर खान ने शुक्रवार को यह कहकर बहस छेड़ दी कि उनकी फिल्म "3 इडियट्स" में फुंसुख वांगडू वाला किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है। इस बयान पर राजद, कांग्रेस और आप जैसी राजनीतिक पार्टियों ने नाराजगी जताई और कहा कि फिल्म अभिनेता सरकार के डर से कोई स्पष्ट रुख अपनाने से बच रहे हैं। 2009 की ब्लाकबस्टर फिल्म "3 इडियट्स" का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। इसमें आमिर ने फुंसुख वांगडू (रैंचो) का किरदार निभाया था।

मुंबई से एंटरटेनमेंट ब्यूरो के अनुसार, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में आमिर की फिल्म "लगान" के 25 साल पूरे होने पर खास स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। इस मौके पर जब आमिर से पूछा गया कि क्या वाकई "3 इडियट्स" में उनका किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था? इस पर आमिर ने कहा कि यह सच नहीं है। यह एक गलतफहमी है। मैंने हाल ही में चतुर ("3 इडियट्स" के पात्र व अभिनेता ओमी वैद्य) का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन वह गलत है। जब हम फिल्म बना रहे थे, उस समय हममें से कोई भी सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानता था। आमिर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। कहा कि हम सभी आशा कर रहे हैं कि वह अपना अनशन समाप्त करें।

प्रेट्र के अनुसार, राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने आमिर के सफाई देने के समय पर सवाल उठाया। कहा-उन्हें यह बात कहने में इतने साल लग गए। मुझे तो यह भी याद नहीं कि फिल्म कितने साल पहले रिलीज हुई थी। अब तक तो सब यही मानते थे। अब जाकर आपको अहसास हुआ है कि यही बात कही जानी चाहिए थी।

वहीं, वांगचुक ने कहा कि वह 20 जुलाई तक हर हाल में जिंदा रहेंगे और उसी दिन प्रस्तावित संसद मार्च के जरिए अपनी बात लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाएंगे। कहा कि सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले बिना अनशन समाप्त करना गलत संदेश देगा।

इतने डरे हुए क्यों हैं आमिर : दलवई

कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य हुसैन दलवई ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि खान इतने डरे हुए क्यों हैं। उन्हें वांगचुक के प्रति सहानुभूति तो दिखानी ही चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह चाहे आमिर खान हों या कोई और, मोदी सरकार ने सबके असली चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। वे सभी इस सरकार के सामने झुक गए हैं। उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर कुछ यूजरों ने भी अभिनेता पर वांगचुक से दूरी बनाने का आरोप लगाया। एक यूजर ने कहा-इस आदमी की सारी इज्जत तुरंत खत्म हो गई। एकदम डरपोक। एक अन्य यूजर ने लिखा-मुझे समझ नहीं आता कि कोई इन लोगों का फैन कैसे हो सकता है।

वांगचुक के समर्थन में उतरी कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पार्टी ने जंतर-मंतर पर पवन खेड़ा को भेज वांगचुक से अनशन तोड़ने का किया आग्रह

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पेपर लीक और व्यवस्था की गंभीर खामियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है। समझा जाता है कि छात्रों के पक्ष में जारी अनशन का समर्थन करने की कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्पष्ट राय के बाद पार्टी ने जंतर-मंतर पर 'कारकोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के मंच पर जाकर वांगचुक के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वैसे तो गुरुवार को ही एक संक्षिप्त बयान में वांगचुक का समर्थन करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया था। लेकिन शुक्रवार को पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा को कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वांगचुक से मिलने जंतर-मंतर पर भेजा गया। ताकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रुख को लेकर किंतु-परंतु के सारे सवालों का रास्ता बंद हो जाए।

वांगचुक तथा अनशनकारी छात्रों से जंतर-मंतर पर मुलाकात के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि जब नागरिक विरोध करते हैं तो उनकी बातें सुनना सरकार का कर्तव्य है। मगर वांगचुक तथा युवा छात्रों की बात नहीं सुना जाना सरकार की असंवेदनशीलता के साथ ही लोकतंत्र के प्रति उसके अशोभनीय अहंकार को दर्शाता है। वांगचुक और छात्रों से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन समाप्त करने का अनुरोध कर कहा कि अपने लोगों को खोकर कोई आंदोलन मजबूत नहीं होता।

8 किलो अफीम का दूध और 1.60 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है जोधपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जो एनएसजी में कमांडो रह चुका है।

लगातार बढ़ रहा मेडिकल में दाखिले का क्रेज, आठ वर्षों में 50% आवेदन बढ़े

2019 में आवेदन करने वालों में 6.80 लाख छात्र और 8.38 लाख छात्राएं शामिल

2026 में आवेदन करने वालों में छात्रों की संख्या 9.46 लाख, जबकि छात्राओं की संख्या हुई 13.32 लाख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

युवाओं में मेडिकल से जुड़े कोर्सों में दाखिले का क्रेज न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका अंदाजा मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की एक ताजा रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसके अनुसार, पिछले आठ वर्षों में मेडिकल में दाखिले के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें भी छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में मेडिकल में दाखिले से जुड़े परीक्षा नीट-यूजी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या जहां 15 लाख थी, वहीं 2026 में आवेदन करने वालों की संख्या 22.79 लाख हो गई है। यानी पिछले आठ सालों में इसमें साढ़े सात लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। जो 2019 के मुकाबले पचास प्रतिशत अधिक है। 2019 में आवेदन करने वालों में 6.80 लाख छात्र व 8.38 लाख छात्राएं थीं। जबकि 2026 में इनमें आवेदन करने वालों में छात्रों की संख्या 9.46 लाख हो गई, जबकि छात्राओं की संख्या 13.32 लाख हो गई है।

आंकड़ों को देखें तो पिछले आठ सालों में नीट-यूजी में आवेदन करने वालों में छात्रों की संख्या में जहां 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं छात्राओं की संख्या में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि मेडिकल दाखिले से जुड़ी नीट-यूजी की यह परीक्षा अभी पेन-पेपर मोड में ही होती रही है। हालांकि अगले साल से इसे सीबीटी मोड में कराने का फैसला लिया गया है।

आठ वर्षों में हिंदी माध्यम से नीट-यूजी देने वालों की संख्या हुई दोगुनी : छात्रों को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की मुहिम में जुटी केंद्र सरकार के लिए एनटीए की यह रिपोर्ट उत्साहित कर सकती है, जिसमें नीट-यूजी में पिछले आठ सालों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्र तेजी से बढ़े है। खासकर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या आठ सालों में दोगुनी हो गई है। 2019 में जहां 1.79 लाख छात्रों ने हिंदी माध्यम के जरिये परीक्षा दी थी, वहीं 2026 में यह संख्या 3.45 लाख हो गई है। बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसे भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि मराठी, कन्नड़ व ओडिया भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वालों की संख्या घटी है।

नीट अभ्यर्थी डिजिलाकर से जल्द प्राप्त कर सकेंगे पुराने स्कोरकार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीट अभ्यर्थी जल्द ही डिजिलाकर के जरिये पुराने स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकेंगे। एनटीए ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि नीट के पिछले वर्षों के स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिलाकर आधारित व्यवस्था तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। यह व्यवस्था शुरू होने के बाद छात्रों को अपने पुराने स्कोरकार्ड तक पहुंच खोने की चिंता नहीं रहेगी। आरटीआइ अधिनियम के तहत दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने आई है। यह अपील नीट-यूजी 2020 की एक अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई थी। उसने अपने स्कोरकार्ड की प्रमाणित प्रति और अपनी योग्यता की पुष्टि संबंधी दस्तावेज मांगा था ताकि वह इन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के लिए पात्रता सत्यापन के वास्ते राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में जमा करा सके। एनटीए ने सीआइसी को बताया कि उसने इस मुद्दे की समीक्षा की है और वह डिजिलाकर के साथ एक ऐसा तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिससे अभ्यर्थी पिछले वर्षों के स्कोरकार्ड दोबारा प्राप्त कर सकें।

तीन बार बदला परिणाम, पहले 609, फिर 540 और बाद में 167 का स्कोर

जागरण संवाददाता, कानपुर

- कानपुर की आर्या सिंह ने किया दावा- नीट के स्कोर कार्ड में की गई गड़बड़ी
- एनटीए ने ओएमआर शीट में गलती की, शिक्षा मंत्री को भेजा ईमेल

आर्या सिंह। स्वयं

नीट-यूजी के परिणामों को लेकर एक बार फिर बड़ी लापरवाही व तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगा है। परीक्षा के बाद जारी ओएमआर शीट व फाइनल आंसर-की के मिलान में 609 अंक प्राप्त करने वाली कानपुर की छात्रा आर्या सिंह का दावा है कि एनटीए के पोर्टल पर उनका स्कोर कार्ड केवल कुछ ही घंटों में बदल गया। पहले 540 अंक दिखाए गए, फिर यह स्कोर 167 अंक पर पहुंच गया। छात्रा ने इस गड़बड़ी की शिकायत एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ईमेल भेजकर की है। छात्रा के पिता पूर्व सैनिक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस विसंगति के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

छात्रा ने बताया कि 21 जून को आयोजित री-नीट के परिणाम जारी करने में गड़बड़ी हुई है। एनटीए द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर 13 जुलाई को जारी की री-नीट की पहली ओएमआर शीट (नंबर-3823333) में प्रश्न संख्या 77 गायब था और 85 दो बार दर्ज था। इस तकनीकी त्रुटि पर जब उन्होंने पोर्टल के माध्यम से प्रश्न संख्या 77 पर चुनौती दी तो एनटीए ने दूसरी अपडेटेड ओएमआर शीट तो जारी कर दी, लेकिन उसका सीरियल नंबर बदलकर 3824338 कर दिया गया। दोनों ही ओएमआर शीट व एनटीए की फाइनल आंसर-की के मिलान से आर्या के कुल 609 अंक बन रहे थे। दावा है कि असली गड़बड़ी 16 जुलाई को परिणाम घोषित होने के बाद शुरू हुई। पोर्टल पर पहला परिणाम रात 12 बजे देखा गया तो स्कोर कार्ड पर 540 अंक प्रदर्शित हो रहे थे। संदेह होने पर दोबारा लागिन करने पर भी अंक 540 ही थे। तीसरी बार रात दो बजे स्कोरकार्ड खोल कर देखा तो कुल अंक घटकर सीधे 167 रह गए। वर्तमान में भी पोर्टल पर यही स्कोर दिख रहा है। इसका असर उनकी आल इंडिया रैंक 12,52,036 और कैटेगरी रैंक (जनरल) 3,67,585 पर पड़ा है, जो बहुत नीचे है। आर्या ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को सभी साक्ष्यों के साथ ईमेल भेजकर जवाब मांगा है।

सभी कोर्ट परिसर में शौचालय बनाइए, भले ही शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाइए

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश भर की जिला अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी अदालतों में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। बेंच ने मौखिक रूप से कहा, "भले ही शराब या सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज टैक्स लगाएं, और हम उसे सही ठहराएंगे।"

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि शौचालय की सुविधा एक बुनियादी मानवाधिकार है और इसके लिए फंड की कमी को बहाना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले पर छह हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "कृपया महिला वकीलों के काम करने की खराब स्थिति पर ध्यान दें। सभी एडवोकेट जनरल को जमीनी स्तर पर असल स्थिति का पता लगाना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। सिर्फ यह कह देना कि फंड नहीं है, काफी नहीं है क्योंकि यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए बार रूम और दूसरी जरूरी सुविधाओं के न होने का मुद्दा उठाया गया था।

बिहार में 131 करोड़ के अवैध बालू खनन में ईडी का तीन राज्यों में छापा

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

2015 से 2023 के दौरान बांका जिले में बड़े पैमाने पर हुआ अवैध बालू खनन

बिहार, राजस्थान और दिल्ली में एक साथ आठ ठिकानों पर छापेमारी

बिहार के बांका में 131 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध बालू खनन मामले में शुक्रवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की पटना क्षेत्रीय टीम ने बिहार, राजस्थान और दिल्ली में एक साथ आठ ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। जानकारी के अनुसार पटना और बांका में एक-एक स्थान, दिल्ली-एनसीआर में एक स्थान, राजस्थान के श्रीगंगानगर में चार स्थान और जयपुर में एक स्थान पर तलाशी की सूचना है।

जांच महादेव एनक्लेव प्रा. लि. से जुड़े मामले में की जा रही है। कंपनी का नियंत्रण राजस्थान के श्रीगंगानगर के चंदक परिवार के पास है। कंपनी का संचालन अशोक चंदक और उनके बेटे राघव चंदक करते हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 के दौरान बांका जिले में बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया। हैरानी की बात यह रही कि इतने लंबे समय तक यह खनन राज्य के खनन विभाग की जानकारी तक में नहीं आया। ईडी ने बांका जिले के बालू घाटों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया। उपग्रह चित्रों और विश्लेषण के आधार पर तैयार रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने 131 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के बालू का अवैध खनन किया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी ने संबंधित जानकारी बिहार राज्य खनन निगम और राज्य सरकार को भेजी। इसके आधार पर खान एवं भूविज्ञान विभाग ने पिछले वर्ष 21 अगस्त को बांका में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच अभी जारी है।

नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता अचल संपत्ति का दस्तावेज: कलकत्ता हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- अदालत ने कहा- विदेशी भी खरीद सकते हैं भारत में संपत्ति, जमीन के कागजात से कोई नहीं बन जाता भारतीय नागरिक
- सिर्फ जमीन के दस्तावेज ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट को भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता

देश की नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान की कानूनी व्याख्या को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाली टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में भूमि अथवा किसी भी अन्य अचल संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज (लैंड डीड) किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अचूक प्रमाण नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने दो-टूक शब्दों में कहा कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में कानूनन संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन महज संपत्ति खरीदने मात्र से वह स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं बन जाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर नागरिकता के कानूनी दस्तावेजों को लेकर देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कानूनी जानकारों के अनुसार, सिर्फ जमीन के दस्तावेज ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट को भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

कलकत्ता हाई कोर्ट

एक बांग्लादेशी के मामले में आई टिप्पणी : यह सख्त टिप्पणी न्यायालय ने नासिर मोल्ला नामक एक व्यक्ति की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।

नासिर को इसी साल 18 जून को मुर्शिदाबाद जिले से 'बांग्लादेशी घुसपैठिया' होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। वर्तमान में वह लालगोला होल्डिंग सेंटर में बंद है। नासिर के चचेरे भाई सुमन ने इस हिरासत को गलत बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि नासिर एक वैध भारतीय नागरिक है।

जब अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से नागरिकता साबित करने वाले ठोस दस्तावेज मांगे, तो जवाब में केवल नासिर के नाम पर पंजीकृत जमीन के कागजात ही पेश किए गए। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि जमीन के रिकार्ड नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं हैं।

अदालत ने न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आरोपित के परिवार को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का एक अंतिम मौका दिया है।

'नामित सदस्यों को विधान परिषद चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं'

2021 के पुनर्मतगणना के खिलाफ भाजपा के केएलसी सदस्य की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट।

कहा-चार टाउन पंचायतों के नामित 12 सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नगरपालिकाओं में नामित सदस्यों को विधान परिषद चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं है और इसने 2021 के चुनावों में मतों की पुनर्गणना के खिलाफ भाजपा के कर्नाटक विधान परिषद (केएलसी) सदस्य प्रणेश एम के द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को एक आदेश में कहा कि कर्नाटक नगरपालिकाओं अधिनियम (केएमए) के तहत चार टाउन पंचायतों में नामित 12 सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं है और वे विधान परिषद चुनावों के लिए मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, "हमारे विचार में केएमए की धारा 352(1)(ब) के तहत नामित सदस्यों को स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल करने का अधिकार नहीं है और उनका समावेश संविधान की योजना के खिलाफ है और इसे कानून में बनाए नहीं रखा जा सकता।"

प्रणेश को चार टाउन पंचायतों के 12 नामित सदस्यों के उनके पक्ष में मतदान करने के बाद छह मतों के संकीर्ण अंतर से एमएलसी के रूप में चुना गया था। पीठ ने कहा कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वे लोग, जिन्हें संविधान द्वारा नगरपालिका मामलों में मतदान करने की अनुमति नहीं है, विधान परिषद के सदस्यों के चुनावों में मतदान कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यदि संविधान के अनुच्छेद 171(3)(अ) को इस प्रकार से व्याख्यायित किया जाए कि नामित सदस्यों को शामिल किया जाए, तो एक असंगत परिणाम उत्पन्न होगा।

एसआइआर पर लोगों को विश्वास, बढ़ा मतदान प्रतिशत इसका स्पष्ट संकेत: ज्ञानेश कुमार

गौतम कुमार मिश्रा • जागरण

- मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, संविधान के दायरे में ही चुनाव, फिलहाल 'एक देश-एक चुनाव' संभव नहीं
- दिल्ली में आयोजित आल इंडिया मीडिया कांफ्रेंस में आए विभिन्न राज्यों के लोगों को कर रहे थे संबोधित

ज्ञानेश कुमार। फाइल

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जहां-जहां भी एसआइआर हुआ है, वहां मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर मतदाताओं का पूरा भरोसा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में आयोजित आल इंडिया मीडिया कांफ्रेंस में आए विभिन्न राज्यों के लोगों को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि 'एक देश-एक चुनाव' को लेकर स्पष्ट किया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरह संविधान के अनुसार कार्य करता है और उसके दायरे से बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता। फिलहाल संवैधानिक व्यवस्था में 'एक देश-एक चुनाव' का कोई प्रविधान नहीं है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल इस तरह की व्यवस्था को आजमाना करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है।

कार्यक्रम में कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर उठ रहे सवालों पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बढ़ा मतदान प्रतिशत इसका बात का स्पष्ट संकेत है कि एसआइआर पर लोगों को विश्वास है। बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत का उल्लेख करते हुए उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 93 प्रतिशत को पार कर गया था। पूरी दुनिया में मतदान को लेकर इतना उत्साह कहीं और नहीं देखा गया। यह दर्शाता है कि लोग एसआइआर को लेकर पूरी तरह निर्वाचन आयोग पर भरोसा कर रहे हैं। एसआइआर को प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वालों को आड़े हाथों लेते ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि भारत में हर चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराया जाता है। यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो इसे लेकर लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इसका भी हमारे यहां प्रविधान है।

एक शादी करने वाला ही मध्य प्रदेश में रह पाएगा: मोहन यादव

नईदुनिया, जबलपुर : मध्य प्रदेश के कटनी में टनल के निरीक्षण के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य में एक समान कानून लागू होगा। कहा कि मध्य प्रदेश में एक शादी करने वाला ही रह पाएगा।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश में सभी धर्मावलंबियों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाई जाएगी। मोहन यादव ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हो। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम दो से अधिक शादी क्यों करेगा। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और अब यूसीसी को भी हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देख रही है।

विस्तारा एयरलाइंस ने जज का कंफर्म टिकट दूसरे को बेचा, एक लाख जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर

45 दिनों के भीतर करना होगा जुर्माने का भुगतान, नहीं तो देना पड़ेगा सात प्रतिशत ब्याज

- ओवरबुकिंग का हवाला देकर एयरलाइंस ने रद किया था छत्तीसगढ़ के एडीजे का टिकट

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 10 हजार रुपये मुकदमे में लगा खर्च शामिल है। यह राशि शिकायतकर्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार वासनीकर को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। आयोग ने साफ किया कि अगर 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो एयरलाइंस को इस राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामला कांकेर में पदस्थ एडीजे भूपेंद्र कुमार वासनीकर से जुड़ा है। जज अपने परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद 28 मई 2023 को दिल्ली से रायपुर लौट रहे थे। उन्होंने 11 मई को ही 23,156 रुपये का भुगतान कर विस्तारा फ्लाइट के चार टिकट बुक किए थे। 28 मई को उड़ान के समय से चार घंटे पहले (दोपहर दो बजे) वे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इसके बावजूद विस्तारा के कर्मचारियों ने उन्हें तीन घंटे तक बोर्डिंग पास जारी नहीं किया। अंत में उड़ान से एक घंटे पहले ओवरबुकिंग का हवाला देकर जज का टिकट रद कर दिया गया और केवल उनकी पत्नी व बेटे-बेटी को रायपुर भेजा गया।

एडीजे को दिल्ली में ही रुकना पड़ा और अगले दिन उन्हें इंडिगो एयरलाइंस की 18,823 रुपये की टिकट खरीदकर रायपुर आना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य आनंद वर्गीस की पीठ ने पाया कि जज ने जो टिकट 11 मई को 7,204 रुपये में खरीदा था, उसे एयरलाइन ने 28 मई को किसी अन्य यात्री को 40 हजार रुपये में बेच दिया।

महाराष्ट्र में इच्छा-मृत्यु के मामलों के लिए मेडिकल पैनल बनाने का आदेश

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक निर्देश जारी किया, जिसमें निजी अस्पतालों में पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा-मृत्यु) और लिविंग विल के मामलों से निपटने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया है। लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कोई व्यक्ति यह तय करता है कि अगर वह भविष्य में किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अचेत अवस्था के कारण अपनी इच्छा बताने की स्थिति में नहीं रहा, तो उसका चिकित्सीय उपचार कैसे किया जाए। राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का यह सरकारी आदेश हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के फैसले के बाद आया है। राणा, जो 2013 से कोमा में थे, भारत में 'पैसिव यूथेनेशिया' की मंजूरी पाने वाले पहले व्यक्ति बने। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया जा रहा जीवन रक्षक सपोर्ट हटाने की मंजूरी दी थी। उनकी मौत एम्स में हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र रहे राणा 2013 में चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे।

उपलब्धि

सोलर, विंड से इतर बिना रुकावट मिल सकेगी चौबीसों घंटे बिजली, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुंओं का लोकार्पण किया

लद्दाख में रचा गया इतिहास, भारत के पहले जियोथर्मल कुएं तैयार

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

लद्दाख में भू तापीय उर्जा तैयार करने के लिए लेह की पुगा वैली में खोदे गए जियोथर्मल कुएं। सूचना विभाग

क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। लद्दाख के पुगा में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुएं तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुओं का लोकार्पण किया। आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित परियोजना भारत के पहले एक मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक मानी जा रही है। भूतापीय ऊर्जा (जियोथर्मल एनर्जी) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लगातार, बिना रुकावट दिन में 24 घंटे और वर्षभर बिजली बना सकती है। जबकि सोलर प्लांट रात में काम नहीं करते हैं और विंड फार्म को खास हवा की स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन धरती की कुदरती अंदरूनी गर्मी से चलने वाले जियोथर्मल प्लांट पूरे साल चौबीसों घंटे चालू रह सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा से पानी को भाप में बदला जाता है और इससे टर्बाइन चलाए जाते हैं और बिजली पैदा की जाती है।

यह परियोजना लद्दाख की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। हमारी इंजीनियरिंग टीमों ने खराब मौसम और मुश्किल जमीन के नीचे की स्थितियों का सामना करते हुए रिकार्ड समय में कुओं की ड्रिलिंग पूरी की। यह उपलब्धि न केवल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख के विजन और नेट-जीरो इंडिया के लक्ष्य के करीब ले जाएगी।

लद्दाख समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक-एक हजार मीटर गहरे दोनों जियो थर्मल कुओं के शुरू होने से लद्दाख को स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में उपलब्धि है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, अत्यधिक ठंड, दुर्गम इलाके व सीमित कार्य अवधि के बावजूद पहला जियोथर्मल कुआं 22 मई को 1,000 मीटर की गहराई तक पूरा किया गया। दूसरा कुआं खोदने का काम पुगा वैली में 3 जून को शुरू हुआ। आठ जुलाई को रिकार्ड समय में दूसरे कुएं को 1,000 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। देश की महत्वकांक्षी परियोजना के इंजीनियरों के अनुसार, जियोथर्मल वेल में 400 मीटर की गहराई पर 135 डिग्री तापमान दर्ज किया है।

'तारीख पर तारीख' न्याय व्यवस्था की पहचान नहीं बन सकती: हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण • लखनऊ

- शादी हुई और दो बच्चे भी हो गए, लेकिन 25 वर्ष तक चलता रहा अपहरण का मुकदमा

वर्ष 2001 में दर्ज अपहरण के एक मुकदमे में पीड़िता ने बाद में आरोपित से विवाह कर लिया, दोनों के तीन बच्चे भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद मामला करीब 25 वर्ष तक अदालत में लंबित रहा। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'तारीख पर तारीख' आपराधिक न्याय व्यवस्था की पहचान नहीं बन सकती है। अदालत ने कहा कि किसी मुकदमे का इतने लंबे समय तक लंबित रहना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी बहराइच के पयागपुर थाने में 2001 में दर्ज अपहरण के मामले में आरोपित अजय कुमार उर्फ चिंगी और रामचंद्र की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि लड़की अपनी इच्छा से अजय कुमार के साथ गई थी। बाद में दोनों ने विवाह कर लिया और अब पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। राज्य सरकार इस तथ्य का प्रभावी ढंग से खंडन नहीं कर सकी। हाई कोर्ट ने पाया कि दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मुकदमे में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और न्यायिक प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई। अदालत ने कहा कि न्याय को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता और विचारण अदालतों को मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

355 गर्ल्स हास्टल बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 315 सरकारी महिला छात्रावास और 469 निजी महिला छात्रावासों को चिह्नित किया गया है। इनमें 469 महिला छात्रावास में से 114 महिला छात्रावास पंजीकृत पाए गए हैं।

टिन्नू यादव के करीबियों ने भी उठाया फायदा, खड़ी की करोड़ों की संपत्तियां

चंपतराय का चालक रहा टिन्नू अपने सहयोगियों के लिए भी साबित हुआ 'पारस पत्थर'

अनुकल्प, अविनाश, लवकुश, रमाशंकर मिश्र, मनीष सहित अन्य का भी किया सहयोग, बनाईं संपत्तियां

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू

टिन्नू और मनीष 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर

चढ़ावा चोरी मामले के शेष दो आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव का भी कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल गया है। विशेष न्यायालय ने दोनों को शनिवार सुबह आठ बजे से रविवार रात 11 बजे तक करीब 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। हालांकि विवेचक ने सात दिनों के रिमांड की अर्जी प्रस्तुत की थी। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस दोनों से पूछताछ करेगी और बरामदगी के लिए उनके ठिकानों पर भी ले जा सकेगी।

चढ़ावा चोरी के आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने न केवल स्वयं धन चुराकर संपत्तियां बनाईं, बल्कि अपने उन परिचितों व सहयोगियों की भी इस कार्य में सहायता की, जो कभी उसकी राह का कांटा बन सकते थे। आरोपित अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, अविनाश शुक्ल व रमाशंकर मिश्र के लिए तो टिन्नू 'पारस पत्थर' जैसा साबित हुआ ही, ट्रस्ट कर्मी महेश कुमार, अंकित, कृष्णदेव तिवारी सहित कुछ अन्य लोगों ने भी जमकर लाभ उठाया, जिनके नाम अब चर्चा में हैं। मंदिर में कार्यरत रहे कुछ कर्मी तो ऐसे भी हैं, जो चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद जांच शुरू होते ही काम छोड़ चुके हैं।

ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय का ड्राइवर रहा टिन्नू चढ़ावा चोरी प्रकरण का मास्टरमाइंड बन कर उभरा है। श्रीराम मंदिर में प्रवेश मिलने के बाद से ही उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके कारनामे सामने आ रहे हैं। उसके सहयोगियों की भी संपत्तियां उजागर हो रही हैं। टिन्नू के इशारे पर ही अनुकल्प, लवकुश, रमाशंकर, अविनाश, सुभाष आदि ने चढ़ावा चोरी की, तो इसमें मिले धन से अधिकांश ने संपत्तियों की खरीद शुरू कर दी थी। अनुकल्प ने तो अपने गांव मिल्कीपुर के बसावां में भागवत कथा का बड़ा आयोजन कर वैभव का प्रदर्शन किया और शहर के कौशलपुरी में 65 लाख का आलीशान मकान खरीद लिया। कई महंगे भूखंड भी खरीदे। इस खेल में अपने लोग ही शामिल रहें, इसके लिए अनुकल्प ने बहनोई लवकुश मिश्र को और टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव को भी ट्रस्टियों के सहयोग से गणना कर्मी बनवा दिया। ये भी टिन्नू व अनुकल्प के इशारे पर काम करने लगे।

रमाशंकर मिश्र व अविनाश ने दिखावे के लिए भले किराए का मकान लिया था, लेकिन ये भी अपने गांव में अचल संपत्तियां खरीद रहे थे। अविनाश ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को आइफोन भी दिया था। इसका प्रतापगढ़ का पैतृक घर भले जर्जर हो, परंतु इसने अयोध्या में महंगा भूखंड खरीदा था। हाल ही में एसआइटी से शिकायत के बाद उस लेखा कर्मी महेश कुमार उर्फ कालिया का नाम भी चर्चा में आया, जिसने टिन्नू के घर पर शरण ले रखी थी। इसने भी टिन्नू का कहना मानते हुए फर्जी बिलिंग की और बैंक खातों में जमा धन में हेरफेर करके गांव सहित कई शहरों में अचल संपत्तियां खड़ी कर लीं। इन्हीं में से एक नाम मिल्कीपुर निवासी कृष्णदेव तिवारी का भी है, जो गर्भगृह में आभूषणों की देखरेख से जुड़े रहकर टिन्नू के इशारे पर कार्य करता था। इस बीच कई संपत्तियां उजागर हुई हैं।

गुजरात एटीएस ने पांच आतंकियों को किया गिरफ्तार

शत्रुघ्न शर्मा • जागरण

- विस्फोटक सामग्री खरीदकर बम धमाके करने का कर रहे थे अभ्यास
- जैश से जुड़कर एक आतंकी संगठन खड़ा करने की थी तैयारी

अहमदाबाद: आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर के भारत विरोधी जहरीले भाषण सुनकर जिहादी और आतंकी गतिविधियों में शामिल पांच युवकों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इंटरनेट मीडिया के जरिये ये जहां एक ओर कट्टरपंथी साहित्य का आदान-प्रदान करते थे, वहीं विस्फोटक सामग्री खरीदकर बम धमाके करने का प्रयोग भी कर रहे थे। गुजरात एटीएस के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी ने बताया कि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़कर कुछ युवकों के गुजरात में एक आतंकी संगठन खड़ा करने की तैयारी करने की सूचना मिली थी।

एटीएस के पुलिस अधीक्षक के सिद्धार्थ ने एक टीम बनाकर जांच शुरू की तो पता चला कि अब्दुल्ला गुजरात में जैश की मदद से एक आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। ये आतंकी टाइम बम बनाने के अलावा जहरीली गैस बनाने की भी तैयारी में थे। एटीएस का कहना है कि जामिया अबुल हसन मदरसा खडियासन में रहकर कुछ युवक बम बनाने व बम विस्फोट करने का प्रशिक्षण ले रहे थे।

इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन्होंने विस्फोटक पदार्थ, रसायन आदि का प्रबंध किया और 2023 से 2026 के बीच आठ बार बम विस्फोट करने का अभ्यास किया।

मोहम्मद शेरा ने आईईडी बनाने का तरीका सीख रहा था। वह टाइमर तकनीक से विस्फोट करने का भी आनलाइन प्रशिक्षण ले रहा था। इसके लिए आनलाइन गन पाउडर खरीदा। मोहम्मद अमीन शेरा के पास से आईईडी बम बनाने की सामग्री बरामद की गई है। जोशी ने बताया कि जांच के लिए इंस्टाग्राम आदि प्लेटफार्म से भी जानकारी मांगी गई है। एटीएस इनका उपयोग साक्ष्य के रूप में कर सकता है। पकड़े गए आरोपित उत्तर गुजरात के सिद्धपुर, वडगाम, बनासकांठा तथा भरुच के मकडीवाला मदरसा के हैं।

इनके पास से उर्दू में छपी कई पुस्तकें बरामद की गई हैं। इनके मोबाइल में आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर के भारत व हिंदू विरोधी जहरीले भाषणों के वीडियो क्लिप मिले हैं।

गुजरात व राजस्थान पुलिस की मदद से इन पांचों को गुजरात के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने गत आठ जुलाई को गैरकानूनी गतिविधियों तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आठ आतंकी पकड़े थे।

सावन माह के बाद मंदिर निर्माण के लिए मथुरा कूच की तैयारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने सावन मास के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा के लिए प्रस्थान कर भव्य मंदिर निर्माण के समर्थन में कार सेवा करने का ऐलान किया है। श्री राधा रासिक बिहारी मंदिर में आयोजित बैठक में संतों, महंतों और समाजसेवियों ने इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (निरंजनी) के अध्यक्ष श्रीमहंत डा. रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में सभी सनातनी मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में करोड़ों रामभक्तों और कार सेवकों के लंबे संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ, उसी प्रकार अब सनातन समाज मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भी संगठित होकर कार सेवा करेगा। भागवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मठ-मंदिरों और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा। संगठित प्रयासों से ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं स्वामी कार्तिक गिरी महाराज ने कहा कि समय आने पर प्रत्येक सनातनी को धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मथुरा कूच को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।

उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला अग्निवीर सेलः पुष्कर धामी

जागरण संवाददाता, देहरादून

- होमस्टे के लिए विशेष अनुदान, सीमांत गांवों में स्वरोजगार को भी बढ़ावा

सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य में अग्निवीर सेल बनाया जाएगा, जो अग्निवीरों को रोजगार, स्वरोजगार व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एकल सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल गठित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

शुक्रवार को दून स्थित यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया में आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को चार वर्ष की सेवा के बाद पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और सेवामुक्त अग्निवीरों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। सीमांत गांवों में रहने वाले पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों व स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने में भी सरकार आर्थिक

देहरादून में शुक्रवार को आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते पुष्कर सिंह धामी। सूचना विभाग

सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन सहित राज्य की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे चुकी है। साथ ही भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता भी सुनिश्चित की गई है।

मुर्शिदाबाद में क्रासिंग पार करते वक्त वैन को ट्रेन ने मारी टक्कर, तीन छात्रों समेत पांच की मौत

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- चार घायल, हादसे के समय खुला था रेल फाटक, ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में गेट मैन गिरफ्तार
- रेल मंत्री ने घटना पर जताया दुख, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन ने रेलवे क्रासिंग पार करते समय स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन में सवार तीन छात्र समेत पांच की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक साइकिल सवार भी शामिल हैं। हादसे के समय रेलवे फाटक खुला था। वैन में चालक समेत आठ लोग सवार थे। दुर्घटना सुबह करीब सात बजे मुर्शिदाबाद के बहरमपुर थाना क्षेत्र में बनियापुकुर स्टेशन के निकट गोविंदपुर रेलवे फाटक पर हुई।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) शिवराम माझी ने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में पुलिस ने गेटमैन को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना के समय गेटमैन नशे में था। रेलवे ने गेटमैन के साथ संबंधित ट्रैक निरीक्षक को तत्काल निलंबित करते

प्रतीकात्मक

हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये व घायलों को ढाई-ढाई लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर 10 सदस्यीय टीम भेजी गई है।

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हावड़ा जाने वाली नवद्वीप धाम एक्सप्रेस के गुजरने के बाद रेलवे फाटक बंद था। एक्सप्रेस ट्रेन निकलने के तुरंत बाद फाटक खोल दिया गया। उसी लाइन पर कुछ ही देर बाद निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन आने वाली थी। फाटक खुला देखकर स्कूल वैन चालक बच्चों को लेकर पटरी पार करने लगा। उसी समय एक साइकिल सवार भी पटरी पार कर रहा था। तभी तेज रफ्तार लोकल ट्रेन ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। गोबिंदपुर गांव के तीन छात्रों और 50 वर्षीय साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में एक अन्य घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई। बाद में बहरमपुर थाने की पुलिस भी पहुंची। स्कूल वैन में फंसे छात्रों को बाहर निकाला।

बिहार में लूटपाट के बाद बाल काट ले रहे बदमाश, आठ दिन में दूसरी घटना

जागरण संवाददाता, दरभंगा

- दरभंगा के डरहार की घटना, नहीं तोड़ सके आभूषण वाली आलमारी
- नौ जुलाई को चिकित्सक के घर हुई थी डकैती, बहू के काटे थे बाल

बिहार के दरभंगा जिले में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि लूटपाट के बाद बदमाश महिला और लड़की के बाल काट ले रहे हैं। आठ दिन में ऐसी दूसरी घटना हुई है। शहर से सटे डरहार गांव में गुरुवार की देर रात शिक्षक दंपती सुमन कुमार चौधरी और कुमारी भारती के घर लूटपाट के लिए बदमाश घुस गए। घर से उन्हें केवल एक हजार रुपये ही हाथ लगे। आभूषण वाली दूसरी अलमारी बदमाश खोल नहीं पाए। वारदात के दौरान बदमाश ने घर में सो रही किशोरी के बाल कैंची से काट दिया। बिस्तर पर कटा बाल मिला। घटना की सूचना पर डायल 112 की पुलिस पहुंची। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य सुरक्षित किया। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आसपास के सीसी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा।

सुमन निजी स्कूल में शिक्षक हैं, उनकी पत्नी हायाघाट स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। गृहस्वामी ने बताया कि बदमाश उनके घर में छत के रास्ते घुसे। उस समय पति-पत्नी प्रथम मंजिल के कमरे में सो रहे थे। नीचे के तल पर कमरे में उनकी छोटी पुत्री 17 वर्षीय आकांक्षा अकेले सो रही थी। कुछ हलचल हुई तो बेटी की नींद खुल गई। उसी समय एक बदमाश को उसने कमरे से छत की ओर भागते देखा। वह काले रंग के कपड़े में था। दोनों हाथों में खुजली होने पर आकांक्षा ने देखा तो हाथ पर एक तरह का स्प्रे छिड़का हुआ था। ध्यान बिस्तर पर गया तो बाल कटा दिखा। मालूम हो कि इसी गांव में नौ जुलाई की देर शाम होम्योपैथिक चिकित्सक पवन कुमार मिश्रा के घर डकैती हुई थी। डकैतों ने चिकित्सक की बहू के साथ मारपीट की और उनके बाल काट दिए थे।

वाराणसी में एक माह में कोरोना के तीन केस मिले, सभी स्वस्थ

जासं, वाराणसी : पिछले एक माह में वाराणसी में कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। इनमें दो मरीज बीएचयू और तीसरा मरीज अपने घर पर क्वारंटाइन रहकर उपचार किया। तीनों संक्रमित अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

शुक्रवार को सीएचसी, पीएचसी और जिला स्तरीय अस्पतालों में माक ड्रिल कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल, मंडलीय चिकित्सालय, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीजन जांच की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. बृजेश कुमार ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड, एंटीजन किट और अन्य आवश्यक संसाधन पूरी तरह तैयार हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। नोडल अधिकारी डा. शिशिर ने बताया कि तीनों संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है।

सिर्फ ट्रेन टिकट न होने से खारिज नहीं हो सकता दुर्घटना का मुआवजा दावा

माला दीक्षित • जागरण

- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन से गिर कर मौत के मामले में परिजन को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कहा है कि पीड़ित को मुआवजा देने से सिर्फ इसलिए इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृत यात्री के पास ट्रेन का टिकट नहीं मिला। लाभकारी कानूनों की व्याख्या शाब्दिक या प्रतिबंधात्मक नजरिया अपनाने के बजाय उद्देश्यपूर्ण और उदार तरीके से की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने ट्रेन से गिरकर मौत के मामले में यात्री के परिजन को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं होने पर आठ प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। शीर्ष अदालत ने रेलवे दावा ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला रद कर दिया है, जिसमें टिकट न मिलने के कारण मृतक के वास्तविक यात्री साबित नहीं होने के आधार पर मुआवजा दावा खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रेलवे में सुधारों, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी अहम निर्देश दिए हैं। रेलवे मैनुअल में सेकेंड क्लास पैसेंजर शब्द पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह यात्री द्वारा यात्रा पर किए गए खर्च से जुड़ा है। लेकिन सुझाव है कि श्रेणी यानी क्लास का संबंध कोच से होना चाहिए न कि यात्री से। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में श्रेणी-आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। इस तरह का वर्गीकरण संविधान की भावना के खिलाफ और अपमानजनक है।

इस मामले में 2015 में एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। उसकी पत्नी लता ने रेलवे दावा ट्रिब्यूनल में दावा दाखिल कर मुआवजा देने की मांग की थी। लेकिन, टिकट नहीं मिलने के आधार पर ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट ने उसका दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए जस्टिस करोल ने कहा है कि रेलवे एक्ट कल्याणकारी कानून है। तकनीकी दृष्टिकोण और प्रक्रिया की खामियों से कानून के कल्याणकारी उद्देश्य को विफल नहीं किया जाना चाहिए। कहा गया है कि रेलवे अधिनियम की धारा 124ए के तहत कार्यवाही दोष रहित दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को बिना किसी लापरवाही के प्रमाण की आवश्यकता के शीघ्र मुआवजा प्रदान करना है। सिर्फ इसलिए कि मृतक के पास ट्रेन का टिकट नहीं मिला, एक असली यात्री के तौर पर उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। मालूम हो कि इस मामले में मृतक का सामान नहीं मिला था। उसकी पत्नी का कहना था कि उसने टिकट लिया था।

महिला की हत्या कर शव से किया दुष्कर्म, आरी से काटे हाथ-पैर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बेमेतरा

- छत्तीसगढ़ का मामला, रंजिश में वारदात
- नदी में मिले लाश के टुकड़े, अलग-अलग गठरियों में बांधकर फेंका

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 50 वर्षीय महिला की हत्या और उसके शव से दुष्कर्म के आरोपित रामप्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपित ने पहले फावड़े से महिला की हत्या की। इसके बाद शव से दुष्कर्म कर उसके हाथ-पैर और धड़ आरी से काट दिए। फिर लाश के टुकड़ों को गठरी में बांधकर नदी में फेंक दिया। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने हत्याकांड का राजफाश किया।

एक युवक ने अपनी 50 वर्षीय मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौ जुलाई को शिवनाथ नदी के पास मृतका का शव टुकड़ों में साड़ी, कंबल और प्लास्टिक में लिपटा मिला था। मृतका के दोनों हाथ-पैर और धड़ अलग-अलग गठरियों में मिले। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, ड्रोन और खोजी अभियान के जरिए संदिग्ध रामप्रसाद सोनवानी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के कारण छह जुलाई की रात मृतका को घर में अकेला पाकर उसने दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर फावड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव के साथ दुष्कर्म किया और पहचान छिपाने के उद्देश्य से धारदार हथियार से शव के दोनों हाथ और पैर काट दिए। हाथ-पैर और धड़ को अलग-अलग गठरियों में बांधकर पहले अपनी झोपड़ी में रखा। फिर सात जुलाई की रात को नदी किनारे फेंक दिया।

वरिष्ठों से तंग शिक्षक ने नदी में कार गिराकर दो बच्चों सहित दी जान

छत्रपति संभाजीनगर, प्रेट्रः महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक शिक्षक ने पहले अपने वाट्सएप स्टेटस पर लिखा 'मैं अपने वरिष्ठों से परेशान हूं और आत्महत्या कर लूंगा।' हताशा और निराशा में आकर उसने ऐसा कर भी दिया। शुक्रवार को शिक्षक ने कथित तौर पर अपनी कार को गोदावरी नदी पर बने पुल की रेलिंग से टकराकर नदी में गिरा दी। कार में उसके दो बच्चे भी सवार थे। सभी की डूबने से मौत हो गई। हिमायतनगर के पोटा बुद्रुक जिला परिषद स्कूल में तैनात सुनील मोरे ने अपने वाट्सएप स्टेटस पर आरोप लगाया था कि उसके वरिष्ठ उसे परेशान कर रहे हैं। वह अपने दो बच्चों के साथ अपनी जान दे दे देगा। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे मोरे अपनी कार में 12 वर्षीय बेटी सारा और आठ वर्षीय बेटे सुमित को लेकर अमदुरा-पुणेगांव रोड पर गया और गोदावरी नदी पर बने पुल की रेलिंग से कार टकरा दी।

शर्मनाक

अररिया के जोगबनी स्थित प्राथमिक विद्यालय का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर हो रहा प्रसारित, स्कूली बच्चे घुटनों तक भरे कीचड़ और पानी में उतरकर शिक्षिका के लिए बना रहे बेंचों का पुल

मैडम के पैर में न लगे कीचड़, बच्चे बेंच से बनाते हैं रास्ता

जागरण संवाददाता, अररिया

बिहार के अररिया जिले से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिले के जोगबनी स्थित प्राथमिक विद्यालय (खजूरबाड़ी) की एक शिक्षिका ने अपने पैर कीचड़ से बचाने के लिए छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को घुटने तक गंदे पानी में उतार दिया। बच्चों ने गंदे पानी में भीगते हुए बेंचों का पुल बनाया, जिस पर चढ़कर 'मैडम' ने स्कूल में प्रवेश किया। गुरुवार की इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे अपनी क्षमता से अधिक भारी बेंच उठाकर गंदे पानी में रख रहे हैं और विशिष्ट शिक्षिका अफसाना परवीन बिना पैर भिगोए आराम से उन पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों से यह काम कई बार कराया गया।

मामले के तूल पकड़ने पर स्कूल की प्रधान शिक्षिका नीलिमा पाठक ने कहा कि शिक्षिका अफसाना की बायपास सर्जरी हुई है, उन्हें एलर्जी की समस्या है। इसलिए वह पानी में नहीं चल सकतीं। हालांकि, उन्होंने बच्चों से ऐसा काम कराने को गलत ठहराया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि सड़क और नाले की ऊंचाई स्कूल से ज्यादा होने के कारण परिसर में हमेशा जलजमाव रहता है। सड़क से स्कूल पहुंचने में करीब 15 मीटर तक पानी से गुजरना पड़ता है।

वहीं, डीपीओ (स्थापना) संदीप रंजन ने प्रधान शिक्षिका के माध्यम से आरोपित शिक्षिका अफसाना से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है।

शिक्षिका अफसाना से पक्ष लेने का प्रयास किया गया, पर संपर्क नहीं हो सका। जिला शिक्षा अधिकारी साहेब आलम ने बताया कि हमारे पास मिट्टी भराई या फिर किसी निर्माण कार्य के लिए कोई फंड नहीं है। स्कूल में होने वाले जलजमाव के समाधान को लेकर नगर परिषद जोगबनी के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रोहित यादव से अनुरोध किया गया है।

बिहार के अररिया जिले में जोगबनी स्थित प्राथमिक विद्यालय जूरबाड़ी में बच्चों के लगाए बेंच पर पानी पार करतीं शिक्षिका। सौ. वीडियो ग्रैब

संभल में सरकारी जमीन पर बनी मजार और इमामबाड़ा पर चले बुलडोजर

जागरण संवाददाता, संभल

- लेखपाल ने तहसीलदार न्यायालय को सौंपी थी जांच रिपोर्ट, सवा करोड़ रुपये है जमीन की कीमत, बसाए जाएंगे भूमिहीन व आवासहीन लोग

करीब पांच बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मजार और इमामबाड़ा को शुक्रवार दोपहर प्रशासन ने ध्वस्त कराए। छह घंटे में तीन बुलडोजर और एक मिनी पोकलेन मशीन लगाकर अवैध कब्जे तोड़े गए। कब्जामुक्त कराई गई जमीन पर भूमिहीन और आवासहीन लोगों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

जिले के मुकर्रबपुर में ग्राम समाज की बंजर भूमि में दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर लेखपाल ने दो जून को जांच रिपोर्ट तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह को सौंपी थी। 12 जून को तहसीलदार न्यायालय से बेदखली आदेश पारित हुआ। राजस्व विभाग की

संभल के मुकर्रबपुर में ग्राम समाज की भूमि पर बनी मजार पर चलता बुलडोजर। जागरण

टीम शुक्रवार पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे गांव पहुंची। बुलडोजरों से पहले अतिक्रमण की गई भूमि पर बनी चहारदीवारी को तोड़ा। फिर इमामबाड़े में बने निर्माण पर लगाए गए शटर और अन्य अवैध कब्जे हटाए गए। शाह मियां नाम वाली मजार को भी बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कियागया।

मुरादाबाद में सड़क पर बनी मजार गिराई गई

जासं, मुरादाबाद : हरिद्वार-देहरादून राजकीय राजमार्ग पर छजलैट में 58.40 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर बनी चांद शाह बाबा की मजार का अवैध हिस्सा शुक्रवार को गिरा दिया गया। प्रशासन के अनुसार, मजार सार्वजनिक उपयोग के रास्ते (श्रेणी-6) की भूमि पर थी और इससे यातायात में बाधा होने के साथ दुर्घटना की आशंका बढ़ रही थी।

Loot Blink
SATURDAY
WEEKEND
DHAMAKA!
MAST DEALS. BADI BACHAT!
SAVE MORE SPEND LESS!
100% REAL DEALS
LIMITED TIME OFFERS
BEST PRICES GUARANTEED
EASY RETURNS
SABSE BADI BACHAT!
UP TO
90% OFF
HUGE DISCOUNTS
TOP BRANDS • BEST QUALITY • LIMITED STOCK
LIMITED STOCK
JOIN KARO AUR LO SABSE BADI LOOT DEALS!
iPhone 13
128GB
₹59,900
₹5,399
91% OFF
YOU SAVE ₹54,501
SAMSUNG
32" HD Smart TV
89% OFF
YOU SAVE ₹22,301
realme
Narzo N55
(6GB+128GB)
₹13,999
₹799
94% OFF
YOU SAVE ₹13,200
boAt
Airdopes 141
₹2,990
₹249
92% OFF
YOU SAVE ₹2,741
Noise
Pulse 2 Smart Watch
₹4,999
₹349
93% OFF
YOU SAVE ₹4,650
ASUS
Vivobook 15
(i3 12th Gen, 8GB/512GB SSD)
₹40,990
₹4,499
89% OFF
YOU SAVE ₹36,491
ZEBRONICS
Headphones
₹1,499
₹169
89% OFF
YOU SAVE ₹1,330
WILDCRAFT
Backpack
₹1,999
₹149
93% OFF
YOU SAVE ₹1,850
PHILIPS
Trimmer
Series 3000
₹1,995
₹199
90% OFF
YOU SAVE ₹1,796
AGARO
Air Fryer 4.5L
₹6,999
₹699
90% OFF
YOU SAVE ₹6,300
SAMSUNG
980 500GB
NVMe SSD
₹6,999
₹6,400
91% OFF
YOU SAVE ₹599
PUMA
Men's Running Shoes
₹3,999
₹699
91% OFF
YOU SAVE ₹3,300
PORTABLE
Laptop Table
Foldable
₹1,299
₹129
90% OFF
YOU SAVE ₹1,170
boAt
Stone 650
Bluetooth Speaker
₹3,999
₹199
95% OFF
YOU SAVE ₹3,800
GREEN SOUL
Office Chair
Ergonomic
₹14,999
₹1,499
90% OFF
YOU SAVE ₹13,500
UPTO 90% OFF ON TOP BRANDS
PRICE DROP ALERTS BE THE FIRST TO KNOW
100% GENUINE PRODUCTS
FAST DELIVERY ACROSS INDIA
DEALS ITN BADHI, KI CHOOK GAYE TO PACHTAUGE!
ABHI JOIN KARO AUR LOOTNA SHURU KARO!
JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
Instant Deal Alerts
Exclusive Offers
Limited Stock Updates
CLICK HERE
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
Latest Deals & Offers
Price Drops Alerts
Limited Time Offers
CLICK HERE
SAVE TIME SHOP SMART
SAVE MONEY LIVE BETTER
SMART CHOICES. BRIGHTER FUTURE!
SHOP SMART. SAVE BIG. SHINE BRIGHT.
JOIN 1 LAKH+ SMART SHOPPERS & SAVE THOUSANDS EVERY MONTH!

रेवड़ियां बांटने के वादे पर चुनाव चिह्न जब्ती की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई का आग्रह

सीजेआइ ने कहा, अभी हमारे पास बहुत मामले,इस मामले में किया जा सकता है इंतजार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया जिसमें चुनाव से पहले अतार्किक रेवड़ियां बांटने का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त करने या उसका पंजीकरण रद करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची, वी. मोहना की पीठ को वकील एवं याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि उनकी जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को 2022 में ही नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने मामले को जल्द सुनवाई पर लगाने का आग्रह किया। उपाध्याय ने कहा, तत्काल सुनवाई के लिए पांच फरवरी को याचिका का जिक्र किया गया था। तब कोर्ट मार्च में इस पर सुनवाई को राजी हो गया था। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "अभी हमारे पास बहुत सारे मामले हैं। इस मामले में इंतजार किया जा सकता है।" उपाध्याय ने कहा, "इस मामले पर सुनवाई जरूरी है। एक समिति बनाई जानी है। " वकील कपिल सिब्बल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग का समर्थन किया।

सुप्रीम कोर्ट । फाइल

जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता से जुड़े मामले पर लिया स्वत: संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता व जीवन के अधिकार से जुड़े मामलों में न्यायिक तत्परता से संबंधित मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। यह मामला केरल की एक महिला से जुड़ा है, जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और उसने दवाओं की बहुत अधिक कीमतों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह अपने यहां लंबित इस मामले का जल्द निपटारा सुनिश्चित करें।

सोमनाथ भारती की चुनाव याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा,वह आप नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें फरवरी, 2025 के दिल्ली विस चुनावों में मालवीय नगर सीट से भाजपा के सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती दी गई है। इन चुनावों में उपाध्याय ने भारती को 2,131 वोटों के से हराया था। भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट के 17 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट में अपनी याचिका में भारती ने उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट तौर-तरीके अपनाने का आरोप लगाया था।

बेंगलुरु में पांच नगर निगमों के चुनाव की समय-सीमा बढ़ाई: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बेंगलुरु के पांच नगर निगमों में चुनाव कराने की समय-सीमा को 31 अगस्त से बढ़ाकर दिसंबर, 2026 कर दी। ग्रेटर बेंगलुरु अथारिटी के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि राज्य में एसआइआर की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूची को इस वर्ष नवंबर में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस तथ्य के मद्देनजर कोर्ट ने चुनाव कराने की समय-सीमा बढ़ा दी।

यलगार परिषद मामले के आरोपित की जमानत पर अगले हफ्ते सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 2018 के यलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में आरोपित वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए राजी हो गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया कि गाडलिंग साढ़े सात वर्षों से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर पहली बार 2023 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सुनवाई से पीछे हटने वालों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने पीठ से मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की।

भारतीय मिशनों में वीजा सेवाओं से जुड़े मामले में सुनवाई सोमवार को

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर, कैनबरा स्थित भारतीय मिशनों में कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए निजी कंपनियों को दी गई निविदा रद कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के कारण इन स्थानों पर वीजा व अन्य सेवाएं प्रदान करने में दिक्कत हो रही है। हाई कोर्ट ने सीपीवी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए निजी कंपनियों को दी गई निविदा रद करते हुए केंद्र को नए प्रस्ताव जारी कर नई बोलियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया था। मेहता ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नई निविदाएं जारी कर दी गई हैं, लेकिन कोई नई एजेंसी तत्काल कामकाज शुरू नहीं कर सकती। इसके परिणामस्वरूप ऐसी सेवाएं लगभग ठप पड़ने की स्थिति में हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्णय लेते समय केंद्र ने अज्ञात तुलनात्मक मानकों पर भरोसा किया, उद्देश्य मूल्यांकन मानदंडों के तहत अस्पष्ट कटौतियां कीं और असंगत अंकन अपनाया। ये कमियां सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता को चोट पहुंचाती हैं।

एनएचआरसी ने तेलंगाना सरकार से 'कलमा' विवाद पर रिपोर्ट मांगी

- 'सेवा न्यायस्थान फाउंडेशन' नाम के संगठन ने की है शिकायत
- हैदराबाद के विवादित स्कूल के बाहर पुलिस बल की भारी तैनाती

नई दिल्ली, आइएएनएस: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तेलंगाना सरकार को हैदराबाद के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के हिंदू छात्र को एक शिक्षिका द्वारा 'कलमा' पढ़वाने के विवाद में कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। हैदराबाद के सैदाबाद क्षेत्र के सक्सेस नामक निजी स्कूल में छात्र को स्कूल डायरी में होमवर्क गतिविधि के रूप में यह कार्य सौंपा गया था, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने गुरुवार को ही संबंधित शिक्षिका की सेवाएं समाप्त कर दी थीं, पर शुक्रवार को स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दरअसल, हिंदू छात्र पर 'कलमा' पढ़ने का दबाव डालने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को कहा, "हमें 'सेवा न्यायस्थान फाउंडेशन' नामक संगठन से एक शिकायत मिली है। इसमें कहा गया है कि हैदराबाद के एक निजी स्कूल में हिंदू छात्र को 'कलमा' याद करने का होमवर्क दिया जा रहा है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। हमने इस मामले में तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है। उचित कार्रवाई के निर्देश के साथ ही विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।" इससे पहले, जब छात्र के माता-पिता को शिक्षक द्वारा बच्चे को इस्लामी धार्मिक ग्रंथों को याद कराने के कथित प्रयास के बारे में पता चला, तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर विरोध दर्ज किया। माता-पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त व त्वरित कार्रवाई की मांग की, जो छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे थे।

प्रतीकात्मक

इधर, सक्सेस स्कूल के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। सुबह स्कूल परिसर सुनसान रहा, क्योंकि कोई छात्र या स्टाफ नहीं आया। गोशामहल के विधायक टी. राजा सिंह ने भी इस घटना की निंदा कर कहा, यह एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में हुआ। यह अत्यंत निंदनीय घटना है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बेंगलुरु-अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट में बम की झूठी धमकी, एफआइआर दर्ज

- अहमदाबाद जाने वाली उड़ान को पांच घंटे से अधिक समय तक रोका
- शौचालय में एक हस्तलिखित नोट मिला,लिखा था, "मत जाओ। बम है!

बेंगलुरु, एएनआइ : बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान को गुरुवार शाम बम होने की झूठी धमकी के बाद पांच घंटे से अधिक समय तक रोके रखा गया। बम होने की झूठी धमकी के मामले में शुक्रवार को एफआइआर दर्ज की गई है।

एयरलाइन के सूत्रों ने बताया कि इंडिगो की उड़ान 6ई 6423, जो शाम 8 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाली थी, नोट मिलने के बाद सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दी गई। प्रेट्र के अनुसार पुलिस ने बताया कि एक क्रू सदस्य को करीब 7:35 बजे आगे के शौचालय में हस्तलिखित नोट मिला, जिसमें लिखा था, "कृपया मत जाओ। बम है!" एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, केआइएएल एयरपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत में एयरलाइन ने कहा, इस धमकी ने यात्रा में व्यवधान उत्पन्न किया और यात्रियों, क्रू और एयरलाइन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं। हम इस घटना की जांच में आपकी मदद का अनुरोध करते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने व उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए गहन जांच करने की मांग करते हैं। एयरलाइन के सूत्रों ने बताया,"इंडिगो की उड़ान 6ई 6423 (बीएलआर-एएमडी) में झूठा बम नोट पाया गया। सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया गया।" एक व्यापक सुरक्षा जांच और सभी अनिवार्य सुरक्षा जांचों के पूरा होने के बाद विमान को संचालन के लिए मंजूरी दे दी गई। यह उड़ान अंततः शुक्रवार को सुबह 1:21 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। झूठे संदेश के स्रोत के बारे में और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

पुरी में रथयात्रा का पहला चरण संपन्न, गुंडिचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ

जागरण संवाददाता, पुरी

- एक सप्ताह तक भगवान भाई-बहनों समेत गुंडिचा मंदिर में ही दर्शन देंगे
- पुरी क्षेत्र में नौ दिनों तक मेले और उत्सव का रहेगा वातावरण

ओडिशा के पुरी में गुरुवार को शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ शुक्रवार अपराह्न अपने गंतव्य स्थान गुंडिचा मंदिर पहुंच गए। यह स्थान भगवान के मुख्य मंदिर से 2.6 किमी दूर है। इसी के साथ नौ दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला चरण पूरा हुआ। परंपरा के अनुसार, भगवान की मूर्तियां शुक्रवार रात भर मंदिर के बाहर अपने रथों पर ही विराजमान रहीं। शनिवार शाम उन्हें गुंडिचा मंदिर ले जाया जाएगा। इससे पूर्व रथ पर भगवान के विग्रहों की विशेष पूजा-अर्चना की गई। विशेष आरती और भजन-कीर्तन के आयोजन भी रातभर चलते रहे।

बता दें कि गुंडिचा मंदिर महाप्रभु और उनके भाई-बहनों की मौसी का घर है। यह मंदिर ही उनका जन्मस्थान माना जाता है। साल में एक बार (रथयात्रा उत्सव के अवसर पर) भगवान अपने भाई-बहनों के साथ यहां पहुंचते हैं। अगले शुक्रवार 24 जुलाई को भगवान गुंडिचा मंदिर से रथ पर सवार होकर वापस अपने धाम (श्रीजगन्नाथ मंदिर) पहुंचेंगे। वापसी रथयात्रा को 'बहुदा' यात्रा कहा जाता है। इस दौरान पूरे पुरी क्षेत्र में नौ दिनों तक मेले और उत्सव का माहौल रहेगा। शनिवार से लेकर अगले एक सप्ताह तक भगवान अपने भाई-बहनों समेत गुंडिचा मंदिर में ही दर्शन देंगे।

पुरी में गुंडिचा मंदिर पहुंचने पर भगवान जगन्नाथ का रथ के ऊपर दर्शन-पूजन करते श्रद्धालु। जागरण

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने कहा कि गुरुवार को 'पहंडी' प्रक्रिया (भगवान के विग्रहों को विधि-विधान के साथ पूजा के बाद मंदिर से लाकर रथ पर विराजमान कराने का अनुष्ठान) में देरी के कारण तीनों रथ गुरुवार को गुंडिचा मंदिर नहीं पहुंच सके। परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद रथों को नहीं खींचा जा सकता है। इस कारण शाम में रथ खींचने का काम रोक दिया गया। भगवान ने अपने-अपने रथों पर ही रातभर रास्ते में विश्राम किया। यहां पूरी रात श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। श्रद्धालु रातभर रथों के सामने भजन-कीर्तन आरती व पूजन करते रहे। शुक्रवार सुबह फिर रथयात्रा शुरू की गई, जो अपराह्न तक चली।

फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' रिलीज को अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ यात्रा के उत्सवों के बाद 28 जुलाई या उसके बाद एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा, यह फिल्म एक वेब सीरीज पर आधारित है, जो पहले ही यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसके प्रदर्शन के लिए मंजूरी दी है। फिल्म निर्माताओं ने उड़ीसा हाई कोर्ट के 15 जुलाई के आदेश को चुनौती दी, जिसने एले एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड को फिल्म रिलीज करने से रोका था। राज्य की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यात्रा गुरुवार को ओडिशा व देश के अन्य हिस्सों में शुरू हो चुकी है। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित करने से इन्कार करते हुए 17 जुलाई को फिल्म की रिलीज का निर्देश देने से मना कर दिया। कहा,"रथ यात्रा समाप्त होने के बाद आप फिल्म रिलीज कर सकते हैं।"

कर्नाटक में एकतरफा प्रेम में नर्स की बस अड्डे पर सरेआम हत्या

- आरोपित को पुलिस ने मंगलुरु से किया गिरफ्तार
- मृत युवती लावण्या का दूर का रिश्तेदार है आरोपित

मंगलुरु, प्रेट्र: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल में बीसी रोड स्थित बस अड्डे पर गुरुवार शाम 21 वर्षीय लावण्या नामक नर्स की सरेआम धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में एकतरफा प्यार का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को मंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान जिले की बेलथंगडी तालुका के ओदिलनाल निवासी चेतन के रूप में हुई है। नर्स की हत्या के बाद आरोपित ने चूहे मारने की दवा खा ली थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दक्षिण कन्नड़ के एसपी अरुण के. ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपित मृत युवती का दूर का रिश्तेदार है। वह युवती से एकतरफा प्रेम करता था। गुरुवार को बंटवाल तालुका के उली गांव के काक्यापदवु निवासी लावण्या काम से लौट रही थी। वह बस में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी चेतन ने उसका रास्ता रोक लिया। घबराकर लावण्या भागी पर आरोपित ने उसका पीछा कर बस अड्डे पर ही उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीच-बचाव करने का प्रयास करने वाले लोगों को भी आरोपित ने धमकाया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया।

प्रतीकात्मक

जहां कभी पढ़ाया जाता था हिंसा और बंदूक का पाठ, वहां पहली बार गूंजी स्कूल की घंटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नारायणपुर

- माओवादी हिंसा के खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में प्रशासन की दस्तक
- नदी-नाले और पहाड़ पार कर बाइक से पहुंचीं कलेक्टर नम्रता जैन

उफनते नाले, बारिश से भीगी पगडंडियां, पहाड़ों से लिपटे बादल और घने जंगल... छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ की यह दुर्गम राह दशकों तक प्रशासन की पहुंच से लगभग दूर रही, लेकिन शुक्रवार को इन्हीं रास्तों पर एक बाइक उम्मीद की नई किरण लेकर बढ़ी। सुरक्षाबलों के जवान के पीछे बैठी नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन नदी-नालों, पहाड़ों के पार करीब 100 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर कोहकापार पहुंचीं। यह सिर्फ एक प्रशासनिक दौरा नहीं था, बल्कि उस गांव तक शिक्षा की पहली दस्तक थी, जहां आज तक किसी बच्चे ने स्कूल की घंटी नहीं सुनी थी। पहली बार गांव में पाठशाला खुली, घंटी बजी और नन्हे हाथों में किताबें थमाईं गईं।

अबूझमाड़ के कोहकापार में नवस्थापित प्राथमिक विद्यालय के पहले दिन बच्चों को घोटूल में पढ़ातीं कलेक्टर नम्रता जैन। नईदुनिया

कलेक्टर ने विद्यालय के पहले दिन 21 बच्चों, 11 छात्राओं और 10 छात्रों का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। उन्हें किताबें दीं और फिर स्वयं बच्चों को पढ़ाया। यह पूरा अभियान जिला प्रशासन के 'स्कूल केइंता' मिशन का हिस्सा है। इस पहल के जरिये अब तक दो हजार से अधिक बच्चों को स्कूलों और छात्रावासों से जोड़ा जा चुका है। कोहकापार में प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में मानी जा रही है। माओवादियों ने इस क्षेत्र में 458 स्कूलों को बंद करवा दिया था। अब वहां फिर पढ़ाई लौट रही है।

आंध्र में कोरोना के 12 मामले सामने आए, 26 जून से अब तक 4 मौतें

अमरावती, एएनआइ: आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 26 जून से 16 जुलाई के बीच राज्य में 12 कोविड-19 संक्रमणों की पुष्टि की है। राज्य सरकार ने मरीजों के बीच प्रचलित विशेष वायरस वेरिएंट की पहचान के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी (एनआइवी) को पांच नमूने भेजे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये मामले कडप्पा, गुंटूर, विशाखापत्तनम और काकीनाडा समेत विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं और स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की क्लस्टरिंग का कोई सुबूत नहीं है। केजीएच अस्पताल की अधीक्षक डा. वाणी ने बताया कि विशाखापत्तनम में एक कोविड-19 पाजिटिव मामला दर्ज किया गया है। मरीज ने कुछ दिन पहले सामान्य चिकित्सक से उपचार के लिए परामर्श किया था।

कोविड-19 के लक्षणों को देखते हुए डाक्टर ने मरीज को परीक्षण के लिए एक निजी प्रयोगशाला में भेजा। निजी प्रयोगशाला द्वारा संक्रमण की पुष्टि के बाद अधिकारियों ने उसी नमूने को केजीएच अस्पताल में सत्यापन के लिए भेजा, जहां परीक्षण परिणाम ने फिर से कोविड-19 की उपस्थिति की पुष्टि की। आंध्र में कोविड-19 के 12 मामले दर्ज किए गए हैं और जीनोम अनुक्रमण के लिए पांच नमूने पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी को भेजे गए हैं। एक जुलाई से अब तक भारत में कुल 339 कोविड-19 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक जुलाई से अब तक भारत में 339 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें केरलम 115 मामलों के साथ राज्यवार आंकड़ों में सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली में 18-18, और राजस्थान में 12 मामले हैं, जबकि शेष मामले अन्य राज्यों में हैं।

प्रकृति, रोमांच और शैलचित्रों का साक्षात्कार, टाटामारी की यात्रा को बनाएगा यादगार

घाटी की सर्पीली सड़कें, बादलों से घिरा हिल स्टेशन, झरने और प्राचीन शैलचित्र इस सफर को बनाते हैं खास

यात्रा

विनोद सिंह • नईदुनिया

जगदलपुर: बारिश के मौसम में बस्तर का जंगल पर्यटकों को आकर्षित करता है। दरअसल, केशकाल घाटी की सर्पीली सड़कें, बादलों से घिरा टाटामारी हिल स्टेशन, झरने, प्राचीन शैलचित्र इसको खास बनाते हैं। रायपुर से शुरू होने वाला यह तीन दिन का बस्तर मानसून सर्किट प्रकृति, रोमांच, इतिहास व स्थानीय स्वाद का अद्भुत अनुभव कराता है।

टाटामारी : प्रकृति का सान्निध्य और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद: पहले दिन रायपुर से 180 किलोमीटर दूर फूलों की घाटी केशकाल की सर्पीली घुमावदार सड़क से यात्रा रोमांचित और पर्यटकों की जिज्ञासा को भी बढ़ाती है। केशकाल से तीन किलोमीटर दूर स्थित है प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल 'टाटामारी हिल स्टेशन'। हर मौसम में टाटामारी का सौंदर्य अलग-अलग श्रृंगार के साथ लुभावना नजर आता है। यहां मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य, जंगल ट्रैकिंग का रोमांच तथा वीआइपी काटेज, वुडन काटेज, शयनगृह और टेंट में आरामदायक सुविधाएं पर्यटकों को नया अनुभव करती हैं। पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद इस यात्रा को और यादगार बना देता है। यहां नीला आसमान मानो छत बन जाता है। बादल पहाड़ियों के ऊपर तैरते से दिखाई देते हैं और हरे-भरे पेड़ प्रकृति का अनुपम श्रृंगार रचते हैं। झरनों की ध्वनि, फूलों पर मंडराती रंग-बिरंगी तितलियां और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों का मन और आंखों दोनों को सुकून से भर देती है। केशकाल इको पर्यटन क्षेत्र में टाटामारी सहित आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जहां पर्यटक भ्रमण कर सकते हैं।

लिंगोदरहा : शैलचित्रों में दिखती है प्राचीन संस्कृति: आप दूसरे दिन टाटामारी से 17 किमी दूर बावनीमारी जा सकते हैं। यह स्थान लिंगोदरहा जलप्रपात व शैलचित्रों के लिए विशेष पहचान रखता है। यहां के शैलचित्र प्राचीन सभ्यताओं के जीवन, संस्कृति और विश्वासों की सजीव झलक प्रस्तुत करते हैं। टाटामारी से आठ किमी दूर गढ़धनोरा पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यहां पांचवी-छठीं सदी का प्राचीन शिवलिंग, विष्णु मंदिर, प्राचीन मूर्तियां और बावड़ी है। यहां का वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। धनोरा की पहाड़ी गुफाओं में भी दुर्लभ शैलचित्र सुरक्षित हैं। इनको देखने में समय कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता।

होनहेड़ जलप्रपात, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं • वन विभाग

यात्रा की यादों के साथ लोग यहां के झरनों का सौंदर्य करते हैं कैमरों में कैद

आप तीसरे दिन टाटामारी से 32 किलोमीटर दूर स्थित कुंवेमारी गांव जा सकते हैं। यह जगह अपने सीढ़ीनुमा स्वच्छ झरनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहां गिरते जल की ध्वनि, चारों ओर फैली हरियाली और वातावरण पर्यटकों को प्रकृति के बेहद करीब होने का अहसास कराते हैं। होनहेड़, उपरबेदी, उमरादाह, मुत्ते खडका, कटुलकासा जैसे जलप्रपात के मनोहारी दृश्य पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। सेल्फी के दौर में लोग यहां पहुंचते ही कैमरे निकाल लेते हैं और अलग-अलग एंगिल से फोटो खींच कर यात्रा की यादों को कैद कर में जुट जाते हैं।

बस्तर में कोंडागांव जिले का टाटामारी हिल स्टेशन, जहां बादल तैरते हुए से नजर आते हैं • वन विभाग

कैसे पहुंचे और कहां रुकें

जगदलपुर से 110 किमी, रायपुर से 180 किमी दूर सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। रायपुर तक रेल और हवाई सेवा उपलब्ध है, जबकि जगदलपुर रेल, विमान और सड़क मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। टाटामारी में काटेज, जबकि केशकाल में होटल उपलब्ध हैं। कोंडागांव और कांकेर में भी ठहरने व भोजन की बेहतर सुविधाएं हैं। इन दोनों शहरों से केशकाल-टाटामारी इको टूरिस्ट सर्किट घूमने के लिए निजी वाहन भी आसानी से मिल जाते हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

पीओएसएच एक्ट की समीक्षा कर रहा महिला आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को बताया कि आयोग 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम' (पीओएसएच एक्ट, 2013) के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहा है। इस पर देशव्यापी विचार-विमर्श पूरा होने के बाद आयोग एक महीने में केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। रहाटकर ने बताया, शनिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग पीओएसएच पर एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श का आयोजन कर रहा है। इससे पहले विचार-विमर्श के चार क्षेत्रीय आयोजनों में हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। उन क्षेत्रीय सुझावों और शनिवार के राष्ट्रीय विचार-विमर्श में मिलने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, हम पूरे दिन इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि और क्या करने की आवश्यकता है। उसके बाद सिफारिशों का एक मसौदा तैयार किया जाएगा।

दैनिक जागरण

मनुष्य का मन उसके जीवन की दशा-दिशा निर्धारित करता है

नागरिकता का प्रश्न

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के समय वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाने और उन्हें कथित तौर पर सरकारी योजनाओं से वंचित करने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, उससे भ्रम पूरी तौर पर दूर होना कठिन ही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा ही कहा था, लेकिन तब उसने यह भी जोड़ा था कि आयोग मतदाता सूची बनाते या उसे संशोधित करते समय नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है। उसने ऐसी टिप्पणी इसलिए की थी, क्योंकि चुनाव आयोग को यह देखना होता है कि मतदाता भारतीय नागरिक है या नहीं? उसे यह देखने का अधिकार इसीलिए दिया गया, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का हक भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। निःसंदेह चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं कि वह किसी की नागरिकता का निर्धारण करे, क्योंकि नागरिकता का निर्धारण तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत होता है और इसके अनुसार जन्म, वंश, भारत में लंबे समय से रहने आदि के आधार पर नागरिकता तय होती है।

समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों जब यह बात सामने आई कि पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज मात्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं, तब भी यह बहस उठी थी कि आखिर किसी की नागरिकता का निर्धारण किस प्रमाण पत्र से होगा? इस प्रश्न का कोई सीधा-सरल उत्तर तब तक नहीं मिल सकता, जब तक लोगों को नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। ध्यान रहे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पैन, राशन कार्ड आदि भी नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं। मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाणन नहीं करता। चुनाव आयोग की एसआइआर प्रक्रिया इसीलिए जटिल है, क्योंकि लोगों के पास ऐसे दस्तावेज बहुत कम हैं, जिनसे उनकी नागरिकता का आसानी से प्रमाणन हो जाए। अपने देश की एक अन्य समस्या यह है कि यदि कोई राशन कार्ड, आधार आदि बनवा ले तो फिर वह हर तरह के दस्तावेज हासिल कर सकता है- मतदाता पहचान पत्र से लेकर पासपोर्ट तक। यह किसी से छिपा नहीं कि तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ऐसा कर रखा है। यदि यह समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के यह कहने से समस्या का समाधान हो जाएगा कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता तो यह सही नहीं। ऐसी किसी टिप्पणी से एसआइआर की प्रक्रिया भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि चुनाव आयोग को तो यह सुनिश्चित करना ही होगा कि मतदाता भारतीय नागरिक हो।

हरेला का संदेश

प्रकृति एवं हरियाली को समर्पित लोकपर्व हरेला के साथ उत्तराखंड में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो गई। अभियान के तहत प्रदेशभर में दस लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वन एवं ग्राम पंचायतों के साथ तमाम सरकारी विभाग और स्वयं सेवी संस्थाएं सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से भी 'मिशन पोषण संकल्प' और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्येय यही है कि धरती हरी-भरी रहे और हवा-पानी स्वच्छ एवं निर्मल। वैसे तो उत्तराखंड में 71 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि के अंतर्गत आता है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 45 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर वनावरण है, लेकिन ढांचागत विकास एवं बढ़ते शहरीकरण के चलते बड़े पैमाने पर पेड़ काटे भी जा रहे हैं। इसकी भरपाई नए पौधे रोपकर ही हो सकती है। इसीलिए सरकार का व्यापक पौधारोपण पर विशेष जोर है। इसके लिए हर साल हरेला पर्व के निमित्त 15 दिन तक बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाता है। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण रोपे गए पौधों का संरक्षण है, जिस पर शायद ही कभी गंभीरता से ध्यान दिया गया हो। पौधे रोपते समय इनके संरक्षण का संकल्प तो लिया जाता है, लेकिन फिर बात आई-गई हो जाती है। इसी का नतीजा है कि रोपे गए पौधों का बहुत कम प्रतिशत ही जीवित रह पाता है।

उत्तराखंड सरकार भी मिशन पोषण संकल्प और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रही है

बार-बार के चुनावी भंवर से निकले देश

डा. रामानंद शर्मा

'एक देश-एक चुनाव' को किसी दलगत राजनीति के चश्मे से देखने के बजाय इसे राष्ट्र-निर्माण के नजरिए से देखा जाना चाहिए

अवधेश राजपूत

इस मानसून सत्र की दहलीज पर 'एक देश-एक चुनाव' को लेकर देश में जैसी बहस छिड़ी है, वैसी किसी अन्य सुधार पर लंबे समय से नहीं देखी गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि एक देश-एक चुनाव को लेकर कोई विधेयक संसद के इस सत्र में आएगा या नहीं, लेकिन यदि आता है तो उसे लेकर विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के विचार को खारिज करते चले आ रहे हैं। मूल प्रश्न यह नहीं है कि देश में चुनाव कितनी बार होते हैं, यह है कि चुनी हुई सरकारें जनता को कैसा शासन दे पाती हैं। यही वह बुनियादी आधार है, जिसके केंद्र में यह पूरा प्रस्ताव खड़ा है। वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को खंगाल रही है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न पक्षों से संवाद जारी है। इसे केवल चुनाव का कैलेंडर ठीक करने की यांत्रिक कसरत समझना भूल होगी। यह भारतीय शासन-व्यवस्था को बुनियादी तौर पर कसने और उसे नया स्वरूप देने का ऐतिहासिक अवसर है।

एक साथ चुनाव लोकतंत्र का विकल्प नहीं, बल्कि हमारी चुनावी प्रक्रिया का अनिवार्य शोधन है। बीते एक दशक में शासन की रफ्तार, डिजिटल गवर्नेंस और बुनियादी ढांचे के निर्माण को जिस तरह नीति की निरंतरता से गति मिली है, उसी सिलसिले में इस सुधार का दस्तक देना स्वाभाविक है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट यह है कि देश एक स्थायी चुनावी भंवर में फंस चुका है। पिछले पांच वर्षों का रिकार्ड गवाह है कि हर साल किसी न किसी बड़े राज्य में चुनावी मरोड़ उठती है और आचार संहिता का पहरा बैठ जाता है। नतीजा यह कि शासन का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के काम के बजाय चुनावी बंदोबस्त में होम हो जाता है। इसका सीधा असर सार्वजनिक निवेश और नीतिगत फैसलों पर पड़ता है। कोविंद समिति की रिपोर्ट ने साफ रेखांकित किया है कि इन बिखरी हुई चुनावी तारीखों के कारण देश प्रशासनिक और आर्थिक अनिश्चितता की भारी कीमत चुका रहा है। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, नई विकास योजनाएं, टेंडर और बड़े फैसले फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार चाहिए, लेकिन बार-बार लगने वाला यह राजनीतिक ब्रेक उनकी लागत बढ़ाता है और समय लील जाता है।

देश का करदाता अपनी गाढ़ी कमाई से जिस प्रशासनिक तंत्र को विकास के लिए टैक्स देता है, वह भी मशीनरी महीनों चुनावी फेर में उलझी रहती है। इसकी सबसे करारी चोट हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ती है। चुनावों की घोषणा होते ही लाखों शिक्षकों और सुरक्षा बलों को उनके मूल दायित्वों से हटाकर ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप हो जाती है। बच्चों के इस नुकसान की भरपाई कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। जनता को निर्बाध और सुचारु नागरिक जीवन मिलना ही इसकी असली कसौटी है। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि किसी राज्य में चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकताएं बदलने को बाध्य हो जाते हैं।

यदि हम भारतीय चुनावी इतिहास को देखें तो 1951 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। यह समकालिक व्यवस्था इसलिए समाप्त नहीं हुई कि वह नाकाम थी, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता और समयपूर्व विघटनों के कारण उसका क्रम टूटा। इसलिए यह विचार किसी एक सरकार की तात्कालिक उपज नहीं है। चुनाव आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग वर्षों से इसे एक जरूरी सुधार के रूप में रेखांकित करते रहे हैं। स्वयं चुनाव आयोग आवश्यक संवैधानिक और प्रशासनिक तैयारी के साथ इसे संभव मानता है। ऐसे में यह बहस केवल राजनीतिक नफा-नुकसान की नहीं, देश की संस्थागत तत्परता की है। यह कोई नया या अनजाना प्रयोग नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की मूल चुनावी व्यवस्था को आज की परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्स्थापित करने का एक गंभीर प्रयास है।

हालांकि इस सुधार के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी उठाई जा रही हैं। मुख्य विपक्षी दलों और क्षेत्रीय ताकतों का तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दे प्रांतीय चुनावों पर हावी हो जाएंगे। उनका मानना है कि इससे स्थानीय सरोकार हाशिए पर चले जाएंगे और बहुदलीय ढांचा कमजोर पड़ सकता है। हालांकि हमारा चुनावी इतिहास यह दिखाता है कि भारतीय मतदाता कहीं अधिक परिपक्व है। यदि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों को दबा देते तो अनेक राज्यों में मतदाता एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा में अलग-अलग दलों को जनादेश क्यों देते? आखिर अब भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। हमारी जनता राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकताओं के फर्क को बखूबी समझती है। इसका सबसे कठिन हिस्सा इसके कानूनी पहलुओं से जुड़ा है। यदि कोई राज्य सरकार दो साल में ही गिर जाए या केंद्र में त्रिशंकु सदन की स्थिति बन जाए तो उस स्थिति में इस समकालिक चक्र को कैसे बचाया जाएगा? विधि आयोग और उच्चस्तरीय समिति के अनुसार, ऐसी स्थिति में होने वाले मध्यावधि चुनाव केवल पिछले सदन के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होने चाहिए। यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या मतदाता केवल दो साल के कार्यकाल के लिए फिर से मतदान करने के लिए तत्पर होंगे?

असली चुनौती केवल एक बार साथ चुनाव कराने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता के बीच इस पूरी व्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने की है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के वृहद राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीतियों की निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता सबसे पहली शर्त है। जब देश निरंतर चुनावी चक्रों के भंवर से मुक्त रहेगा, तभी हम बुनियादी ढांचे के निर्माण और बड़े आर्थिक सुधारों को सफलता से जमीन पर उतार पाएंगे। इसीलिए 'एक देश-एक चुनाव' को भी किसी दलगत राजनीति के चश्मे से देखने के स्थान पर इसे राष्ट्र-निर्माण के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसमें ही सबका हित है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

अतिवाद की हदों को पार करता स्त्रीवाद

क्षमा शर्मा

जिस अमेरिका और यूरोप से स्त्रीवादी का विचार चला था, वहां की महिलाएं ही अब इस पर सवाल उठाने लगी हैं

सिया-केतन प्रकरण से सबक सीखे समाज। फाइल

हाल में अमेरिका में हुए कुछ सर्वे और रिपोर्ट पढ़ी। उनमें बताया गया है कि वहां अधिकांश स्त्रियां पुरुषों से बराबरी चाहती हैं। समान वेतन और समान सुविधाओं को पसंद करती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खुद को फेमिनिस्ट या स्त्रीवादी नहीं कहलाना चाहतीं। बहुत से पुरुष भी स्त्रियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं, पर वे इस शब्द से परहेज करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? स्त्रियों का कहना है कि स्त्रीवाद ने शुरुआत में जो अधिकार मांगे थे, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि वे कमोबेश पूरे हो चुके हैं। जहां नहीं हुए हैं, वहां इन पर सोचा जा रहा है। इसलिए अब पुराने रागों का अलाप बंद होना चाहिए। वे फेमिनिज्म के अतिवादी रूप (रेडिकल फेमिनिज्म) से परेशान हैं। उनका कहना है कि हमेशा पुरुषों को शिकारी और अपने को शिकार दिखाना गलत अवधारणा है। पुरुष अच्छे भी हो सकते हैं और स्त्रियां बुरी भी हो सकती हैं। वे यह भी कहती हैं कि किसी दफ्तर में अधिकारी बनकर घंटों काम करने और दफ्तर की परेशानियों को झेलने से उनका जीवन आसान नहीं, बहुत कठिन हुआ है।

यही नहीं, फेमिनिज्म द्वारा स्त्री की हर पुरानी भूमिका की आलोचना की जाती है, जैसे खाना बनाने, बच्चे पालने, घर की देखभाल करने आदि को पिछड़ापन और शोषण का कारक बताया जाता है। यह सोच उन स्त्रियों को छोटा करता है, उनका अपमान करता है, जो इन भूमिकाओं में रहना चाहती हैं। इन स्त्रियों का कहना है कि यदि वे अपनी मर्जी से ये सब करना चाहती हैं तो कोई और उनका मजाक कैसे उड़ा सकता है? उन्हें मुख्यधारा से कटा हुआ कैसे कह सकता है? यह भी सच है कि नौकरीपेशा स्त्रियां एक तरह से खुद को सैंडविच की तरह से महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें घर भी देखना होता है और दफ्तर में भी काम करना होता है। स्त्रियों का कहना यह भी है कि मेनस्ट्रीम फेमिनिस्ट स्त्रियों को हमेशा कमजोर साबित करती रहती हैं, जबकि उन्हें स्त्रियों की तरह-तरह की भूमिकाओं, उन्हें निभाने की उनकी ताकत और उनकी क्षमताओं पर बात करनी चाहिए। यही नहीं, पुरुषों को हमेशा नकारात्मक रूप में पेश करना भी समाज की कोई भलाई नहीं करता, क्योंकि अधिकांश पुरुष भी परिवार के लिए नौकरी या अच्छे काम करते हैं। उनकी इन भूमिकाओं की सराहना आखिर क्यों नहीं की जानी चाहिए?

अमेरिका में चलने वाले ट्रेडिशनल वाइफ मूवमेंट में शामिल स्त्रियां यह तक कहती हैं कि यदि वे अपने पति के लिए खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं तो यह उनका चुनाव है, पसंद है। दूसरी महिला इस पर सवाल उठाने वाली कौन होती है। इन बातों को पढ़ते हुए यही लगा कि कोई भी विमर्श शुरुआत में सहानुभूति से शुरू होता है। फिर धीरे-धीरे उसे ताकत प्राप्त होती है। मीडिया, जनता और सरकारों का समर्थन मिलता है तो फिर वह गुर्राने लगता है। सबसे सवाल पूछने और असहमत होने का अधिकार तो मांगता है, मगर यह नहीं देखना चाहता कि कोई उससे असहमत हो। इन दिनों अपने देश में चल रहे कई विमर्शों की यही सच्चाई है। आप जैसे ही उनसे असहमत होते हैं, सवाल पूछते हैं तो फौरन तरह-तरह के अपशब्दों के साथ आप पर हमला बोल देते हैं। यह एक तानाशाहीपूर्ण रवैया है, क्योंकि तानाशाहियों में ही सवाल पूछना मना होता है। यदि कोई विमर्श सवालों से बचने लगे, सवाल पूछने वालों पर ही आक्रमण करने लगे, गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो माना जाना चाहिए कि उसका अंत करीब है। यों भी इतिहास से अब तक देखें तो किसी भी विचार-विमर्श की उम्र 70-100 साल से अधिक नहीं होती, क्योंकि कोई भी विचार और विमर्श अपना प्रतिपक्ष साथ लेकर आता है। जिस अमेरिका और यूरोप से स्त्रीवादी विचार चला था, वहां ही अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन भी अतिवादी स्त्रीवाद का बड़ा आलोचक है। ट्रंप का कहना है कि रेडिकल फेमिनिज्म और एलजीबीटीक्यू की अमेरिका में कोई जगह नहीं है।

अपने देश में भी स्त्रीवादी विचार की अति अगर देखनी हो तो हाल में हुए सिया-केतन मामले में देखी जानी चाहिए। महिलाओं के एक वर्ग ने इंटरनेट मीडिया में जोर-शोर से कहा कि ऐसे पुरुषों को यही सजा मिलनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े दिखा कहने लगीं कि बड़ी संख्या में पुरुष स्त्रियों को मारते रहे हैं। ऐसे में यदि किसी स्त्री ने पुरुष को मार दिया तो क्या गलत किया। वे अपने साथ हुए अपराधों का बदला ले रही हैं। ऐसी स्त्रीवादियों से कहना चाहूंगी कि चाहे कोई स्त्री मरे या पुरुष, किसी की भी हत्या हो, वह दुखद है। यदि आप जीवन दे नहीं सकतीं तो लेने का क्या अधिकार। किसी को भी किसी की हत्या का अधिकार नहीं है। किसी भी तरह उसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। आखिर केतन की हत्या से पुरुष और स्त्रियां सभी परेशान हुए। याद रखें कि कोई पुरुष या स्त्री अकेली नहीं होती, उसके परिवार में स्त्री-पुरुष दोनों होते हैं। किसी हत्या को वैधता प्रदान करना और उसे सेलिब्रेट करना बताता है कि हम कितना अनैतिक हो गए हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

पवित्रता

आज का मनुष्य बाहरी सौंदर्य, आकर्षक व्यक्तित्व और भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन की सफलता एवं सौंदर्य मान बैठा है, जबकि वास्तविक सौंदर्य न चेहरे की चमक में है और न ही वैभव के प्रदर्शन में। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य पवित्रता है। पवित्रता का अर्थ है- विचारों की शुद्धता, भावों की निर्मलता और कर्मों की श्रेष्ठता। यह पवित्रता आत्मानुशासन, संयम और सदाचार से विकसित होती है। यह वह आंतरिक शक्ति है, जो मनुष्य के विचारों, व्यवहार, चरित्र और संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। मनुष्य का बाह्य रूप चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, यदि वह स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, लोभ, छल, कपट और परिग्रह से मुक्त नहीं है तो उसका व्यक्तित्व कभी भी पवित्र नहीं बन सकता। जो व्यक्ति क्रूर कर्म करता है, असत्य का सहारा लेता है, चोरी करता है, इंद्रियों का दास बनकर जीता है, जिसकी चेतना संग्रह और मोह में डूबी रहती है, जिसका दृष्टिकोण मिथ्या है तथा जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, वह आंतरिक सौंदर्य से वंचित रहता है। ऐसे व्यक्ति का आभामंडल कभी निर्मल नहीं हो सकता।

भगवान महावीर ने कहा-मनुष्य चलते, बैठते, सोते और जागते हर क्षण संयम और जागरूकता का पालन करे। यह आत्मशुद्धि का आधार है। जब हमारी दृष्टि, वाणी और श्रवण पवित्र होते हैं, तब हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व सौंदर्यमय बन जाता है। हम पवित्रता की साधना को जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। पवित्रता कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं, सतत जागरूकता और संकल्प का परिणाम है। यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ अपने विचारों, व्यवहार और संबंधों को शुद्ध बनाने का प्रयास करें तो न केवल हमारा जीवन सुंदर बनेगा, बल्कि समाज और राष्ट्र भी नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों से आलोकित होगा।

ललित गर्ग

भविष्य की पटरी पर भारत

देवेंद्रराज सुथार

हाइड्रोजन ट्रेन उस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें परिवहन, उद्योग और ऊर्जा नीति एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं

भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन-सेल आधारित ट्रेन का परिचालन केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं है। यह ऊर्जा नीति, औद्योगिक रणनीति और जलवायु प्रतिबद्धताओं के संगम पर खड़ा एक ऐसा प्रयोग है, जिसकी सफलता रेलवे से कहीं आगे भारत की विकास यात्रा को प्रभावित कर सकती है। ईंधन-सेल तकनीक में हाइड्रोजन और आक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है। परिचालन के दौरान केवल जल और ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। हालांकि इसका पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रकार किया गया है। यदि इसे सौर, पवन अथवा अन्य नवीकरणीय स्रोतों से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यही कारण है कि इसे भविष्य की स्वच्छ औद्योगिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

इसी दृष्टि से भारत ने 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना ही नहीं, बल्कि भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। सरकारी आकलनों के अनुसार इससे लगभग 1.25 लाख मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की मांग उत्पन्न होगी, बड़े निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। इसलिए यह मिशन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा की बचत और सामरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जर्मनी, फ्रांस, चीन और जापान जैसे देश पहले ही इस तकनीक के विकास पर निवेश कर रहे हैं। भारत के लिए चुनौती केवल हाइड्रोजन ट्रेन चलाना नहीं है, उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, भंडारण, परिवहन, रीफ्यूलिंग, ईंधन-सेल निर्माण और सुरक्षा मानकों सहित पूरी औद्योगिक मूल्य श्रृंखला विकसित करना है। यदि इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित होती है तो भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी बन सकता है।

हाइड्रोजन ट्रेन का वास्तविक महत्व एक रेलगाड़ी से कहीं बड़ा है। यह उस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें परिवहन, उद्योग और ऊर्जा नीति एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। पहली ट्रेन चल चुकी है, अब सफलता इस पर निर्भर करेगी कि भारत इस पहल को प्रतीकात्मक उपलब्धि तक सीमित रखता है या इसे स्वदेशी अनुसंधान, औद्योगिक नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बनाता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि

संपादकीय 'घुसपैठियों के मददगार' पढ़ा। देश की सीमाओं की सुरक्षा केवल सीमा सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति, संगठन या गिरोह अवैध रूप से विदेशी नागरिकों की घुसपैठ में सहयोग करता है, उन्हें फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराता है या उनके रहने-बसने की व्यवस्था करता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा विभिन्न राज्यों में की गई कार्रवाई ने ऐसे संगठित नेटवर्क की ओर संकेत किया है, जो विदेशी धन और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। यदि जांच में ये आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध घुसपैठ का मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के प्रबंधन और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, पहचान संबंधी दस्तावेजों की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना तथा अवैध नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना समय की मांग है। इस विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर तथ्यों और कानून के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। भारत में हर व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन जो भी व्यक्ति या संस्था कानून का उल्लंघन करती है, उसके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून का शासन सर्वोपरि है। इसी भावना के साथ अवैध घुसपैठ तथा उसके मददगारों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

मेलबाक्स

साइबर सुरक्षा पर बड़ा सवाल

भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे डार्क वेब पर लीक होने का दावा सामने आया है। लीक हुए दस्तावेजों में संयंत्र की कूलिंग सिस्टम और मुख्य नियंत्रण कक्ष का विस्तृत लेआउट शामिल होने का दावा किया गया है। परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह डाटा सीधे मुख्य परमाणु रिएक्टर से संबंधित नहीं है, लेकिन संयंत्र की सहायक प्रणालियों की जानकारी दुश्मन के हाथ लगना गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। इस जानकारी का उपयोग कर हैकर सुरक्षा कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। इससे पहले 2019 में भी उत्तर कोरिया से जुड़े हैकरों द्वारा कुडनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क पर साइबर हमला किए जाने की जानकारी सामने आई थी। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमलों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि 73 प्रतिशत भारतीय कंपनियों को यह तक पता नहीं होता कि वे साइबर हमले का शिकार हो चुकी हैं या नहीं। इस घटना ने भारत की साइबर सुरक्षा व्यवस्था में संभावित कमियों को एक बार फिर उजागर किया है।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

बेलगाम साइबर अपराधी

साइबर अपराध भारत के समक्ष सबसे गंभीर आर्थिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों में से एक बन चुके हैं। इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सुदृढ़ समन्वय, साइबर जागरूकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा तंत्र तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। किंतु साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के उपाय तभी प्रभावी सिद्ध होंगे, जब उनके साथ त्वरित जांच, समयबद्ध अभियोजन तथा कठोर एवं अनुकरणीय दंड सुनिश्चित किया जाए। साइबर अपराधी इसलिए निरंतर फल-फूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि दोषसिद्धि का जोखिम, निर्दोष नागरिकों से ठगी गई भारी धनराशि की तुलना में अत्यंत कम है। अतः भारत को विशेष साइबर अपराध न्यायालय स्थापित करने, डिजिटल फारेंसिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने, ठगी गई धनराशि को शीघ्र फ्रीज कर वापस दिलाने तथा बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और डिजिटल मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

बृज गोयल, लुधियाना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाषः नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

25.2 अरब डालर की फंडिंग हुई भारतीय स्टार्टअप्स को वर्ष 2022 में, जबकि 2023 में 11.3 अरब डालर की ही फंडिंग हो सकी थी। वर्ष 2025 में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 11 अरब डालर की फंडिंग हुई है।

आजकल

विपरीत स्थितियों में स्पेस स्टार्टअप्स क्रांति

भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इस समय विदेशी निवेश में भारी गिरावट और 'निवेश की कमी' का सामना कर रहा है। दूसरी ओर, स्पेस टेक स्टार्टअप्स पर वैश्विक निवेशक पिछले पांच साल में 6,100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश कर चुके हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया संकट के दौर में भी आया है। यह विरोधाभास महज एक संयोग नहीं है, बल्कि भारतीय तकनीकी प्रतिभा के 'पूंजी कुशल माडल' और वैश्विक बाजार की बदलती प्राथमिकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके पीछे इसरो का भरोसा और उसके द्वारा प्रदान की गई तकनीकी और ढांचागत सुविधाएं भी हैं

राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

प्रतीकात्मक

पिछले एक दशक में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहचान मुख्य रूप से हाइपर-कंज्यूमरिज्म, क्विक-कामर्स, फिनटेक और एडटेक प्लेटफार्म्स से रही हैं। ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर 'कैश बर्न' और "यूजर्स जुटाने" के माडल पर आधारित थे। हालांकि साल 2024 से 2026 के बीच वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में आए संरचनात्मक बदलाव, विशेष रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीतियां, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक तकनीकी शेयरों में सुधार ने भारतीय स्टार्टअप्स के सामने एक गंभीर 'फंडिंग विंटर' (पूंजी का सूखा) पैदा कर दिया। फंडिंग विंटर मूलतः वह दौर है, जब स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाना बहुत कठिन हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में पारंपरिक भारतीय स्टार्टअप्स में विदेशी पूंजी के प्रवाह में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

लेकिन इस आर्थिक मंदी और निराशाजनक दौर के समानांतर, भारतीय उद्यमशीलता का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने वैश्विक अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया है। देश का स्पेस टेक स्टार्टअप इस फंडिंग विंटर के थपेड़ों से पूरी तरह अछूता ही नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक वेंचर कैपिटलिस्ट्स और संस्थागत निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई है। जहां एक तरफ फिनटेक और एडटेक की वैल्यूएशन धड़ाम हो रही थी, वहीं भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स का संचयी निवेश बढ़कर 730 मिलियन डालर यानी 6,100 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। स्काईरूट और पिक्सेल जैसी स्पेस स्टार्टअप्स में जीआइसी (सिंगापुर सरकार का फंड) और ब्लैकराक जैसी दुनिया के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है।

आशा की किरण : वर्ष 2021 भारतीय स्टार्टअप्स के लिए शिखर साबित हुआ, जब उन्होंने 38 अरब डालर की चौंका देने वाली फंडिंग जुटाई, जो अब तक का रिकार्ड था। इसके बाद फंडिंग में कमी आ गई। वर्ष 2022 में 25.2 अरब डालर, तो वहीं 2023 में 11.3 अरब डालर की ही फंडिंग भारतीय स्टार्टअप्स को हो सकी। वर्ष 2020 में कोरोना संकट के समय भी स्टार्टअप्स फंडिंग 11.37 अरब डालर थी, लेकिन वर्ष 2025 में केवल 11 अरब डालर की फंडिंग हो सकी। वहीं पश्चिम एशिया संकट के कारण इस कैलेंडर वर्ष में भारतीय स्टार्टअप्स में एक मार्च से 15 जून के बीच स्टार्टअप फंडिंग पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 43 प्रतिशत कम रही। वास्तव में, पश्चिम एशिया संकट से पूर्व ही भारतीय स्टार्टअप फंडिंग के संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इस संकट ने इस स्थिति को और भी भयावह कर दिया।

इसरो की भूमिका : भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रही इस अभूतपूर्व क्रांति का सबसे बड़ा सूत्रधार कोई और नहीं, बल्कि इसरो है। इसरो के प्रति वैश्विक भरोसे का लाभ भी इस क्षेत्र को मिल रहा है। 18 जुलाई, 1980 को जब इसरो ने अपने पहले स्वदेशी राकेट के जरिये "रोहिणी" उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था, तब भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का छठा ऐसा देश बना था, जिसके पास स्वतंत्र सैटेलाइट लांच करने की क्षमता थी। इस दिन भारत स्पेस टेक्नोलाजी क्षेत्र में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, जापान और चीन के इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया।

यदि आज भारत के स्पेस स्टार्टअप वैश्विक मंदी में निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, तो उसके पीछे इसरो द्वारा प्रदान की गई तकनीकी और ढांचागत सुरक्षा है। अंतरिक्ष तकनीक बेहद संवेदनशील और जटिल होती है। किसी स्टार्टअप के लिए शुरुआत से राकेट इंजन या उपग्रह तकनीक विकसित करना वित्तीय रूप से असंभव होता है। इसरो के "टेक्नोलाजी ट्रांसफर" करने से स्पेस स्टार्टअप्स को जबरदस्त लाभ पहुंचा। इससे स्टार्टअप का शोध अन्वेषण का बजट और समय दोनों में 90 प्रतिशत तक की बचत हो गई।

एक राकेट या सैटेलाइट बनाने के लिए करोड़ों डालर के क्लीन रूम, लिक्विड प्रोपल्शन टेस्ट बेड और लांचपैड की आवश्यकता होती है। इसरो ने अपने दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोलकर स्टार्टअप्स के पूंजीगत व्यय को लगभग शून्य कर दिया। अग्निकुल कास्मास ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला निजी लांचपैड और मिशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया। स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने राकेट इंजनों का सफल परीक्षण इसरो के महेंद्रगिरि स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में किया।

पूंजीकुशल नवाचार : वैश्विक पटल पर भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स की सफलता का एक और मुख्य स्तंभ उनका वित्तीय और तकनीकी माडल है, जिसे वैश्विक विश्लेषक "द इंडियन एज" या पूंजी-कुशल नवाचार कह रहे हैं। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के स्पेस स्टार्टअप्स भारी-भरकम पूंजी और अत्यधिक महंगे संसाधनों के उपभोग पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत, विषम परिस्थितियों में पले-बढ़े भारतीय स्टार्टअप्स ने न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम परिणाम निकालने की इसरो की पारंपरिक कला को अपने डीएनए में आत्मसात कर लिया है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में 30 से 50 प्रतिशत कम परिचालन लागत पर विश्वस्तरीय उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों से बचने के लिए भारतीय कंपनियों ने आयात पर निर्भरता को न्यूनतम किया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नीति : संशोधित एफडीआइ नीति ने विदेशी पूंजी के आगमन के सारे रास्ते खोल दिए। उपग्रह निर्माण, डाटा प्रणालियों और ग्राउंड सिस्टम में बिना किसी सरकारी बाधा के 100 प्रतिशत तक आटोमेटिक रूट से निवेश की अनुमति दी गई। लांच व्हीकल्स और उनके प्रणालियों में 49 प्रतिशत तक आटोमेटिक रूट से निवेश की राह साफ की गई। इस नीतिगत स्पष्टता ने वैश्विक निवेशकों को यह कानूनी भरोसा दिया कि उनका निवेश भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विनियामक भूलभुलैया में नहीं फंसेगा।

हाल ही में सरकार द्वारा पूरी तरह क्रियान्वित किए गए 1,005 करोड़ रुपये के अंतरिक्ष वेंचर फंड ने बाजार में सकारात्मक संदेश दिया है। जब किसी उभरते और जोखिम भरे क्षेत्र में सरकार खुद 'एंकर इनवेस्टर' के रूप में उतरती है, तो निजी और विदेशी निवेशकों का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है।

आर्थिक-रणनीतिक प्रभुत्व का सूचकांक : भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का यह शानदार उभार केवल कुछ होनहार युवाओं की सफलता की कहानी या कुछ सौ मिलियन डालर के निवेश का आंकड़ा मात्र नहीं है। यह इस बात का एक निर्णायक और ऐतिहासिक उद्घोष है कि भारतीय स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम अब अपनी परिपक्वता के उस स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है जहां वह केवल पश्चिमी देशों के व्यावसायिक माडलों की नकल नहीं कर रहा, बल्कि मौलिक विज्ञान और वैश्विक स्तर की मूल बौद्धिक संपदा का निर्माण कर रहा है।

वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 500 अरब डालर की है, जिसके अगले दशक में एक ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डालर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत सरकार और निजी क्षेत्र के इस बेजोड़ तालमेल के दम पर, भारत इस विशाल वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा दो प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत से अधिक करने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा चुका है। भारत के ये युवा अंतरिक्ष उद्यमी आज गर्व से पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि आकाश अब कोई सीमा नहीं है, बल्कि यह तो हमारी अंतहीन आर्थिक और तकनीकी संभावनाओं का एक नया मैदान है।

कामयाबी की कहानी लिखते स्टार्टअप्स

इस आर्थिक परिदृश्य को और स्पष्ट करने के लिए उन प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिन्होंने भारतीय स्पेस-टेक को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है। हैदराबाद में स्थापित स्काईरूट एयरोस्पेस आज भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकार्न बन चुका है। नवंबर 2022 में अपने राकेट "विक्रम-एस" के सफल प्रक्षेपण से इतिहास रचने के बाद कंपनी ने पूरी ऊर्जा अपने मुख्य आर्बिटल व्हीकल "विक्रम-1" पर केंद्रित की। आइआइटी मद्रास के प्रांगण से "अग्निकुल कास्मास" स्टार्टअप ने वैश्विक अंतरिक्ष विनिर्माण की स्थापित धारणाओं को हिलाकर रख दिया है।

अग्निकुल ने दुनिया का पहला सिंगल-पीस 3डी प्रिंटेड राकेट इंजन विकसित किया, जो पूरी तरह से इन-हाउस और एक बार में प्रिंट होकर निकलता है। एक पारंपरिक राकेट इंजन को बनाने के लिए हजारों छोटे-छोटे पुर्जों को अत्यधिक सटीकता के साथ वेल्ड और असेंबल करना पड़ता है, जिसमें महीनों का समय और भारी श्रम लागत लगती है। अग्निकुल की 3डी प्रिंटिंग तकनीक से पूरा इंजन कंप्यूटर डिजाइन के जरिये कुछ दिनों में बन जाता है।

हाइपरस्पेक्ट्रल डाटा की वैश्विक बादशाहत : अंतरिक्ष व्यवसाय का एक बुनियादी सत्य यह है कि वास्तविक और निरंतर आने वाला राजस्व राकेट लांच करने से कहीं अधिक अंतरिक्ष जनित डाटा से प्राप्त होता है। पिक्सेल ने इसी सत्य को भांपकर हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिनरी सैटेलाइट्स का एक अनूठा कांस्टिलेशन (नक्षत्र) तैयार किया है।

सामान्य उपग्रह पृथ्वी की तस्वीरों को केवल तीन या चार स्पेक्ट्रल बैंड्स में देखते हैं। पिक्सेल के हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे प्रकाश को सैकड़ों संकीर्ण बैंड्स में तोड़ते हैं, जिससे वे ऐसी चीजें देख सकते हैं जो मानव आंख या सामान्य उपग्रहों के लिए अदृश्य हैं- जैसे किसी विशिष्ट खेत में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, भूमिगत गैस पाइपलाइनों में सूक्ष्म रिसाव, या जंगलों में आग लगने से पहले पेड़ों के भीतर नमी का स्तर। (राहुल लाल)

खरी-खरी

एक नंबर ईमानदार

पूरन शर्मा

वे एक नंबर के ईमानदार आदमी थे। किसी का कार्य किए बिना कुछ नहीं लेते थे। मेरा भी एक बार उनसे सामना हुआ। मेरे मकान के बराबर से एक आम रास्ता था। मुझे आम आदमी और आम रास्ता दोनों ही पसंद नहीं है। मेरे पास से आम आदमी गुजरे, यह मुझे गंवारा नहीं था। नगर निगम गया तो वहां सभी ने कहा कि मुक्तिदास जी को पकड़ो। मैंने मालूम किया कि वे कहां मिलेंगे। पता चला कि वे कैंटीन में मिल जाएंगे। कैंटीन में पहुंचा तो वे गरमा-गरम समोसे खाते हुए किसी को नेक सलाह दे रहे थे। मुझे देखकर बोले- 'आओ बैठो, समोसे खाओगे।'

मैं कहा- 'नहीं समोसे का तेल गला पकड़ता है, इसलिए मैं समोसे नहीं खा पाऊंगा।'

वह बोले- 'क्या नाम है आपका।' अपने साथ बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोले- 'तीन महीने से रोज मेरे साथ कैंटीन आ रहे हैं, इन्हीं से पूछो तेल कहां से निकलता है।'

साथ वाला व्यक्ति बोला- 'मेरा काम कब होने की उम्मीद है।'

मुक्तिदास ने चाय को सुड़का और दांत निकालकर बोला- 'भाई जल्दी हो तो तुम किसी और से मिल लो। अफसर को पकड़ लो। मेरी काम कराने की अपनी शैली है।'

साथ वाला स्वयं ही चुप हो गया। चुपचाप उठा, चाय-समोसे का भुगतान कर रवाना हो गया। उसकी सीट मैंने ली तो वे बोले- 'किसने सताया है तुम्हें?'

मैं बोला- 'मुझे आम आदमी और आम रास्ते ने परेशान कर दिया है। यह कैसे भी बंद होना चाहिए।'

उन्होंने मेरे निवास की स्थिति को समझा और बोले- 'बस इतनी सी बात। ऐसा करो तुम कल से ही निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दो और रास्ते को अतिक्रमण कर अपनी 'बाउंड्री' में ले लो। बाकी मैं निपट लूंगा। नगर निगम में शिकायत आने दो। शिकायत करने वालों के छक्के नहीं छुड़ा दिए तो मेरा भी नाम मुक्तिदास नहीं। लेकिन मैं ठहरा एक नंबर का ईमानदार। काम होने के बाद नकद 20 हजार ही मुझे देना।'

मुक्तिदास जी के मुंह से 20 हजार की राशि सुनकर एक बार तो मैं सन्नाटे में आया, परंतु अगले ही क्षण जमीन मिलने और आम रास्ता खत्म होने की खुशी में मैं विभोर हो गया।

पोस्ट

तकनीक हमें ऐसी दुनिया में ले जा रही है, जहां असल और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है।
मूर्ति नैन@Murti_Nain

सरकार को पुरानी फाइलें एक बार फिर से पलटनी चाहिए। जौहर विश्वविद्यालय को बनाने में 3000 करोड़ रुपये सरकार के खर्च हुए हैं। उसे यूं ही मिट्टी में मिला देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता, सिवाय लोकल नेताओं की निजी अदावत के। यूपी सरकार इस पूरी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।
ममता त्रिपाठी@MamtaTripathi80

प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा के उन चाटुकार समर्थकों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो व्यक्तिपूजा का माहौल बनाते हुए कहते हैं-'मोदी ही भारत हैं और भारत ही मोदी है।' सरकार का ध्यान व्यक्तिपूजा के बजाय आर्थिक सुधारों, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा सुधारों पर होना चाहिए। सत्ता-विरोधी लहर एक राजनीतिक चुनौती होती है। आइएनडीआइए भले ही बिखर गया हो, लेकिन कांग्रेस और उसके समर्थक अब भी सक्रिय हैं।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

बिहार डायरी

विपक्ष ने एनडीए को दे दिया खुला मैदान

अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

राज्य की एनडीए सरकार के लिए यह सुखद है कि उसे विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वर्ष 1952 के बाद से यह पहली सरकार है, जिसे विपक्ष से सदन के भीतर और बाहर चुनौती नहीं मिल रही है। संख्या बल के आधार पर पहले भी विपक्ष कमजोर रहा है। अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद के केवल 22 विधायक जीते थे। संविधानिक व्यवस्था के अनुसार यह संख्या विपक्षी दल की मान्यता के लिए पर्याप्त नहीं थी। राजद को विपक्ष के नेता का पद देकर उस पर कृपा की गई थी। तब भी विपक्ष सदन के भीतर और बाहर हमलावर था। इसके विपरीत वर्तमान विधानसभा में राजद के विधायकों की संख्या 25 है। यह विपक्षी दल के लिए 10 प्रतिशत सदस्य संख्या की अनिवार्यता को पूरी करने वाली संख्या है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा मिला हुआ है। वह इस पद को धारण करने पर मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। लेकिन, पद के अनुरूप वह श्रम नहीं कर रहे हैं।

पिछले साल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद ही तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर निकल गए थे। इस समय भी वह यूरोप की यात्रा पर हैं। किसी व्यक्ति के विदेश दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की हरेक गतिविधि पर उनके समर्थकों और विरोधियों की नजर रहती है। इस समय पूरे देश की नजर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर टिकी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा से त्यागपत्र देने के कारण उपचुनाव हो रहा है। इसके अच्छे-बुरे परिणाम से राज्य सरकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी,

तेजस्वी यादव। फाइल

परिणाम के विश्लेषण से पता चलेगा कि राज्य में पहली बार भाजपा की अगुआई में बनी एनडीए सरकार के कामकाज के बारे में शहरी मतदाताओं का क्या आकलन है। यह भी कि बांकीपुर के मतदाता नितिन नवीन की उन्नति से कितने उत्साहित हैं।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ऊर्फ पीके पहली बार चुनाव मैदान में हैं। वह अपनी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में वह नितिन नवीन से पराजित हुई थीं। भाजपा और जसुपा के उम्मीदवारों का नामांकन उत्साह के वातावरण में हुआ। उधर राजद का मामला बिना वर के बारात की याद दिला रहा था। उचित ही है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नामांकन समारोह से अनुपस्थित थे। बताने की आवश्यकता नहीं है कि पहले ही दिन राजद कार्यकर्ताओं का मन छोटा हो गया। यही कारण है कि रेखा गुप्ता अपने दम पर चुनाव मैदान में हैं। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी यादव 24 जुलाई को पटना लौटने वाले हैं। वह चुनाव प्रचार का अंतिम दौर होगा। तीन दिन में तेजस्वी कितनी सभाएं कर लेंगे। कितने मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लेंगे, इसके बारे में ठीक-ठीक वही बता सकते हैं।

उधर बांकीपुर में 2010 से लेकर अब तक हुए चार चुनावों में पहली बार भाजपा की हार के बारे में सोचा जा रहा है। इससे पहले के चुनावों में तो हारने की गारंटी के साथ ही विपक्ष अपना उम्मीदवार देता था। भाजपा इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका उदाहरण यह है कि उसकी 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू तक शामिल हैं। योजना यह है कि हरेक मतदाता के घर पर भाजपा के नेता पहुंचेंगे। भाजपा हार के बारे में तो नहीं ही सोच रही है, बल्कि वह जीत के अंतर को भी बढ़ाना चाह रही है। प्रशांत किशोर के कई करीबी भाजपा से जुड़ रहे हैं। यह क्रम जारी है। केवल बांकीपुर का उप चुनाव ही नहीं, विधानसभा का महत्वपूर्ण मानसून सत्र भी 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 24 को समापन होगा। संभवतः अंतिम दिन की बैठक में तेजस्वी भाग लेंगे।

तेजस्वी की अनुपस्थिति का दुष्प्रभाव राजद के अलावा महागठबंधन के अन्य दलों पर भी पड़ रहा है। रणनीति बनी थी महागठबंधन के सभी दल राज्य सरकार का नीति आधारित विरोध करेंगे। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बावजूद राजद को मिला वोट उसका उत्साह बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। अकेले में राजद को 23 प्रतिशत वोट मिला। यह भाजपा के 20.08 और जदयू के 19.25 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2010 और 2025 के विधानसभा चुनाव की पराजय का अंतर यह है कि उस समय लालू प्रसाद नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने संगठन को और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा कर रखा। परिणाम भी मिला। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 80 सीट जीत कर राजद सबसे बड़ा दल बन कर उभरा। वर्ष 2020 में भी राजद का विजय अभियान जारी रहा। यहीं आकर राजद के समर्थक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बीच अंतर करने लगे हैं।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

स्पेन के सामने अर्जेंटीना फीफा विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार दिखाई देता है?

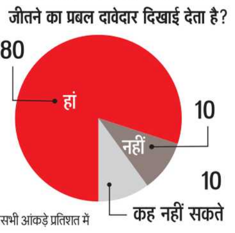

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव सही है कि नौवीं के बजाय पांचवीं या छठी कक्षा से तीसरी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

आंदोलनजीवी जमे जंतर-मंतर जाय,
दिन में अनशन चल रहा रात मलाई खायं।
रात मलाई खायं ढूंढ मुद्दे पर मुद्दा,
खेल देश के साथ खेलते रहते भद्दा।
नहीं जेहन में राष्ट्र विदेशी हित के सेवी,
अनशन करने हेतु जमे आंदोलनजीवी।
-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

एथनाल से जुड़ी दुविधाएं

ऊर्जा आत्मनिर्भरता भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य है और एथनाल उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, किंतु बड़ी संख्या में लोगों के मन में इससे संबंधित प्रश्न भी पैदा हो रहे हैं जिस ओर ध्यान देना होगा

डा. कुशाग्र राजेंद्र
एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी विश्वविद्यालय, हरियाणा

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता है। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों के लिए नए बाजार तैयार करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना- इन सभी लक्ष्यों को साथ लेकर भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण (ई-20) को पूरे देश में लागू कर दिया है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। पिछले कुछ वर्षों में एथनाल मिश्रण से देश ने विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय बचत की है और तेल आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन किसी भी बड़े ऊर्जा संक्रमण की सफलता केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं मापी जाती। उसकी असली परीक्षा तब होती है जब नई नीति आम नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा बनती है। ई-20 के साथ भी आज वही स्थिति दिखाई दे रही है। एक ओर सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों वाहन मालिक कम माइलेज, बढ़ते रखरखाव और तकनीकी अनिश्चितताओं की शिकायत कर रहे हैं।

वस्तुतः एथनाल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा घनत्व कम होता है। इसका अर्थ यह है कि समान दूरी तय करने के लिए इंजन को अधिक ईंधन जलाना पड़ता है। सरकारी और आटोमोटिव संस्थानों के परीक्षणों में माइलेज में केवल सीमित गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में अनेक वाहन मालिक इससे कहीं अधिक कमी महसूस कर रहे हैं। हाल के एक बड़े उपभोक्ता सर्वेक्षण में अनेक प्रतिभागियों ने माइलेज घटने और रखरखाव बढ़ने की शिकायत दर्ज कराई। प्रयोगशाला और सड़क पर मिलने वाले अनुभवों के बीच यही अंतर आज इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

चिंता केवल माइलेज तक सीमित नहीं है। देश की सड़कों पर चल रहे अधिकांश वाहन 2023 से पहले बने हैं, जिन्हें मूलतः ई-10 तक के मिश्रण के लिए डिजाइन किया गया था। एथनाल नमी को आकर्षित करता है और पुराने इंजनों के रबर तथा धातु के कई पुर्जों पर उसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है। नई पीढ़ी के इंजनों में ईंधन की गुणवत्ता के अनुसार स्वयं को समायोजित करने वाली प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन पुराने वाहनों में ऐसी सुविधा नहीं है। यदि ऊर्जा परिवर्तन का सबसे बड़ा बोझ उसी उपभोक्ता पर आ जाए जिसने अपनी गाड़ी वर्षों पहले खरीदी थी, तो यह केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति का भी प्रश्न बन जाता है।

इस पूरी बहस का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा हुई है। सरकार ने पूरे देश में ई-20 को मानक ईंधन बना दिया है, जबकि उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल या कम एथनाल मिश्रण का विकल्प उपलब्ध नहीं है। पहली नजर में यह उपभोक्ता अधिकार का प्रश्न लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा लाजिस्टिक पक्ष भी है। यदि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल, ई-10 और ई-20 अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएं, तो अलग भंडारण टैंक, पाइपलाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण व्यवस्था विकसित करनी होगी। देश के हजारों छोटे पेट्रोल पंपों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत महंगी और जटिल साबित होगी। संभवतः इसी कारण सरकार ने पूरे देश के लिए एक समान ईंधन माडल अपनाया है।

इस नीति का एक और आर्थिक विरोधाभास भी है। ई-20 की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम है, लेकिन उसकी कीमत लगभग समान है। इसकी लागत प्रति किमी अधिक है। यदि नागरिक को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़े, तो उसे उसके कारणों और लाभों की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह बहस एकतरफा नहीं है। यह सही है कि वाहन से निकलने वाले कुछ उत्सर्जनों में कमी आती है और यह भारत के नेट जीरो विकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन किसी भी जैव ईंधन का वास्तविक पर्यावरणीय मूल्यांकन उसके पूरे जीवन-चक्र के आधार पर किया जाता है। गन्ना और धान जैसी फसलों की सिंचाई, उर्वरकों का उपयोग, प्रसंस्करण, परिवहन और डिस्टिलरी संचालन को भी इसमें शामिल करना होगा। विशेष चिंता पानी की है। अनुमान है कि एक लीटर एथनाल के उत्पादन में औसतन 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब देश के अनेक हिस्से भूजल संकट से जूझ रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा के बीच संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मक्का, कृषि अवशेष और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों जैसे कम जल-आधारित विकल्पों को तेजी से बढ़ावा देना आज जरूरी है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य है और एथनाल उसकी अहम कड़ी है, परंतु किसी भी नीति की स्थायी सफलता तब सुनिश्चित होती है, जब उसमें राष्ट्रीय हित और नागरिक हित साथ-साथ चलें। ऊर्जा संक्रमण की यह यात्रा जितनी तेज होगी, उतनी ही पारदर्शी और सहभागी भी होनी चाहिए। अन्यथा यह आशंका बनी रहेगी कि हम मंजिल की दिशा तो सही चुन रहे हैं, लेकिन शायद उसकी ओर कुछ अधिक जल्दबाजी में बढ़ रहे हैं।

प्रतीकात्मक

आरबीआइ ने छह कंपनियों पर जुर्माना लगाया

मुंबई: आरबीआइ ने विभिन्न नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मुथूट फाइनेंस समेत कुल छह कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआइ की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मुथूट फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपये, सत्या माइक्रोकैपिटल व पैन इमाम कास्म्ड पर 3.10-310 लाख रुपये, धानी लोन्स और एसेट फाइनेंस पर 2.70-2.70 लाख रुपये और अवेल फाइनेंस सर्विसेज पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। (प्रेट्र)

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी विश्वसनीयता बनाने से आगे बढ़कर, लंबे समय तक चलने वाली क्षमताएं विकसित करने में मदद करेगा।
- अशोक चंडक, सीईओ, सेमी इंडिया

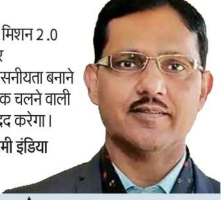

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलो ग्राम	डालर	क्रूड प्रति बैरल
78,151.45 ▲ 964.58	24,334.30 ▲ 261.55	₹ 1,45,500 ▼ ₹ 800	₹ 2,22,500 ▼ ₹ 2,000	₹ 96.30 ▼ ₹ 0.12	$ 85.52

महंगे कच्चे तेल के बावजूद रिलायंस की आय बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के दौरान रिलायंस इंडस्ट्री ने रिकार्ड कोर लाभ और एबिटा (कर-पूर्व आय) दर्ज किया है। इसमें तेल से रसायन और दूरसंचार कारोबार के मजबूत प्रदर्शन का प्रमुख योगदान रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि बीती तिमाही के दौरान उसका समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 25.4 प्रतिशत बढ़कर 3.12 लाख करोड़ रुपये रहा है।

कंपनी ने बताया कि पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान उसने एशियन पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने से 8,924 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। उसको छोड़कर नियमित आधार पर बीती तिमाही में उसका एबिटा 10.1 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 54,067 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, कर-पश्चात लाभ 6.1 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 23,196 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, 8,924 करोड़ रुपये के लाभ को शामिल करने पर एबिटा में 6.8 प्रतिशत की गिरावट रही है। साथ ही कर-पश्चात लाभ वार्षिक आधार पर 22 प्रतिशत घटकर 20,946 करोड़ रुपये रहा है।

ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से प्रभावित तिमाही के दौरान कंपनी की आय में मजबूती आई है। इस दौरान तेल से रसायनों के व्यवसाय कारोबार से होने वाली आय में पिछले वर्ष की तुलना में 17.2 प्रतिशत और दूरसंचार कारोबार में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अप्रैल-जून 2026 के दौरान कंपनी की दूरसंचार इकाई जियो प्लेटफार्म्स लिमिटेड का कर-पूर्व लाभ 20,865 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का ग्राहक आधार 53.3 करोड़ को पार कर गया है।

- अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 3.12 लाख करोड़ रुपये रही कंपनी की कुल आय
- तेल और रसायन कारोबार से होने वाली आय वार्षिक आधार पर 17 प्रतिशत बढ़ी

1.23 लाख करोड़ रुपये रहा बीती तिमाही के अंत में कंपनी पर शुद्ध कर्ज

रिलायंस रिटेल का एबिटा 1.1 प्रतिशत घटा

बीती तिमाही के दौरान रिलायंस रिटेल का राजस्व वार्षिक आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 90,408 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, एबिटा 1.1 प्रतिशत घटकर 6,309 करोड़ रुपये रहा है। तिमाही के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कारोबारों पर 38,682 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बीती तिमाही के अंत में कंपनी पर शुद्ध कर्ज 1,22,914 करोड़ रुपये रहा है।

रिलायंस ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत मजबूती से की है और सभी कारोबारों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। हमारे पोर्टफोलियो ने एक बार फिर मुश्किल हालात में भी मजबूती दिखाई है, जबकि इस तिमाही में भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी रहे। बीती तिमाही के प्रदर्शन ने "शेष वर्ष के लिए उम्मीद रखने की वजह" दी है। कंपनी नई ऊर्जा परियोजना और जियो के आइपीओ की दिशा में आगे बढ़ रही है।
- **मुकेश अंबानी**, चेयरमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज

प्लास्टिक नोट लाने की दिशा में आरबीआइ ने बढ़ाया कदम

मुंबई, एएनआइः प्लास्टिक नोटों को प्रचलन में लाने की दिशा में आरबीआइ ने एक और कदम बढ़ा दिया है। आरबीआइ की नोट मुद्रण शाखा ने पालीमर सब्सट्रेट शीट्स (प्लास्टिक नोट बनाने वाले बेस मैटेरियल) के लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया है। शुक्रवार को जारी किए गए इस टेंडर के मुताबिक, चयनित कंपनी को बायएक्सियली ओरिएंटेड पालीप्रोपाइलीन (बीओपीपी) आधारित पालीमर सब्सट्रेट की 68,000 रिम की आपूर्ति करनी होगी। इसमें दो अलग-अलग मूल्यवर्ग के लिए 34,000-34,000 रिम की जरूरत है और हर रिम में 500 शीट होंगी। आपूर्ति की जाने वाली पालीमर शीट में मैटेलिक अंक और शैडो इमेज जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, जो सरकारी प्रेस में छपाई के लिए उपयुक्त हों।

जानकार सूत्रों का कहना है कि शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपये जैसे कम मूल्यवर्ग के पालीमर नोट चलन में लाए जा सकते हैं।

- केंद्रीय बैंक की नोट मुद्रण शाखा ने पालीमर सब्सट्रेट शीट्स के लिए जारी किया वैश्विक टेंडर
- शुरुआती चरण में 10 व 20 रुपये जैसे कम मूल्यवर्ग के पालीमर नोट ला सकता है बैंक

खास बात यह है कि जारी किए गए टेंडर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई कड़ी शर्तें शामिल हैं। टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन या पाकिस्तान में उनका कामकाज भारत से जुड़े किसी भी कारोबार से पूरी तरह अलग हो। इसके साथ ही वे किसी भी देश से कच्चा माल नहीं लें और ऐसे कर्मचारियों को काम पर नहीं रखें, जिन्होंने चीन या पाकिस्तान में किसी भी भूमिका में काम किया हो। भारत के साथ जमीन साझा करने वाले देशों की टेंडर में तभी हिस्सा ले सकेंगी जब वह डीपीआइआइटी की पंजीकृत कमेटी के पास रजिस्टर होंगी। आरबीआइ की नोट मुद्रण शाखा ने कहा कि अभी की जरूरत सिर्फ तत्काल आधार पर है और अगर सब्सट्रेट शीट का ट्रायल सफल रहता है तो भविष्य में कई अन्य मूल्यवर्ग के लिए बड़ी मात्रा में खरीद की जा सकती है। टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के पास किसी केंद्रीय बैंक या नोट/सिक्योरिटी प्रिंटिंग आर्गनाइजेशन को सिक्योरिटी फीचर्स वाले पालीमर सब्सट्रेट शीट्स की आपूर्ति करने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। लैब टेस्टिंग के लिए पालीमर शीट के कम से कम 10 सैंपल जमा करने होंगे और यह जानवरों की चर्बी से मुक्त होना चाहिए।

पालिमर नोट की खास बातें

- पालिमर बैंक नोट एक पतली और लचीली प्लास्टिक पर प्रिंट किए जाते हैं।
- प्लास्टिक होने के बावजूद यह क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते हैं।
- पालिमर के यह नोट काफी हल्के होते हैं। इन्हें मोड़ा जा सकता है।
- इन नोटों का इस्तेमाल कागजी मुद्रा की तरह ही किया जा सकता है।
- यह नोट काफी मजबूत हैं और इन पर गंदगी-नमी का ज्यादा असर नहीं होता है।
- प्लास्टिक के इन नोटों को लंबे समय तक चलन में रखा जा सकता है।
- इनमें सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर शामिल किए जा सकते हैं।
- माइक्रो-आप्टिक होलोग्राम और खास तरह की स्याही के चलते इनकी नकल करना काफी मुश्किल है।

एक नजर में

बीते सप्ताह 96 करोड़ डालर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

मुंबई: बीते सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 96.4 करोड़ डालर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआइ के ताजा डाटा के अनुसार, 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 675.157 अरब डालर हो गया है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डालर बढ़ा था। बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा आस्तियों में 93 करोड़ डालर की बढ़ोतरी हुई है और यह 546.508 अरब डालर पर पहुंच गई है। इसी तरह, स्वर्ण भंडार का मूल्य 2.4 करोड़ डालर बढ़कर 105.223 अरब डालर हो गया है। (प्रेट्र)

कोर सेक्टर की सूची में शामिल हुआ लौह अयस्क

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोर सेक्टर के इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों की सूची में लौह अयस्क को शामिल किया है। इस कदम से अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अब इस सूची में शामिल उद्योगों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई है। अभी सरकार आठ प्रमुख क्षेत्रों- कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, तैयार स्टील और कोयला के प्रदर्शन का हर महीने मूल्यांकन करती है। नौ प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित डाटा 20 जुलाई को जारी किया जाएगा। (प्रेट्र)

मेकमाईट्रिप इंडिया ने जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली: नैस्डेक में सूचीबद्ध ट्रैवल बुकिंग प्लेटफार्म मेकमाईट्रिप ने शुक्रवार को कहा कि उसकी भारतीय सब्सिडियरी मेकमाईट्रिप (इंडिया) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के लिए मसौदा दस्तावेज सेबी के पास जमा कर दिए हैं। कंपनी ने गोपनीय रूट के जरिये मसौदा दस्तावेज जमा किए हैं। आइपीओ प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी मेकमाईट्रिप इंडिया अपनी पैरेंट कंपनी की सब्सिडियरी बनी रहेगी और इसके वित्तीय नतीजे पैरेंट कंपनी के साथ ही जारी किए जाएंगे। (प्रेट्र)

बड़ी कंपनियों में खरीदारी से सेंसेक्स 965 अंक उछला

डालर के मुकाबले रुपये में मजबूती से भी धारणा बेहतर हुई, प्रमुख आइटी कंपनी टेक महिंद्रा में 3.91% की तेजी रही

मुंबई, प्रेट्र: रिलायंस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग और सूचना-प्रौद्योगिकी शेयरों में खरीदारी से शुक्रवार को शेयर बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिछले कारोबारी सत्र में सुस्त कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 964.58 अंक या 1.25% की बढ़त के साथ 78,151.45 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह एक समय 1,095.68 अंक या 1.41% बढ़कर 78,282.55 पर पहुंच गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 261.55 अंक या 1.09% चढ़कर 24,334.30 पर बंद हुआ। कारोबारियों का कहना है कि डालर के मुकाबले रुपये में मजबूती से भी धारणा बेहतर हुई। हालांकि कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते बाजार का ज्यादातर हिस्सा नकारात्मक बना रहा।

साप्ताहिक आधार पर देखें तो बीएसई सेंसेक्स 582.06 अंक या 0.75% चढ़ा और निफ्टी में 127.4 अंक या 0.52% की तेजी आई है। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में टेक महिंद्रा में 3.91% की तेजी दर्ज की गई। जून तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 28.4% की वृद्धि के साथ 1,465 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और बजाज फाइनेंस भी बढ़कर बंद होने वाले शेयर में शामिल रहे। हालांकि, सन फार्मा, ट्रेंट, भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे। ग्लोबल आयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.79 प्रतिशत बढ़कर 85.52 डालर प्रति बैरल हो गया। गुरुवार को सेंसेक्स 1.44 अंक बढ़कर 77,186.87 पर बंद हुआ। निफ्टी 5.75 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 24,072.75 पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई225 इंडेक्स, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग काफी गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया के बाजार शुक्रवार को बंद थे।

78,151.45 पर बंद हुआ बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक

261.55 अंक चढ़कर 24,334.30 पर बंद हुआ एनएसई का निफ्टी

582 अंकों की तेजी दर्ज की गई पूरे सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में

0.32 प्रतिशत गिरा स्मालकैप इंडेक्स

0.07 प्रतिशत नीचे आया मिडकैप इंडेक्स

बैंकिंग, फाइनेंशियल और आइटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों के शेयरों में व्यापक खरीदारी ने बेंचमार्क इंडेक्स को कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की। एआइ वैल्यूएशन को लेकर लगातार चिंता, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता के बावजूद निवेशकों को भरोसा बना रहा।
- **पोनमुडी आर. सीईओ**, आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म एनरिच मनी

डालर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत होकर 96.28 पर बंद हुआ रुपया

मुंबई, प्रेट्र: रुपया शुक्रवार को 14 पैसे मजबूत होकर डालर के मुकाबले 96.28 पर बंद हुआ। आरबीआइ के संभावित हस्तक्षेप के बाद घरेलू मुद्रा में लगातार चार कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट थमी। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से स्थानीय मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.35 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के दौरान डालर के मुकाबले 96.27 से 96.41 के दायरे में रहा। अंत में 96.28 प्रति डालर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 14 पैसे की तेजी है।

तीन सप्ताह के निचले स्तर पर सोना

नई दिल्ली, प्रेट्र: शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 800 रुपये गिरकर तीन सप्ताह के निचले स्तर 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोना 25 जून को भी इसी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था और उस समय उसकी कीमत 1,45,300 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। चांदी भी 2,000 रुपये गिरकर 2,22,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,24,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 15.42 डालर या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 3,992 डालर प्रति औंस हो गया। हालांकि, चांदी की कीमत थोड़ी गिरकर 55.37 डालर प्रति औंस हो गई।

एनवीडिया को पछाड़ एपल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी

न्यूयार्क, रायटरः चिप कंपनी एनवीडिया को पीछे छोड़कर एपल ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। इससे तकनीकी जगत की बड़ी कंपनियों की रैंकिंग में बदलाव आया है, क्योंकि निवेशक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के भविष्य को लेकर अपनी राय बदल रहे हैं। शुक्रवार को एपल की वैल्यूएशन 4.88 ट्रिलियन डालर हो गई जबकि एनवीडिया के शेयरों में 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे इसकी वैल्यूएशन घटकर 4.86 ट्रिलियन डालर रह गई। वैल्यूएशन के मामले में पिछले साल अप्रैल के बाद एपल फिर शीर्ष पर आ गई है।

बीआइआइ वेल्थ मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट हेड टोनी मुडीज ने कहा, 'एआइ की दौड़ में एपल को पीछे माना जाता था, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। एपल पर पूंजीगत खर्च का दबाव कम है और यह सर्विस, इकोसिस्टम और हार्डवेयर अपग्रेड के जरिये एआइ से कमाई करने की बेहतर स्थिति में है।

म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स की हस्तांतरण प्रक्रिया सरल बनाई

नई दिल्ली, प्रेट्रः एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) ने निवेशक की मृत्यु के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। इसमें पते, नाम और हस्ताक्षर में असमानताओं से संबंधित मानदंडों को शिथिल किया गया है और यह बदलाव तुरंत प्रभावी हो गए हैं।

एएमएफआइ ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य परिचालन बाधाओं को कम करना और मृतक यूनिटधारकों के नामांकित व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स या प्राप्तियों का दावा करने में अधिक सहजता प्रदान करना है। नए ढांचे के तहत, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को सलाह दी गई है कि वे मृतक यूनिटधारक के नवीनतम उपलब्ध पते पर भरोसा करें। एएमएफआइ ने नाम और हस्ताक्षर में असमानताओं को हल करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण भी पेश किया है। एएमसी अब नाम और हस्ताक्षर में छोटी-बड़ी असमानताओं के निस्तारण के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) के लिए निर्धारित ढांचे का पालन कर सकती हैं। यह बदलाव उन रिपोर्टों के बीच हुआ है जिनमें नामांकित व्यक्तियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को छोटी असंगतियों के कारण हस्तांतरण में कठिनाई की बात कही गई थी।

नाम, पते और हस्ताक्षर में असमानता से संबंधित मानदंडों को शिथिल किया गया, तुरंत लागू हो गए हैं नए बदलाव

चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है एलपीजी सब्सिडी बिल

नई दिल्ली, एएनआइः चालू वित्त वर्ष (2026-27) में सरकार का एलपीजी सब्सिडी बिल एक लाख करोड़ से ज्यादा रह सकता है। यह केंद्रीय बजट में तय 30 हजार करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग 70 हजार करोड़ रुपये ज्यादा होगा। इसकी वजह यह है कि ईंधन और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सरकार और तेल कंपनियां खुद वहन कर रही हैं। पीएल कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार अभी तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर 490 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कुल सब्सिडी खर्च में भारी वृद्धि हुई। अप्रैल-मई, 2026 के दौरान मुख्य सब्सिडी पर कुल खर्च 755.40 अरब रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 512.50 अरब रुपये था। यानी इसमें साल-दर-साल 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

खाद्य सब्सिडी 279.90 अरब रुपये से बढ़कर 408 अरब रुपये हो गई, जो साल-दर-साल 46 प्रतिशत की वृद्धि है। पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी 43.1 अरब रुपये से बढ़कर 60.10 अरब रुपये हो गई। इस अवधि में पिछले साल पेट्रोलियम सब्सिडी 280 करोड़ रुपये रही जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह शून्य थी। रिपोर्ट के अनुसार, सब्सिडी पर ज्यादा खर्च की वजह युद्ध जैसी स्थिति से पैदा हुई अनिश्चितता है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

- सरकार ने बजट में इस मद के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का किया था आवंटन
- एलपीजी कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन करने से बिल में होगी वृद्धि

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

आइटीआर में विदेशी संपत्ति की जानकारी जरूर दें करदाता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विदेश में किसी भी प्रकार की संपत्ति है तो उसकी जानकारी सरकार को देने में ही भलाई है। अब आपकी आय को लेकर आयकर विभाग की तरफ से जारी होने वाले वार्षिक सूचना विवरण (एआइएस) में विदेशी संपत्ति का भी ब्योरा दिया जा रहा है। आटोमेटिक एक्सचेंज आफ इन्फार्मेशन फ्रेमवर्क के तहत भारत को दुनिया के 100 देशों से उन सभी भारतीयों की संपत्तियों की जानकारी हर साल मिलती है, जिन्होंने उन देशों में बैंक खाते खोल रखे हैं या फिर किसी प्रकार की संपत्ति की खरीद-फरोख्त की है।

सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग एआइएस में विदेशी संपत्ति की सूचना इसलिए दे रहा है ताकि करदाता टैक्स देने के दौरान इस संपत्ति से होने वाली कमाई को भी ध्यान में रखें। टैक्स विभाग का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी जांच की शुरुआत करना नहीं है। करदाता को टैक्स फाइलिंग में सहूलियत प्रदान करना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस प्रकार के करदाताओं ने अपने रिटर्न में विदेशी संपत्ति से होने वाली आय पर टैक्स नहीं दिया है तो वे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें। वर्ष 2022, 2023 और वर्ष 2024 का आंकड़ा विभाग को मिल गया है, जिसे एआइएस में प्रदर्शित कर दिया गया है। वर्ष 2025 का आंकड़ा इस साल सितंबर-अक्टूबर में प्राप्त होगा और उसके बाद उन्हें भी एआइएस में प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

सरकार को 100 देशों से मिल रही भारतीयों की संपत्ति की जानकारी, एआइएस में दिया जा रहा ऐसी संपत्तियों का ब्योरा

राष्ट्रीय फलक

शिक्षकों के खाली होने वाले पदों को 90 दिनों में भरें उच्च शिक्षण संस्थान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विश्वविद्यालय सहित देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली होने वाले पदों को 90 दिनों के भीतर भरने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा, खाली होने वाले पदों को भरने की प्रक्रिया पद रिक्त होने के छह माह पहले से ही शुरू की जाए, ताकि उसे समय से भरा जा सके। अप्रैल, 2025 तक आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 प्रतिशत रिक्तियां थीं।

संयुक्त संसदीय समिति ने यह सुझाव विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को लेकर सौंपे जाने वाले मसौदे में दिया। माना जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इसे सौंप दिया जाएगा। हालांकि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार यानी 17 जुलाई को समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसे बाद में टाल दिया।

सूत्रों की मानें तो अब यह बैठक 20 जुलाई को होगी। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक पर करीब 23 बैठक कर चुकी है। इस दौरान राज्यों व शिक्षाविदों आदि की भी राय जान चुकी है। प्रस्तावित विधेयक में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। समिति के मसौदे में गुणवत्ता जांचने वाली एक परिषद भी बनाने का प्रस्ताव है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों ने सवाल उठाए थे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

इस पर संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से यह सुझाव पारित किया कि उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षकों के खाली होने वाले पद को 90 दिन में भरें। साथ ही इसकी तैयारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तिथि से छह महीने पहले से शुरू की जाए। सरकार यदि इस सुझाव को मानती है तो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। साथ ही उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर गठित जेपीसी ने प्रस्तावित मसौदे में दिए सुझाव
- कहा, शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के छह महीने पहले से ही खाली हो रहे पदों को भरने की शुरू की जाए तैयारी

एअर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट जल्द जारी होगी: नायडू

वडोदरा, प्रेट्र: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा, सरकार अहमदाबाद में जून 2025 में हुए एअर इंडिया एआइ-171 विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। हादसे की जांच जारी है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) को सभी जरूरी संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

नायडू ने वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षा समारोह में के बाद पत्रकारों से कहा, जांच में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सरकार की प्राथमिकता हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाना है। उन्होंने मृतकों के परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय तभी मिलेगा जब पूरी सच्चाई सामने आएगी। कहा, एएआइबी पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से जांच कर रहा है।

ई-20 के लिहाज से तैयार नहीं 78 प्रतिशत वाहन

प्रथम पृष्ठ से आगे

अधिकारी बताते हैं कि भारत में मोटे तौर पर 30 करोड़ दोपहिया वाहन और सात-आठ करोड़ कारें हैं। इनमें सात करोड़ बीएस-6 मानक वाले वाहन (वर्ष 2023 से उत्पादन) हैं, जो ई-20 ईंधन के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। यानी तकरीबन 78 प्रतिशत वाहन ऐसे हैं जिसे ई-20 के लिहाज से तैयार नहीं किया गया था। हालांकि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले दिनों इस तर्क को खारिज किया था कि ई-10 के लिए निर्मित वाहनों में ई-20 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने कहा था कि लोगों में एक धारणा है कि पुराने वाहनों में 'ई-10 के लिए उपयुक्त' मैनुअल को लेकर है। लोगों को समझना चाहिए कि वाहन मैनुअल उस समय के ईंधन स्टैंडर्ड को दर्शाता है, जब वह वाहन सर्टिफाइड हुआ था। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर बाद में व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण, इंजीनियरिंग वैलिडेशन और नियामक मंजूरी के बाद में ईंधन स्टैंडर्ड में बदलाव होता है तो वाहन अचानक असुरक्षित हो जाता है। ई-10 से ई-20 की तरफ जाना अनुमानों के आधार पर नहीं किया गया था बल्कि वर्षों के परीक्षण, वाहन निर्माताओं के साथ 2021 से ही परामर्श व फील्ड अनुभव पर आधारित था। वाहन निर्माता कंपनी भी पूरी तरह ई-20 से सहमत थी। इसीलिए सभी गाड़ियों की वारंटी मिल रही है।

हालांकि, ई-20 ईंधन से वाहनों के रबर के पुर्जों को क्षति होने की बात हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक साक्षात्कार में स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि पुरानी कारों (ई-20 या उससे कम मिश्रण के लिए निर्मित) के उन पुर्जों को सर्विसिंग के दौरान मुफ्त में बदला जाएगा, जो ई-20 से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया था कि इस बारे में वाहन निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इन पुर्जों को ग्राहक से बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदल दें, लेकिन इस बारे में कम से कम दो प्रमुख आटो कंपनियों ने दैनिक जागरण को बताया कि उन्हें इस तरह का निर्देश नहीं मिला है।

भारत में लगभग 1,00,266 पेट्रोल पंप हैं (नवंबर 2025 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार)। लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर अभी ई-20 ही मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2026 से ई-20 को देशव्यापी स्टैंडर्ड बना दिया गया है। साथ ही शुद्ध पेट्रोल (ई-0) या ई-10 अलग से उपलब्ध कराना अब संभव नहीं है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक देश में 500 ई-85 पेट्रोल पंप स्थापित करने की भी घोषणा की है। ई-85 पेट्रोल ई-20 के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी है। वैसे देश में सिर्फ मारुति सुजुकी ने ही अभी ई-85 से चलने वाली एक वाहन को लांच किया है। उम्मीद है कि कुछ और कंपनियां जल्द ही अपने अन्य माडलों की लांचिंग करेंगी। महंगे प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री हर स्टेशन पर पूर्ववत होती रहेगी।

17 जुलाई को हुए भूस्खलन में दक्षिण-पश्चिमी चीन के चोंगकिंग शहर में आठ लोगों की मौत हो गई और 34 लोग लापता हो गए। इस घटना में रिहायशी इमारतें मलबे में दब गईं और 1,100 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा।

न्यूज गैलरी

आस्ट्रेलिया पहुंचे भारतीय वायुसेना के राफेल विमान

कैनबरा : भारत के राफेल जेट और सी-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ये रायल आस्ट्रेलियन एयर फोर्स की प्रमुख मल्टीनेशनल एयर कांबेट एक्सरसाइज, पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेंगे। यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। कैनबरा में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पोस्ट में कहा, "भारतीय उच्चायोग को डार्विन में वायु सेना की उस टुकड़ी का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है, जिसमें चार राफेल और दो सी-17 एयरक्राफ्ट संग 120 से अधिक एयर वारियर्स शामिल हैं।" (आइएएनएस)

एफबीआइ ने गैंगस्टर नीतीश कौशल को किया गिरफ्तार

वाशिंगटन : एफबीआइ ने गैंगस्टर नीतीश कौशल को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर अमेरिका में हत्या, अपहरण और ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप है। मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। एफबीआइ ने कहा कि भारतीय नागरिक कौशल ने भगवानपुरिया आर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप के लिए अपराधों को अंजाम दिया, जिसमें अपहरण और मारपीट जैसी वारदातें शामिल हैं। (प्रेट्र)

स्पेसएक्स स्टारशिप की टेस्ट फ्लाइट रोकनी पड़ी

वाशिंगटन : स्पेसएक्स का विशाल स्टारशिप राकेट टेस्ट फ़्लाइट के लिए उड़ान भरने ही वाला था कि कुछ इंजन चालू नहीं हो पाए, जिससे लांच को रोकना पड़ा। एलन मस्क की कंपनी ने कहा कि स्टारशिप को दुनिया के आधे हिस्से तक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में उड़ाने की अगली कोशिश करने से पहले उन्हें यह पता लगाना होगा कि क्या गड़बड़ हुई थी।" (एपी)

युगांडा में स्कूल बस पलटने से 20 बच्चों समेत 21 की मौत

कंपाला : युगांडा के पूर्वी कपचोरवा जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 बच्चों और एक वयस्क की मौत हो गई। बस सिपी फाल्स की शैक्षणिक यात्रा से लौट रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया। (एपी)

टेक्सास में अचानक आई बाढ़ से दो लोगों की मौत

यूवाल्डे : अमेरिका के टेक्सास राज्य में मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण फ्लैश फ्लड में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया। गवर्नर ग्रेग एबाट ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य में 1,300 से अधिक कर्मियों को लगाया गया है। (एपी)

नागरिक ठिकानों पर और तेज हुए अमेरिका-ईरान के हमले

ईरान के पुल, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट बने निशाना, जवाब में कुवैत के बिजली घर व पानी संयंत्र तबाह

होर्मुज में एक जहाज पर ईरान का हमला, दो पर अमेरिकी सेना का कब्जा, कच्चे तेल की कीमत 86 डालर के पार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को लगातार आठवें दिन सैन्य टकराव ने नागरिक ठिकानों का रुख कर लिया। दोनों देशों ने हमलों का दायरा बढ़ाते हुए एक-दूसरे के रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी सेना ने उसके सात पुलों, एक रेलवे स्टेशन और ईरानशहर हवाई अड्डे समेत कई नागरिक ढांचों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सैन्य अड्डों के साथ-साथ नागरिक ठिकानों पर हमले तेज करने की बात कही है।

लगातार बढ़ते संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी चिंता गहरा गई है। कच्चे तेल की कीमतें 86 डालर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं, जबकि दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग होर्मुज स्ट्रेट लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है। गुरुवार को केवल आठ जहाज निकल सके, जिसमें से सात ईरान अधिकृत जलमार्ग से गुजरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान में बड़ी जीत मिल रही है। रायटर के अनुसार, ईरान ने ओमान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया। वहीं, अमेरिकी सेंटकाम ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी झंडा लगे एक टैंकर को कब्जे में ले लिया, जबकि दूसरे जहाज को मिसाइल से निष्क्रिय कर दिया। दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में बंदर खमीर के सात पुलों, रेलवे स्टेशन और ईरानशहर हवाई अड्डे सहित कई ठिकानों पर हमले किए। सेंटकाम का कहना है कि कार्रवाई केवल सैन्य लाजिस्टिक्स, तटीय निगरानी और हवाई रक्षा ढांचे तक सीमित थी, जबकि ईरानी मीडिया ने इन हमलों में सात नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमलों में अब तक 38 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा घायल हैं।

ईरान में अज्ञात स्थान पर गुरुवार को अमेरिकी हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। वीडियोग्रैब/रायटर

जवाब में ईरान ने कुवैत के एक बिजली संयंत्र और मीठे पानी के प्लांट पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई और दोनों को काफी नुकसान पहुंचा। कुवैत में 90 प्रतिशत पीने का पानी इन्हीं संयंत्रों से आता है, जो खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं। इससे पहले 30 मार्च को कुवैत के पानी संयंत्र (डीसैलिनेशन प्लांट) पर हमला हुआ था, जिसके बाद पहली बार ट्रंप ने युद्धविराम की घोषणा की थी।

एएनआइ के अनुसार, ईरान ने दावा किया कि उसके जवाबी हमले कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, जार्डन, इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंचे हैं। ओमान और कतर में धमाकों की खबरें भी सामने आई हैं। ईरान ने पहली बार सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया है। ये हमला तांफ स्थित अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज बेस पर किया गया।

चाबहार बंदरगाह पर तीसरी बार हमला

एपी के अनुसार, हमलों की चपेट में भारत के लिए रणनीतिक महत्व वाला चाबहार बंदरगाह भी आया। इस बंदरगाह पर पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार हमला हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ये सर्विलांस टावर था, जबकि ईरान का कहना है कि ये व्यापारिक जहाजों के यातायात को नियंत्रित करनेवाला निगरानी टावर था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ध्वस्त टावर की तस्वीर अपने एक्स एकाउंट पर साझा की। बता दें कि इस बंदरगाह के विकास में भारत ने निवेश किया है और इसका संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आइपीजीएल) कर रही है। यह परियोजना भारत को पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराती है।

ट्रंप की हत्या पर एक करोड़ डालर का इनाम घोषित

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू महदी अल-मुहंदिस की हत्या का बदला लेने का दावा
- ईरान समर्थित इराकी समूह की धमकी, 2020 के ड्रोन हमले का जिक्र कर ट्रंप के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया

ईरान समर्थित इराकी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक (आइआरआइ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वाले को एक करोड़ डालर (10 मिलियन डालर) का इनाम देने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि यह कदम 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल-मुहंदिस की अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई मौत का बदला लेने के लिए उठाया गया है।

ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार, संगठन ने कहा है कि इनाम की राशि सदस्यों और समर्थकों से चंदा जुटाकर एकत्र की जाएगी। 16 जुलाई को जारी बयान में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ट्रंप की हत्या करेगा, ऐसा करने का निर्देश देगा या इस कार्रवाई में किसी भी तरह की मदद करेगा, उसे यह इनाम दिया जाएगा। संगठन ने आरोप लगाया कि ट्रंप हाल के दिनों में सुलेमानी और अल-मुहंदिस की हत्या की जिम्मेदारी लेकर शेखी बघार रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह घोषणा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस में इराकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने 2020 के ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि उन्होंने सुलेमानी को नहीं मारा होता तो हालात अलग होते। उन्होंने यह भी

इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के सदस्य।

कहा कि उसी हमले में "एक और बेहद खतरनाक व्यक्ति" भी मारा गया था, जिसका इशारा अबू महदी अल-मुहंदिस की ओर माना गया। इस बीच, अल-मुहंदिस के परिजनों ने ट्रंप के बयान पर इराकी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की आलोचना की है। उल्लेखनीय है कि 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर कई बार हमले या हमले की साजिशों की जांच हुई है। इनमें पेंसिलवेनिया की रैली में हुआ गोलीबारी का मामला सबसे गंभीर था। अमेरिकी एजेंसियों ने कुछ मामलों में ईरान से संभावित संबंधों की भी जांच की थी, हालांकि ईरान ने ट्रंप की हत्या की किसी भी साजिश में शामिल होने से इन्कार किया है।

बर्नहम होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री

- किंग चार्ल्स से मुलाकात बाद 20 को संभालेंगे कार्यभार
- सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में नेता पद के लिए निर्विरोध चुनाव

लंदन, रायटर : ब्रिटेन में हाल के हफ्तों में किंग आफ नार्थ के निकनेम से प्रसिद्ध हुए सांसद एंडी बर्नहम को सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है। इसी के साथ ब्रिटेन में उनका प्रधानमंत्री बनना अब तय हो गया है। बर्नहम सोमवार (20 जुलाई) को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल सकते हैं। जून में किएर स्टार्मर के प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने के बाद जैसे ही बर्नहम ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, उसी समय से लेबर पार्टी में उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना पैदा हो गई थी।

56 वर्षीय बर्नहम बीते दस वर्षों में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री बनेंगे। उनसे पहले के छह प्रधानमंत्रियों को विभिन्न कारणों से पूरे कार्यकाल में काम करने का मौका नहीं मिला। नेता चुने जाने के बाद बर्नहम ने कहा, वह किन्हीं कारणों से पिछड़ गए और अभावग्रस्त लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कार्य करेंगे। हम एकजुट होकर लोगों में फिर से उम्मीदें जगाएंगे और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बर्नहम ने प्रधानमंत्री के रूप में

सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी के 'स्पेशल कांफ्रेंस' से निकलते हुए एंडी बर्नहम अभिवादन स्वीकार करते हुए। एएफपी

स्टार्मर के बेहतरी के प्रयासों की प्रशंसा की। बर्नहम अब किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे और उनकी अनुमति से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह ब्रिटेन के 59 वें प्रधानमंत्री होंगे।

निकाय चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी हार स्टार्मर के असमय इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण बनी।

इजरायल में संसद भंग, आम चुनाव की तैयारी शुरू

तेल अवीव, एपी : इजरायल में 27 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व शुक्रवार को संसद विघटित हो गई। इससे पहले संसद ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के लंबित विधेयकों को पारित किया।

इजरायली संसद नीसेट का अधिवेशन ग्रीष्मावकाश के बाद शुक्रवार को ही शुरू हुआ था और कुछ घंटों की कार्यवाही के बाद उसे विघटित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब 27 अक्टूबर के चुनाव में निर्वाचित होने वाले सदस्यों से संसद के नए सदन का गठन होगा। करीब तीन महीने बाद होने वाले चुनाव तक नेतन्याहू को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना होगा और उस दौरान सरकार को बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेगी। जाहिर है गाजा और लेबनान में लड़ाई की स्थितियों और ईरान के आसन्न हमले के खतरे के बीच इजरायल के लिए यह मुश्किल दौर होगा।

चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के हमले में टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं : भारत

- अमेरिका ने इसी हफ्ते ईरान में इस बंदरगाह पर किया था हमला

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर मौजूद शहीदी बेहेश्ती टर्मिनल को अमेरिका के हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर लड़ाई भड़क गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने माना था कि ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान के तहत अमेरिका ने इस सप्ताह चाबहार बंदरगाह पर हमला किया।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट भारत और ईरान द्वारा कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। दोनों देश चाबहार पोर्ट को "इंटरनेशनल नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कारिडोर" का अहम हिस्सा बनाने की भी जोरदार वकालत कर रहे हैं। चाबहार पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से छूट अप्रैल में समाप्त हो गई थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

रणधीर जायसवाल।

भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है यह बंदरगाह

जायसवाल ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, "अमेरिका की ओर से एक छूट दी गई थी और यह कुछ समय पहले समाप्त हो गई। इसके बाद हम संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं।" कहा, "जहां तक हमले का सवाल है तो हमने इस बारे में कुछ रिपोर्ट देखी हैं, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।" जायसवाल ने चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले के बारे में एक प्रश्न पर यह जवाब दिया। चाबहार पोर्ट में भारत शहीदी बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करता है।

पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक 14 भारतीयों की मौत : आइएएनएस के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया में हालात अभी भी अस्थिर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में युद्ध के दौरान अब तक 14 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि दो अभी भी लापता हैं।

पाकिस्तान की कड़ी आलोचना : भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसे अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया था।

बलूचिस्तान में बीएलए के हमले में मारे गए 45 पाकिस्तानी सैनिक

- मस्तंग में सेना के काफिले को बनाया निशाना
- पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की

बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके। फाइल

क्वेटा, आइएएनएस : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। सैन्य बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने एक बयान में बताया कि सशस्त्र संगठन की इकाई 'फतह स्क्वाड' ने गुरुवार रात मस्तंग जिले के खदकुचा इलाके में एक समन्वित अभियान में इस हमले को अंजाम दिया। सशस्त्र संगठन ने बसों के उस काफिले को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सैनिक सवार थे। बयान के अनुसार, "अभियान में 45 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। युद्ध मैदान के मौजूदा हालात को देखते हुए मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।" बलूचिस्तान पोस्ट ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार को मस्तंग के खदकुचा इलाके में गोलीबारी की। इसमें दो लोग मारे गए और चार बच्चों समेत 11 घायल हो गए। इस महीने की शुरुआत में बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के जिवानी क्षेत्र में पाकिस्तानी तटरक्षक बल के कैंप पर हमला किया गया था। इसमें 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। बीएलए ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। उस समय बीएलए प्रवक्ता ने बताया था कि "फतह स्क्वाड" के एक सदस्य ने विस्फोटक से भरे माजदा वाहन से तटरक्षक बल के कैंप में विस्फोट किया था। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में चलाए गए एक अभियान में 24 आतंकी मारे गए।

गिलगित-बाल्टिस्तान असेंबली ने अंतरिम प्रांतीय दर्जे की मांग की

इस्लामाबाद, प्रेट्र : गिलगित-बाल्टिस्तान असेंबली ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें पाकिस्तान सरकार से मांग की गई कि इस इलाके को संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ अंतरिम प्रांतीय दर्जा दिया जाए। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को असेंबली सत्र के दौरान विधायक जलाल अली शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों का समर्थन मिला। प्रस्ताव में कहा गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान (सशक्तिकरण और स्व-शासन) आदेश 2009 ने एक चुनी हुई विधानसभा बनाई और स्व-शासन को बढ़ाया, साथ ही यह भी दोहराया कि इस इलाके का संवैधानिक विकास राज्य का एक मकसद बना हुआ है। इसमें यह भी बताया गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018 के तहत, दिवंगत नेता सरताज अजीज की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद विधानसभा को विधायी शक्तियां दी गई थीं। सदन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देकर समिति की सिफारिशों को लागू करें।

चीन पर अमेरिकी चुनाव में दखल का डोनाल्ड ट्रंप का आरोप, जांच के लिए दिए आदेश

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ट्रंप का दावा- चीन ने 22 करोड़ मतदाताओं का डाटा हासिल कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने और अपनी चुनावी हार सुनिश्चित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा से जुड़े कई गोपनीय खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने की घोषणा करते हुए कहा कि इनसे अमेरिकी चुनावी व्यवस्था में गंभीर खामियों का पता चलता है। उनका दावा है कि चीन ने अवैध तरीके से 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डाटा हासिल किया, जिसमें नाम, पते, फोन नंबर और राजनीतिक पसंद जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल थीं।

एएनआइ के अनुसार, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी खुफिया समुदाय के आकलन के अनुसार केवल चीन ही नहीं, बल्कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला ने भी अलग-अलग

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

डेमोक्रेट्स ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, खुफिया एजेंसियों में भी एकराय नहीं

स्तर पर अमेरिकी चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया। उनके मुताबिक, साइबर खतरे अब अमेरिकी लोकतंत्र के केंद्र तक पहुंच चुके हैं।

ट्रंप ने आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को 2020 में ही चीन की कथित गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी, लेकिन न तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में इसकी जानकारी दी गई और न ही कांग्रेस को अवगत कराया गया।

चैनलों पर राष्ट्रपति भड़के, लाइसेंस रद करने की दी धमकी

न्यूयार्क, रायटर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम प्राइमटाइम संबोधन दिया, लेकिन प्रमुख अमेरिकी टीवी नेटवर्क एनबीसी, एबीसी और सीएनएन ने इसे मुख्य प्रसारण प्लेटफार्म पर लाइव नहीं दिखाया। इससे नाराज ट्रंप ने कहा कि जो चैनल राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण नहीं करेंगे, उनके लाइसेंस तक रद किए जा सकते हैं। उनका भाषण चार महीने बाद होने वाले मध्यावधि चुनावों की सुरक्षा पर केंद्रित था। ट्रंप ने कहा कि एनबीसी और एबीसी जैसे "फेक न्यूज" नेटवर्क ने संबोधन का मुख्य प्रसारण नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा कि ऐसे कदम चैनलों के लाइसेंस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि समाचार संस्थानों को यह तय करने का अधिकार है कि वे किस सामग्री का प्रसारण करेंगे।

जापान में शाही परिवार के केवल पुरुष ही बन सकते हैं सम्राट, कानून पारित

- जापानी संसद ने 19वीं सदी के शाही परिवार कानून में किया ऐतिहासिक संशोधन
- राजकुमारियों को आम लोगों से शादी पर भी शाही दर्जा बनाए रखने की अनुमति

टोक्यो, एपी : जापान की संसद ने शुक्रवार को 19वीं सदी के शाही परिवार कानून में ऐतिहासिक संशोधन पारित किया। इस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि शाही परिवार के केवल पुरुष उत्तराधिकारी ही सम्राट बन सकते हैं। इससे यह आशंका पैदा हुई है कि पहले से सिकुड़ रहे शाही परिवार का भविष्य संकट में पड़ सकता है।

संसद की ओर से पारित संशोधन में भविष्य के लिए उत्तराधिकारी बनाने की खातिर दूर के पुरुष रिश्तेदारों को गोद लेना व राजकुमारियों को आम लोगों से शादी करने के बाद भी शाही दर्जा बनाए रखने की अनुमति देना शामिल है। विशेषज्ञों को आशंका है कि नए नियमों से 1500 साल पुरानी वंशानुगत संस्था समाप्त हो सकती है, क्योंकि इनमें जोर दिया गया है कि केवल पुरुष उत्तराधिकारी ही सम्राट बन सकते हैं।

राजकुमारी आइको काफी लोकप्रिय, पर नहीं बन सकेंगी उत्तराधिकारी : मौजूदा 66 वर्षीय सम्राट नारुहितो की 24 साल की बेटी राजकुमारी आइको लोकप्रिय हैं और कई जापानी चाहते हैं कि वह उनकी उत्तराधिकारी बनें, लेकिन महिला होने के कारण राजकुमारी पात्र नहीं हैं।

शाही परिवार के ये सदस्य हैं उत्तराधिकार की कतार में : उत्तराधिकार के लिए केवल पुरुषों को ही चुने जाने का मतलब है कि सम्राट के छोटे भाई और उनके 19 वर्षीय भतीजे राजकुमार हिसाहितो उत्तराधिकार की कतार में होंगे। उनके बाद इस क्रम में सम्राट के 90 वर्षीय चाचा आते हैं।

शाही परिवार में लड़कों को बहुत अहमियत दी जाती है और हिसाहितो पिछले चार दशक में पैदा होने वाले इकलौते लड़के हैं।

मैक्सिको तट पर 7.4 तीव्रता का आया भूकंप

ग्वाटेमाला सिटी, रायटर : मैक्सिको तट के पास शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। इसे ग्वाटेमाला व अल साल्वाडोर में भी महसूस किया गया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों ने तुरंत किसी नुकसान की सूचना नहीं दी है।

अमेरिकी जियोलाजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप मैक्सिको के शहर प्यूर्टो मडेरो के पास आया और इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके के बाद चेतावनी जारी की गई कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तटों पर सुनामी लहरें उठ सकती हैं। भूकंप आने पर ग्वाटेमाला सिटी में लोग इमारतों से बाहर आ गए। अल साल्वाडोर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका के गवर्नर सैलोमन जारा ने कहा कि राज्य की राजधानी में भूकंप के झटके मध्यम तीव्रता के साथ महसूस किए गए, लेकिन तुरंत किसी गंभीर नुकसान की खबर नहीं मिली।

बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या का आरोपित सेना के हवाले

- हत्या के 45 साल से अधिक समय बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया
- पुलिस से बचने के बाद आरोपित लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा था

ढाका, एएनआइ : बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के मामले में फरार आरोपित मेजर (रिटायर्ड) मुजफ्फर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 77 वर्षीय हुसैन को गुरुवार को सेना को सौंप दिया। उसे ढाका के बनानी इलाके में एक घर से गिरफ्तार किया गया। मई 1981 में चट्टोग्राम के सर्किट हाउस में जिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश सरकार ने उस पर इनाम की घोषणा की थी। हत्या के 45 साल से अधिक समय बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद से ही मेजर मुजफ्फर हुसैन अपना ठिकाना बदलता रहा। डिटेक्टिव ब्रांच ने खुफिया सूत्रों और तकनीक का इस्तेमाल कर उसकी लोकेशन का पता लगाया। एक टीम ने छापा मारकर 15 जुलाई को रात 10:10 बजे (स्थानीय समय) बनानी के एक घर से उसे गिरफ़्तार किया। पूछताछ में उसकी पहचान की पुष्टि की गई और तुरंत आर्म्ड फोर्सेज डिवीजन को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने कहा, "16 जुलाई को शाम 6:10 बजे (स्थानीय समय), कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे सेना को सौंप दिया गया।" पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के पिता थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के पति थे। लेफ़्टिनेंट जनरल ज़ियाउर रहमान 'बीर उत्तम' (1936-1981) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। वे सेना प्रमुख थे और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने बांग्लादेश में बहु-दलीय लोकतंत्र की शुरुआत की और बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। 19 नवंबर 1976 को जब जस्टिस सायेम ने अपना पद छोड़ा, तो जियाउर रहमान 'चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर' बने और 21 अप्रैल 1977 को जब राष्ट्रपति सायेम ने इस्तीफा दिया, तो वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने।

ढाका में पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते बीएनपी कार्यकर्ता। फाइल

बंगाल की खाड़ी में दो नौकाएं डूबने से 500 से अधिक रोहिंग्या की मौत की आशंका

सिडनी, एपी : म्यांमार से सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकले रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ समुद्री हादसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या समुदाय को लेकर जा रही दो नावें डूब गईं। हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, हालांकि मरने वालों की आधिकारिक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आइओएम) और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के अनुसार, दोनों नावें जून के आखिर में म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य से रवाना हुई थीं। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे, जबकि कुछ लोग बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से भी आए थे। पहली नौका में करीब 250 लोग सवार थे, जिसका रवाना होने के कुछ समय बाद संपर्क टूट गया। दूसरी नौका में लगभग 280 लोग थे, जिसके आठ जुलाई को म्यांमार के अयेयारवाडी तट के पास डूबने की आशंका है।

सांत्वना पुरस्कार के लिए भिड़ेंगे फ्रांस और इंग्लैंड

फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान का मुकाबला आज सेमीफाइनल में हारी टीमें होंगी आमने-सामने

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: बहुत पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास... फीफा विश्व कप 2026 में यही हाल फ्रांस और इंग्लैंड का है। विश्व विजय की आकांक्षा लेकर अमेरिकी महाद्वीप पहुंचे ये देश अब तीसरे स्थान के मुकाबले में एक-दूसरे के सामने होंगे। फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन से हार मिली तो इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने हराकर बाहर भेजा अब घर जाने से पहले एक आखिरी चुनौती में दोनों ही देश अपना सबकुछ झोंकने को तैयार हैं। फीफा विश्व कप के फाइनल में ना जाने का दुख इस जीत से कम करने की इनकी कोशिश कितनी सफल होगी, ये वक्त ही बताएगा। मौजूदा स्थिति ये है कि दोनों टीमों को पिछले मैच में मिडफील्ड में मात मिली और इस बार उनके पास मौका है कि वो इस गलती को सुधारें और दो हारी हुई मिडफील्ड में से किसी एक के सर विजय का ताज आए।

सेमीफाइनल में हारने तक टूर्नामेंट की विजेता मानी गई फ्रांस की टीम ने इस विश्व कप में सिर्फ एक मैच गंवाया लेकिन ये हार इतनी बड़ी है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती जबकि इंग्लैंड साल 1966 में विश्व कप जीतने के बाद से लगातार कोशिशें ही कर रहा है।

इन्होंने खिलाड़ी से लेकर कोच तक बदलकर देख लिया लेकिन ट्राफी घर आने का नाम नहीं ले रही, आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि इंग्लैंड ने ही दुनिया को क्रिकेट की तरह आधुनिक फुटबाल के खेल से भी परिचित कराया था और इसीलिए उनका मानना है कि यही देश विश्व कप ट्राफी का घर है। ये हर बड़े टूर्नामेंट से पहले बड़े जोर से कहते हैं- इट्स कमिंग होम यानी ये घर आ रही है। हालांकि, आखिरी बार फुटबाल की कोई बड़ी ट्राफी साल 1966 में ही इंग्लैंड आई थी।

हैरी केन

काइलियन एमबापे

इंग्लैंड की रणनीति

इंग्लैंड की टीम अति आक्रामक फुटबाल खेलने की कोशिश करती है, ऐसा सेमीफाइनल से पहले सबको लगता था फिर इंग्लैंड ने दिखाया कि वो अति कायर फुटबाल खेलते हैं। इस रणनीति की बहुत आलोचना हुई उनके जर्मन कोच थामस ट्यूशेल को काफी कुछ कहा गया लेकिन ये किसी को याद नहीं रहा कि 2018 फीफा विश्व कप का फाइनल और 2024 यूरो का फाइनल इंग्लैंड ने ठीक ऐसे ही गंवाया था। दोनों बार 1-0 की बढ़त के बाद टीम ने अपना किला बचाने के नाम पर ऐसी कायरता दिखाई कि मैच हार गए। रणनीति पर लौटें तो ये दो विंगर्स को लगातार विपक्षी टीम पर अटैक करने के लिए उतारते हैं और ज्यादातर मौकों पर ये सफल भी रहते हैं। इनके स्ट्राइकर हैरी केन और अटैकिंग मिडफील्डर जूड बेलिंघम ने इस विश्व कप में छह-छह गोल किए हैं। टीम को इन्हीं से ज्यादा उम्मीद रहती है।

6 गोल किए हैं इस विश्व कप में स्ट्राइकर हैरी केन और अटैकिंग मिडफील्डर जूड बेलिंघम ने, दोनों खिलाड़ियों के नाम एक-एक असिस्ट भी हैं

14 गोल के साथ इस विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में नंबर तीन पर है इंग्लैंड की टीम, इसके लिए इन्होंने 41 बार निशाने पर शाट मारे हैं

संभावित शुरुआती 11

जार्डन पिकफोर्ड, एजरी कोंसा, जान स्टोंस, मार्क गुही, निको ओ राइली, कोबी मेनू, एलियट एंडरसन, नोनी मदुएके, जूड बेलिंघम, एंथनी गोर्डन, हैरी केन

फ्रांस की रणनीति

फीफा विश्व कप 2026 में काइलियन एमबापे ही फ्रांस की रणनीति का केंद्र हैं। वह ना सिर्फ तेजी से आगे बढ़ते हैं बल्कि मिले मौकों को भुनाने में भी उनके जैसे कम ही खिलाड़ी होंगे। फ्रांस की टीम ना सिर्फ अटैकिंग फुटबाल खेलती है बल्कि अगर इन पर हमला हो और किसी तरह से ये गेंद छीन पाएं तो काउंटर अटैक करने में भी इनका कोई सानी नहीं है। विंग पर ओस्मान डेंबेले और माइकल ओलीसे अपनी कलाकारी, सटीक पासिंग/क्रासिंग से एमबापे का काम और आसान कर देते हैं। हालांकि स्पेन के विरुद्ध इनकी मिडफील्ड कुछ नहीं कर पाई थी लेकिन बाकी टूर्नामेंट में इन्होंने ठीक काम किया है।

19 जुलाई का मैच

इंग्लैंड *vs* फ्रांस

स्थान: मियामी समय: 2:30 एएम

प्रसारण: युनाइट8 1 व 2 स्पोर्ट्स, जी5

8 गोल और तीन असिस्ट कर चुके हैं काइलियन एमबापे इस विश्व कप में, गोल्डन बूट की रेस में वह सिर्फ मेसी से पीछे हैं

16 गोल किए हैं फ्रांस ने इस विश्व कप में, इस मामले में इनसे आगे बस अर्जेंटीना की टीम है, जिन्होंने 19 गोल मारे हैं

संभावित शुरुआती 11

माइक मेंयोन, जूल्स कूंडे, दायोत उपामेकानो, मैक्सेंस लैक्रोइक्स, थियो हर्नांडेज, मनु कोने, एड्रियन राबियो, माइकल ओलीसे, ओस्मान डेंबेले, डिजायर डू, काइलियन एमबापे

अर्जेंटीना को फीफा की मदद मिलने के आरोपों पर भड़के लियोन मेसी

कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला: मेसी

अटलांटा, एपी: अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोन मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 के दौरान उनकी टीम पर फीफा की मदद के आरोप लगा रहे लोगों को दो टूक जवाब दिया है। मेसी ने स्पष्ट कहा है कि उनकी टीम को कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला। मेसी ने कहा कि मैच के अंतिम पलों में परिणाम बदलने की क्षमता टीम की विजेता बनने की काबिलियत का नतीजा है और कुछ नहीं।

इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल में अर्जेंटीना 84 मिनट तक 0-1 से पीछे थी लेकिन आखिरी के मिनटों में दो गोल मारकर टीम ने मैच को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जमकर जश्न मनाया गया। टीम ने फीफा विश्व कप के नाकआउट चरण में लगातार ऐसे मैच जीते हैं। इन्होंने केप वर्दे और स्विट्जरलैंड को अतिरिक्त समय में मात दी जबकि मिस्र के विरुद्ध ज्यादातर वक्त 0-2 से पीछे रहने के बाद मुकाबला 3-2 से जीता।

मैच के बाद स्विट्जरलैंड और मिस्र दोनों टीमें के कोचों ने मैच रेफरी की आलोचना की और उनके फैसलों पर सवाल उठाए। मिस्र के होसैम हसन ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी टीम फीफा का शिकार बनी, फीफा ने मेसी और अर्जेंटीना के फायदे के लिए मिस्र के साथ पक्षपात किया। इन मैचों के बाद इंटरनेट मीडिया पर अर्जेंटीना के आलोचकों की बाढ़ आ गई, लोगों ने पूरे विश्व कप को ही भ्रष्ट बता दिया। इंग्लैंड के विरुद्ध जीत के बाद मेसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। वह बोले, पीछे चार सालों में हम अपने सर्वश्रेष्ठ पर रहे हैं, फिर चाहे आपको ये बात पसंद आए या ना, किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर हमने दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों में अपनी जगह बना ली है। ये बताता है कि हमने जो कुछ भी किया वो कोई तुक्का नहीं था, हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला। मेसी ने ये भी कहा कि लगातार दो बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचना एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम देश हासिल कर पाते हैं और हम लोगों ने ये किया है। अगर हम इंग्लैंड से हार जाते तो कुछ लोग आते और बकवास बातें कहते लेकिन हमने उनको मौका नहीं दिया। अर्जेंटीना की टीम रविवार देर रात होने वाले फाइनल में स्पेन का सामना करेगी, स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

लियोन मेसी • फाइल फोटो

फाइनल मैच देखने अमेरिका नहीं जाएंगे अर्जेंटीनी राष्ट्रपति

ब्यूनस आयर्स: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई अंधविश्वास के कारण विश्व कप फाइनल देखने के लिए न्यू जर्सी नहीं जाएंगे और वह अपनी टीम का मैच घर में बैठकर ही देखेंगे। उन्होंने अर्जेंटीना के पिछले सातों मैच भी घर से ही देखे थे। मौजूदा चैंपियन इन सभी मैच में जीत हासिल करने में सफल रहा था। इन मैच के दौरान मिलेई ने एक खास जैकेट पहनी थी और उन्होंने कहा कि फाइनल के दिन भी वह इसी जैकेट को पहनकर मैच देखेंगे। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए इस मैच में खेलेगा। दुनियाभर के प्रशंसक और खिलाड़ी अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनकी टीम का भाग्य बदल सकते हैं।

स्लावको विंसिक होंगे फाइनल में मुख्य रेफरी

न्यूयार्क, आइएएनएस: फीफा ने विश्व कप 2026 के फाइनल मैच के लिए रेफरी के नाम की घोषणा कर दी है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में स्लोवेनिया के अनुभवी अधिकारी स्लावको विंसिक मुख्य रेफरी की भूमिका निभाएंगे। फीफा के रेफरी प्रमुख पियरलुइगी कोलिना ने इस नियुक्ति पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए अनुभवी और योग्य रेफरी का होना बेहद जरूरी है। विंसिक को इस महत्वपूर्ण मैच की जिम्मेदारी मिलना उनके शानदार करियर को दिखाता है। फीफा के अनुसार, फाइनल में स्लावको विंसिक की सहायता के लिए टोमाज क्लैंचनिक असिस्टेंट रेफरी-1 और एंड्राज कोवाचिक असिस्टेंट रेफरी-2 की भूमिका निभाएंगे। वहीं, अधम मखादमेह चौथे अधिकारी और मोहम्मद अल्कालाफ रिजर्व असिस्टेंट रेफरी होंगे। 46 साल के विंसिक का यह पहला बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल होगा। उन्होंने 2022 में कतर वर्ल्ड कप से अपने विश्व कप करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने दो मैचों में रेफरी की जिम्मेदारी संभाली थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी वह अब तक तीन मैचों में रेफरी रह चुके हैं। फाइनल उनके विश्व कप करियर का छठा मुकाबला होगा। विंसिक के करियर में कई बड़े मुकाबले शामिल हैं। वह यूईएफए 2024 चैंपियंस लीग फाइनल में भी थे, जिसमें रीयल मैड्रिड और बोरुसिया डोर्टमंड आमने-सामने थे। इसके अलावा वह यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप क्वालीफायर, यूरोपा लीग, नेशंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप में भी रेफरी रह चुके हैं।

खिलाड़ी को घूस देने के आरोप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गिरफ्तार

कोलंबो, प्रेट्र: लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) फ्रेंचाइजी जाफना किंग्स के सह-मालिक और भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर को शुक्रवार को श्रीलंका की खेल भ्रष्टाचार रोधी जांच इकाई ने एक खिलाड़ी को रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी टूर्नामेंट के छठे चरण के शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई। मामले में संदिग्ध मनजोत कालरा हैं जिन्होंने 2018 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में शतक जड़ा था जिससे टीम यह मैच जीत गई थी। उन्हें खेलों से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विशेष जांच इकाई ने गिरफ्तार किया और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। 27 साल के कालरा ने खेल उद्यमिता में कदम रखते हुए इस साल की शुरुआत में जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी में निवेश किया था। श्रीलंकाई पुलिस के अनुसार कालरा पर टूर्नामेंट के सिलसिले में पैसे का लालच देकर एक खिलाड़ी को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है।

अफगानिस्तान सीरीज के बाद ही रोहित को ड्राप करना चाहते थे चयनकर्ता

अभिषेक त्रिपाठी • जागरण

- 2027 में वनडे विश्व कप में रोहित की जगह यशस्वी को देना चाहते हैं मौका
- संन्यास लेने के मूड में नहीं हैं रोहित, अब तक टीम प्रबंधन को नहीं दी है कोई सूचना

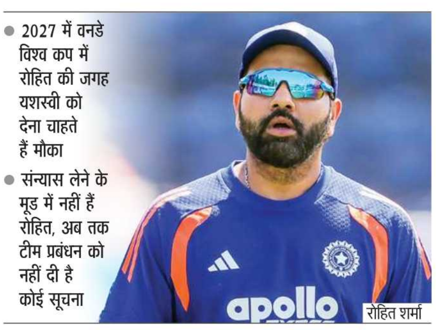

रोहित शर्मा

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखे जाने की आहट सुनाई दे रही है। पिछले डेढ़ दशक में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले रोहित शर्मा का भविष्य अधर में है। अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अवसर देना चाहती है। हालांकि 513 अंतरराष्ट्रीय मैच में 20289 रन और सभी प्रारूपों में 50 शतक लगाने वाले रोहित ने अभी तक टीम प्रबंधन को यह सूचित नहीं किया है कि वह लाड्र्स वनडे के बाद संन्यास लेंगे या नहीं। रोहित फिलहाल संन्यास लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। चयन समिति उन्हें अफगानिस्तान के विरुद्ध घर में खत्म हुई वनडे सीरीज के बाद ही ड्राप करना चाहते थे लेकिन बीसीसीआइ ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज तक के लिए मोहलत दे दी थी।

अजित अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति भविष्य की सबसे मजबूत वनडे टीम तैयार करना चाहती है जो दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 वनडे विश्व कप में खिताब की दावेदार बन सके। चयनसमिति से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि आप कब तक यशस्वी को बाहर बैठाओगे, ये उसके साथ अत्याचार है। उसने पिछले तीन मैचों में दो शतक लगाए लेकिन उसको बाहर बैठना पड़ रहा है। 2023 में रोहित का गेम देखिए और अब देखिए। ऐसा लग रहा है कि रोहित अब टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं। हमने 2011 के बाद से वनडे विश्व कप नहीं जीता है। हमें अगले साल उस ट्राफी को जीतने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। अगर यशस्वी विश्व कप में खेलें तो उससे पहले उन्हें कम से कम 20 वनडे खेलने होंगे। हमने तय किया है कि अगली वनडे सीरीज में रोहित को नहीं चुनेंगे। ये बात उन्हें बता दी गई है। अब वह संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे ये उनका निर्णय होगा। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

रिश्ते सहज नहीं: रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के बीच रिश्तों में लंबे समय से पूरी सहजता नहीं रही है। पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में स्थिति अलग थी। द्रविड़ ने 2023 वनडे विश्व कप और 2024 टी-20 विश्व कप जैसे अभियानों के दौरान रोहित और अगरकर के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखा था। भारत ने रोहित की कप्तानी में टी-20 विश्व कप भी जीता था। हालांकि अब रोहित की बल्लेबाजी पहले जैसी नहीं रही और ऐसे में स्थितियां बदलती गईं। 2024 आइपीएल के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले से पहले रोहित ने खुद गौतम गंभीर से भारतीय टीम से जुड़ने का आग्रह किया था।

आस्ट्रेलिया दौरे से बढ़ी दूरियां: रोहित की कप्तानी में न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-3 की हार और फिर आस्ट्रेलिया में बार्डर गावस्कर ट्राफी में हार ने रोहित के कद को कम किया। खराब फार्म के कारण बार्डर-गावस्कर ट्राफी के दौरान रोहित ने कप्तान रहते हुए खुद को अंतिम एकादश से अलग कर लिया। चयनकर्ताओं ने उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी क्योंकि इससे इंग्लैंड दौरे के लिए उनके चयन पर असर पड़ सकता था। रोहित नहीं माने और चयनकर्ताओं ने रोहित से अलग होने का फैसला कर लिया। इंग्लैंड में पिछले साल टेस्ट सीरीज से पहले विराट और रोहित दोनों ने क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप से संन्यास ले लिया था। चैंपियंस ट्राफी जीतने के बावजूद जब अगले ही वनडे दौरे से पहले रोहित शर्मा से कप्तानी वापस ले ली गई तो वह बेहद निराश हुए। अगरकर ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि चयनकर्ता अब 2027 विश्व कप को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस फैसले पर गंभीर और अगरकर एकमत थे। इसके बाद रोहित का एकमात्र लक्ष्य 2027 वनडे विश्व कप खेलना था, लेकिन टीम प्रबंधन और चयन समिति ने इस पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। लगातार अनिश्चितता और संवाद की कमी का असर उनकी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी पर भी पड़ा और हालिया वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। अब सबकी नजरें लाड्र्स वनडे पर हैं।

जब तक रोहित योजना का हिस्सा हैं टीम में बने रहेंगे: सैकिया

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीसीसीआइ ने शुक्रवार को रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इंग्लैंड के विरुद्ध रविवार को लाडर्स पर तीसरा वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है। बीसीसीआइ सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि लाडर्स पर रविवार को रोहित आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि रोहित रविवार को लाड्र्स पर अपना आखिरी मैच खेलेगा। उन्होंने कहा कि रोहित भारतीय वनडे टीम का नियमित सदस्य है और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिए खेलता रहेगा। दूसरे शब्दों में लाड्र्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है।

इससे पहले अटकलें लगाई जा रही है कि लाड्र्स वनडे रोहित का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा, क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता उन्हें बता चुके हैं कि वह 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम की योजनाओं का हिस्सा नहीं है।

देवाजीत सैकिया

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली-गंभीर: कोटक

कार्डिफ, प्रेट्र: भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बीच बातचीत नहीं होने की खबरों को कोरी अफवाह करार देते हुए कहा कि अभ्यास सत्र के दौरान भले ही वे एक-दूसरे से दूर-दूर दिखाई दें, लेकिन वे दिन में 10 बार बात करते हैं। बर्मिंघम और कार्डिफ में अभ्यास सत्रों के दौरान भी दोनों को आपस में बातचीत करते नहीं देखा गया। कोहली कोटक से बात करते देखे गए थे।

खेल डायरी

सिंधू जापान ओपन के सेमीफाइनल में

टोक्यो, प्रेट्र: दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू करीब तीन साल में पहली बार सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई, जब शुक्रवार को जापान ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल से पहले पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने नाम वापिस ले लिया। 2019 विश्व चैंपियन सिंधू आखिरी बार 2023 डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंची थी। इस सत्र में वह मलेशिया ओपन सुपर 1000 और आस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। ओकुहारा को प्री क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की अन सि यंग के नाम वापिस लेने के बाद अंतिम आठ में प्रवेश मिला था। सिंधू अब टोक्यो ओलिंपिक चैंपियन चेन युफेइ से खेलेंगी।

हंसिका ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में जीता रजत

बुडापेस्ट, प्रेट्र: अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हंसिका लांबा ने पोल्याक इमरे, वर्गा जानोस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 55 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। हंसिका ने सेमीफाइनल में शानदार वापसी करते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। उन्होंने जर्मनी की अनास्तासिया ब्लेवास के विरुद्ध 2-7 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए वापसी करके 10-7 से जीत हासिल की। लेकिन स्वर्ण पदक मुकाबले में हंसिका यूक्रेन की मजबूत प्रतिद्वंद्वी नतालिया क्लीवचुत्स्का को कड़ी टक्कर देने के बावजूद पाइंट्स (वीपीओ) के आधार पर 0-5 से हार गईं जिससे उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। हंसिका के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक और उपलब्धि है, इससे पहले उन्होंने 2026 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।

पेले की जर्सी 47 करोड़ रुपये में बिकी

पूर्व फुटबालर पेले की जर्सी • रायटर

न्यूयार्क, एपी: ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले ने 1958 के विश्व कप फाइनल में जो 10 नंबर की जर्सी पहनी थी, वह नीलामी में 49 लाख डालर (लगभग 47 करोड़ 21 लाख रुपये) में बिक गई है। नीलामीकर्ता सोथबीज ने यह जानकारी दी। पेले उस समय 17 वर्ष के थे जब उन्होंने रासुंडा स्टेडियम में मेजबान स्वीडन पर ब्राजील की 5-2 की जीत में दो गोल किए थे। सोथबीज ने कहा कि ब्राजील के स्टार खिलाड़ी द्वारा पहनी गई जर्सी अब तक बेची गई दूसरी सबसे महंगी फुटबाल जर्सी है। डिएगो माराडोना की 1986 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध पहनी गई 'हैंड आफ गाड' जर्सी 2022 में 93 लाख डालर (अब 89 करोड़ रुपये) में बिकी थी।

क्रिकेट के महानतम आलराउंडर सर गैरी सोबर्स नहीं रहे

स्मृति शेष

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, 1954 में किया था टेस्ट पदार्पण, बचपन में खेलते थे लिलिपुटियन क्रिकेट

सर गैरी सोबर्स • एक्स

ब्रिजटाउन, रायटर: क्रिकेट इतिहास के सबसे महान आलराउंडरों में से एक सर गैरी सोबर्स का शुक्रवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को उनके निधन की पुष्टि की, हालांकि मौत के कारण का खुलासा नहीं किया गया। अपनी बेजोड़ बल्लेबाजी, हर तरह की गेंदबाजी और शानदार क्षेत्ररक्षण के दम पर सोबर्स ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विजडन अल्मनैक ने उन्हें 20वीं सदी के पांच महानतम क्रिकेटरों में शामिल किया था, जबकि महान बल्लेबाज सर डान ब्रैडमैन ने उन्हें अपने समय का सर्वश्रेष्ठ आलराउंडर बताया था।

28 जुलाई 1936 को बारबाडोस के सेंट माइकल में जन्मे गैरी सोबर्स का पूरा नाम गारफील्ड सेंट आबर्न सोबर्स था। उनका जन्म दोनों हाथों में एक-एक अतिरिक्त अंगुली के साथ हुआ था। बचपन में उन्होंने खुद ही तेज चाकू और कैटगट (सर्जिकल टांका) की मदद से इन अतिरिक्त अंगुलियों को हटा दिया। सोबर्स का बचपन संघर्षों से भरा रहा। जब वह केवल पांच वर्ष के थे, तब कनाडाई मर्चेंट नेवी में नाविक उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले में मारे गए। उनकी मां थेल्मा ने अकेले ही छह बच्चों का पालन-पोषण किया। सोबर्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद बच्चों की पढ़ाई, भोजन और पालन-पोषण में कभी कमी नहीं आने दी।

फुटबाल और बास्केटबाल में भी प्रतिभाशाली सोबर्स का पहला प्यार क्रिकेट था। बचपन में वह सड़क और समुद्र तट पर 'लिलिपुटियन क्रिकेट' खेलते थे, जिसमें तार की गेंद और लकड़ी के टुकड़े से बने बल्ले का इस्तेमाल होता था। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने बारबाडोस के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और 1954 में वेस्टइंडीज के लिए पहला टेस्ट खेला। 21 वर्ष की आयु में पाकिस्तान के विरुद्ध अविजित 365 रन बनाकर उन्होंने उस समय टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। वह आज भी टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं।

छह गेंद में जड़े थे छह छक्के: 1965 में सोबर्स वेस्टइंडीज के कप्तान बने। 1968 में नाटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए उन्होंने ग्लैमरगन के मैल्कम नैश के एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। सोबर्स बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी में माहिर थे और मैदान के किसी भी हिस्से में क्षेत्ररक्षण करते थे।

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दी थी नाइटहुड की उपाधि: 1975 में क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि से सम्मानित किया। 1998 में उन्हें बारबाडोस के 10 आधिकारिक राष्ट्रीय नायकों में शामिल किया गया और उनके सम्मान में सर गारफील्ड सोबर्स स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण किया गया। द. अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला भी उन्हें अपने पसंदीदा क्रिकेटरों में गिनते थे।

सर गारफील्ड सोबर्स का करियर

प्रारूप	मैच	रन	औसत	50/100	विकेट
टेस्ट	93	8032	57.78	30/26	235
वनडे	1	0	-	0/0	1

दुनिया के महान क्रिकेटर अब हमारे बीच नहीं रहे। सर गारफील्ड सोबर्स जैसे क्रिकेटर के बारे में कुछ भी कहना कम ही होगा। वे वो सब कुछ थे जो हम बचपन में बल्ला या गेंद उठाते समय बनने का सपना देखते हैं। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं और मैं उन्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा।
-**सुनील गावस्कर**, पूर्व भारतीय कप्तान

विश्व क्रिकेट की बड़ी हस्ती और खेल के सच्चे लीजेंड सर गारफील्ड सोबर्स के निधन से बहुत दुख हुआ है। आइसीसी ने लंबे समय से उनके सम्मान में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम उनके नाम पर रखा है।
- **जय शाह**, चेयरमैन, आइसीसी

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

दैनिक जागरण
सप्तरंग
जोश नई राहों का
शनिवार, 18 जुलाई, 2026

तैयारी की रणनीति का फिर से करें विश्लेषण

काउंसलर
अशोक सिंह
councelor@nda.jagran.com

जाब के लिए बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और विभिन्न प्रदेशों की कर्मचारी चयन आयोगों की चयन परीक्षाएं दे रहा हूं, लेकिन अब तक सफल नहीं हो सका हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

सुनील कुमार

असफलताओं से निराश होने के बजाय कारणों को समझें और अपनी तैयारी की रणनीति का विश्लेषण करें। पिछले प्रश्नपत्रों और माक टेस्ट के माध्यम से अपनी कमजोरियों की पहचान करें तथा नियमित अभ्यास करें। समय प्रबंधन, सटीकता और पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो किसी अच्छे मार्गदर्शन या कोचिंग की सहायता लें। इस बारे में सफल साथियों द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटेजी को भी ध्यान में रखें। इसके साथ ही, अन्य करियर विकल्पों और कौशल विकास पर भी ध्यान दें, ताकि रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध रहें।

12वीं के बाद एडमिशन के लिए संस्थान को ज्यादा महत्व दें या या कोर्स को?

नीलाभ यादव

12वीं के बाद प्रवेश लेते समय केवल संस्थान या केवल कोर्स में से किसी एक को अधिक महत्व देना उचित नहीं है। सबसे पहले अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य के अनुसार सही कोर्स चुनना चाहिए, क्योंकि वही आपके करियर की दिशा तय करता है। इसके बाद उस कोर्स के लिए अच्छे शिक्षकों, सुविधाओं, प्लेसमेंट और प्रतिष्ठा वाले संस्थान का चयन करना चाहिए। यदि किसी प्रसिद्ध संस्थान में मनपसंद कोर्स नहीं मिल रहा है तो केवल नाम के कारण प्रवेश नहीं लेना चाहिए, इसलिए सफल भविष्य के लिए कोर्स और संस्थान दोनों का संतुलित चयन सबसे बेहतर निर्णय होता है।

मुझे केमिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से किसका चुनाव करना चाहिए?

प्रज्ञा अग्रवाल

वर्तमान समय में यदि दोनों में से एक कोर्स चुनना हो, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अधिक लाभदायक कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि एआइ, साइबर सुरक्षा, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, केमिकल इंजीनियरिंग भी पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा और विनिर्माण उद्योगों में महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरियां अपेक्षाकृत सीमित हैं। यदि आपकी रुचि कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग और नई तकनीकों में है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेहतर विकल्प है। वहीं, औद्योगिक प्रक्रियाओं में रुझान रखने वाले छात्रों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग उपयुक्त रहेगी।

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें-feature@jagran.com

टर्निंग प्वाइंट

नए अवसरों के निर्माता बनें युवा

एआइ, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स या डाटा साइंस जैसी तकनीकें आज केवल नए करियर के विकल्प नहीं हैं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने के प्रभावी माध्यम भी बन चुके हैं। कैसे युवा इन तकनीकों के इस्तेमाल से तमाम समाधान निकाल सकते हैं, बता रहे हैं आइआइटी रांची के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव...

फोटो : मैग्नीफिक

आज के युवाओं के सामने बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भविष्य में उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी, बल्कि यह है कि तकनीकों की मदद से वे भविष्य की किन चुनौतियों का समाधान कर सकेंगे। भारत सहित पूरी दुनिया आज कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच, कृषि की चुनौतियां, शिक्षा में असमानता, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता, जल संरक्षण, सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बुजुर्गों की देखभाल, दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी समाधान और आपदा प्रबंधन जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां युवा अपने सोच और नवाचार के माध्यम से बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

नवाचार के बारे में सोचें युवा: कल्पना कीजिए कि कोई छात्र ऐसा एआइ आधारित माडल विकसित करे, जो शुरुआती चरण में ही गंभीर बीमारियों की पहचान कर सके। कोई कंप्यूटर विजन की मदद से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने वाली स्मार्ट प्रणाली तैयार करे। कोई युवा किसानों को फसल के रोगों की समय रहते जानकारी देने वाला समाधान विकसित कर सके या फिर ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म बनाए, जो दूर-दराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचा सके। ऐसे नवाचार केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं होते, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बनते हैं। तकनीक का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि जीवन को सरल, सुरक्षित और बेहतर बनाएं।

सीखें नई तकनीकें: कई युवा नई-नई तकनीकों को सीखने में अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हैं, जो निश्चित रूप से जरूरी भी है, लेकिन केवल तकनीक सीखना ही पर्याप्त नहीं है। उससे अधिक महत्वपूर्ण है अपने आसपास की समस्याओं को समझना, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानना और तकनीक के प्रयोग से उनका समाधान निकालना। जो युवा केवल तकनीक का उपयोग करना सीखते हैं, वे अच्छे पेशेवर जरूर बनते हैं, लेकिन जो तकनीक के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास करते हैं, वही भावी परिवर्तनकारी नेता बनते हैं।

खुद को पहचानें: भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, जो केवल अवसरों की तलाश न करें, बल्कि नए अवसरों का निर्माण भी करें। आने वाले वर्षों में सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो बदलती तकनीकों के साथ स्वयं को लगातार सीखने के लिए तैयार रखेंगे। जरूरत के अनुसार नवाचार करेंगे।

(जैसा सुमन अग्रवाल को बताया)

ध्यान देने योग्य बातें

1. समस्याओं को केवल शिकायत की तरह नहीं, बल्कि समाधान विकसित करने के अवसर के रूप में देखें।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़कर देखें।
3. स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचार व तकनीकी समाधान विकसित करने का प्रयास करें।
4. केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच, संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और टीमवर्क भी विकसित करें।
5. ऐसा कार्य करें, जिससे केवल आपका करियर ही नहीं, बल्कि समाज और देश का भविष्य भी बेहतर बन सके।

वर्ग पहेली-3399

बाएं से दाएं:
1. पक्षियों की चहक (4)। 5. आय-व्यय का विवरण, बही (2)। 6. जलाने की क्रिया (3)। 8. विघ्न, बाधा (3)। 9. इसे सफेद चींटी भी कहते हैं (3)। 10. चार वेदों में से एक (4)। 12. धमकी देना, डराना (4)। 14. उल्टी, कै (3)। 16. गाना, गीत, सुरीली आवाज (3)। 17. प्यारा, दुलारा (3)। 19. पवित्र (2)। 20. दुर्बल, जर्जर (4)।

ऊपर से नीचे:
2. स्त्री, औरत, प्रेमिका (3)। 3. प्रातः, भोर (3)। 4. बच्चों की एक प्रसिद्ध पत्रिका (4)। 5. सिखों का एक प्रमुख समुदाय (3)। 6. यह जगह है पश्चिम बंगाल में (4)। 7. सरिता (2)। 11. यहां नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है (4)। 13. सिखों के एक गुरु (3)। 14. कम बोलने वाला (4)। 15. अभिनय, रहस्य से भरा (2)। 18. रास्ता, पथ (3)। 19. कार्टून कैरेक्टर पोपाय को इसे खाने से मिलती है ताकत (3)।

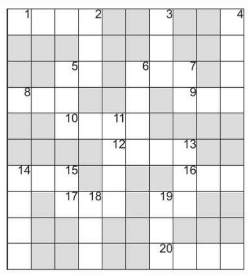

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

		श	प	थ			खे		
	ब		रि		ता	र	त	म्य	
खा	ल		मा	सि	क				वि
	वा		र्ज		ना	च	न	चा	ना
	न	य	न				मा		श
ल		ती				ब	ज	ना	
प	र	म	वी	र		ह		रा	
ट				क	ह	र		ज	ग
	गु	मे	ना	म		हा		गी	
		न			अ	ल	ग		

सुडोकू-3399

	3				1		6	
8	7		5		4		3	
		5		3		1		8
6			9					
	2			5	6	7		9
7		9	1				5	
	4		3		2			7
				4				
2		6		1		8		3

कल का हल

4	5	6	3	2	1	9	8	7
1	2	3	9	8	7	4	5	6
7	8	9	6	5	4	1	2	3
8	9	4	5	6	3	7	1	2
2	3	7	8	1	9	6	4	5
5	6	1	4	7	2	3	9	8
6	4	8	7	9	5	2	3	1
3	1	5	2	4	6	8	7	9
9	7	2	1	3	8	5	6	4

आज का भविष्यफल : 18 जुलाई, 2026 शनिवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी का राशिफल।
आज का राहुकाल : प्रात : 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : पूर्व। **विशेष :** चतुर्थी तिथि की वृद्धि।

कल 19 जुलाई, 2026 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : स्कंद षष्ठी।
विक्रम संवत 2083 शके 1948 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी 27 घंटे 31 मिनट तक तत्पश्चात सप्तमी, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र तत्पश्चात हस्त नक्षत्र, परिघ योग तत्पश्चात शिव योग, कन्या में चंद्रमा।

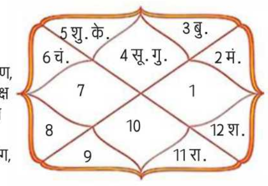

मेष : पारिवारिक तनाव आ सकता है। आर्थिक मामलों में उलझने रहेंगी।
वृष : उपहार में वृद्धि होगी। बुद्धि से किया गया कार्य संपन्न होगा।
मिथुन : गृह वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
कर्क : भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
सिंह : आर्थिक मामलों में सुधार होगा। जीवन सुखमय होगा।
कन्या : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
तुला : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। तनाव मिल सकता है।
वृश्चिक : जीवन सुखमय होगा। यात्रा की स्थिति सुखद होगी।
धनु : सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
मकर : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कुंभ : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
मीन : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

लाइफ स्किल

मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी अनुशासन

आज का युवा मोटिवेशनल वीडियो, रील्स और प्रेरणादायक भाषणों से घिरा हुआ है। इन्हें देख-सुनकर कुछ मिनटों के लिए ऊर्जा बढ़ती है, लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगता है और हम सोचते हैं कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उत्साह कम हो जाता है। यही कारण है कि केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहना स्थायी सफलता की गारंटी नहीं है। मोटिवेशन आपकी शुरुआत कराता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है।

विपुल शर्मा
मोटिवेशनल स्पीकर

अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें
हर युवा को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। परीक्षा में असफलता, इंटरव्यू में चयन न होना या किसी प्रयास का असफल हो जाना। मोटिवेशन ऐसे समय में कम हो सकता है, लेकिन अनुशासन आपको फिर से उठने की ताकत देता है। यदि आपने रोज मेहनत करने की आदत बना ली है तो एक असफलता आपको रोक नहीं पाएगी।

मोटिवेशन क्यों टिकता नहीं?: मोटिवेशन भावनाओं पर आधारित होता है। जब हम किसी सफलता की कहानी सुनते हैं या किसी उपलब्धि से प्रभावित होते हैं तो भावनात्मक रूप से प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन भावनाएं स्थायी नहीं होतीं। थकान, असफलता, आलोचना या परिणाम में देरी, ये सब प्रेरणा को कमजोर कर देते हैं। भारतीय युवाओं के सामने आज प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर की अनिश्चितता और इंटरनेट मीडिया का दबाव है। ऐसे में केवल प्रेरणा के भरोसे चलना मुश्किल है।

अनुशासन मतलब रोज की छोटी जीत: अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्य के अनुसार रोज व्यवहार करना, चाहे मन करे या न करे। रोज छोटे-छोटे नियम अपनाएं। समय पर उठना, दिन की योजना बनाना, लक्ष्य तय करना, निरंतर अभ्यास करना, ये साधारण नियम ही असाधारण परिणाम देते हैं। यदि कोई युवा रोज तीन-चार घंटे नियमित पढ़ाई करता है तो वह लंबे समय में उस छात्र से आगे निकल जाता है, जो केवल मोटिवेट होने पर पढ़ता है।

एक रूटीन बनाकर चलें: सफलता अचानक नहीं आती। यह आदतों का परिणाम होती है। जब आप रोज एक ही समय पर मेहनत करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस रूटीन का आदी हो जाता है।

राष्ट्रीय फलक

800 मीटर दूर तय हुई नमाज की जगह, मस्जिद पक्ष को मंजूर नहीं

भोजशाला विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार

- अंतरिम व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर धार प्रशासन ने तय किया वैकल्पिक स्थान
- मंदिर पक्ष ने स्थान को उचित बताया, मस्जिद पक्ष बोला- दूर नहीं जाएंगे, कोर्ट में चुनौती देंगे

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर से करीब 800 मीटर दूर जगह पर प्रशासन ने शुक्रवार की नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन मस्जिद पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया है। मस्जिद पक्ष के पैरोकारों ने इस जगह को भोजशाला से दो किलोमीटर दूर बताते हुए कहा है कि यहां नमाज अदा नहीं की जाएगी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अलबत्ता, मंदिर पक्ष ने प्रशासन द्वारा चयनित जगह को उचित बताया है।

उल्लेखनीय है कि गत 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि नमाज के लिए भोजशाला परिसर के निकट पृथक खुला स्थान उपलब्ध कराया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दोनों पक्षों के धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान प्रवेश और निकासी में किसी प्रकार की बाधा न आए। व्यवस्था अंतरिम होगी और अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उसका अध्ययन किया। इसके बाद धार कलेक्टर ने भोजशाला परिसर से करीब 800 मीटर दूर ग्राम मालीवाड़ा (40 पीर) की शासकीय नजूल भूमि पर शुक्रवार दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज के लिए पृथक खुला स्थान निर्धारित कर दिया। इससे नमाज की जगह को लेकर बीते दिनों से बनी असमंजस की स्थिति दूर तो हुई लेकिन मस्जिद पक्ष के रुख ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, मस्जिद पक्ष चाहता था कि नमाज के लिए भोजशाला से सटी भूमि उपलब्ध कराई जाए। इस पर मंदिर पक्ष को आपत्ति थी।

मस्जिद पक्ष के रुख की वजह से ही नई व्यवस्था के तहत इस शुक्रवार को नमाज नहीं हो सकी। मस्जिद पक्ष ने स्पष्ट किया है कि वह 24 और 31 जुलाई को भी निर्धारित किए गए स्थान पर शुक्रवार की नमाज अदा नहीं करेगा। इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को निर्धारित है। वहीं, प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन, दोनों पक्षों के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा तथा शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

धार में प्रशासन ने मस्जिद पक्ष को नमाज के लिए यह जमीन उपलब्ध कराई है। अगले सप्ताह नमाज हो सके इसके लिए सफाई भी करवा दी गई है। नईदुनिया

> मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों से चर्चा, अधिकारियों की रिपोर्ट और कानून-व्यवस्था के आकलन के बाद मालीवाड़ा का चयन किया गया। यह स्थान सुरक्षित है और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दोनों पक्षों के धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा नहीं आएगी।
> **- संजीव केशव पांडे, अपर कलेक्टर, धार**

> प्रशासन ने हमारी मांग के अनुरूप स्थान नहीं दिया। करीब दो किलोमीटर दूर तय किया गया स्थल हमें स्वीकार नहीं है। अब इस निर्णय को चुनौती देते हुए सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
> **- अब्दुल समद, सदर, मौलाना वेलफेयर सोसाइटी**

> नमाज के लिए तय नए स्थान पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी मांग केवल इतनी थी कि व्यवस्था भोजशाला परिसर और उसके आसपास से बाहर हो, ताकि पूजा-पाठ और दर्शन निर्बाध रूप से जारी रह सकें।
> **- गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति**

'थैंक यू मेरी जान' संदेश से नहीं टूट सकती शादी, तलाक रद, विवाह बहाल

राज्य ब्यूरो, जागरण • रांची

- झारखंड हाई कोर्ट ने कहा-फेसबुक संदेश को अवैध संबंध का सुबूत मानने में कुटुंब न्यायालय से हुई गंभीर भूल

फेसबुक पर आए एकमात्र "थैंक यू मेरी जान" संदेश को आधार बनाकर पति-पत्नी का रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महज एक इंटरनेट मीडिया संदेश और फेसबुक मित्रता को अवैध संबंध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने चाईबासा के कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित तलाक के आदेश को रद करते हुए दंपती का विवाह बहाल कर दिया।

हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि उस पर लगाए गए क्रूरता और अवैध संबंध के आरोप किसी ठोस साक्ष्य से सिद्ध नहीं हुए हैं। अवैध संबंध का आरोप किसी व्यक्ति पर गंभीर सामाजिक कलंक लगाता है, इसलिए इसे केवल संदेह या अधूरे साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मामले में पति ने पत्नी के फेसबुक मित्र द्वारा भेजे गए "थैंक यू मेरी जान" संदेश को अवैध संबंध का आधार बनाकर तलाक की मांग की थी। सुनवाई में पत्नी ने स्वीकार किया कि ऐसा संदेश आया था, लेकिन उसने उस पर आपत्ति जताई थी।

संबंधित व्यक्ति केवल फेसबुक मित्र था और उससे उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई। बिना किसी मुलाकात, घनिष्ठ संबंध या अन्य ठोस साक्ष्य के केवल एक संदेश के आधार पर अवैध संबंध का निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है।

अदालत ने कुटुंब न्यायालय के उस निष्कर्ष को भी गलत ठहराया, जिसमें पति की जेब से दो बार 10-20 रुपये निकालने की घटना को क्रूरता माना गया था। यह भी कहा कि अवैध संबंध वाले व्यक्ति को पक्षकार बनाए बिना उसके खिलाफ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था। इसी आधार पर 23 दिसंबर 2023 को चाईबासा कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित तलाक का आदेश रद कर दिया।

आसाराम की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से कथावाचक आसाराम के स्वास्थ्य के बारे में सही निर्देश लेने को गया है, जो चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा, "हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो।"

राजस्थान हाई कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 27 मई को 80 वर्षीय आसाराम की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा था। कथावाचक ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि एम्स ने कहा है कि आसाराम को जीवनशैली में कुछ बदलाव की जरूरत है। पीठ ने कहा, हम नहीं चाहते कि हम पर या आप पर कोई आरोप लगे।

100 वर्ष बाद भी संघ को लेकर समाज के बड़े वर्ग में भ्रमित जानकारी : राजनाथ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- रक्षा मंत्री बोले- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र की सेवा का प्रतीक, 100 वर्षों से अटूट समर्पण
- उपराष्ट्रपति भवन में हुआ पुस्तक 'आरएसएस एट 100 : एक सदी संकल्प की' का लोकार्पण समारोह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संघ पिछले 100 वर्षों से निरंतर देश और समाज की सेवा में लगा हुआ है, फिर भी समाज का एक बड़ा वर्ग इसके बारे में अनजान या गलत जानकारी वाला है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधारित पुस्तक 'आरएसएस एट 100: एक सदी संकल्प की' के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। यह पुस्तक भाजपा नेता श्याम जाजू और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी ने लिखी है। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया।

कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार के योगदान को याद करते हुए कहा कि 1925 में बोया गया यह बीज आज विशाल वटवृक्ष बन चुका है। संघ दुनिया का सबसे बड़ा और पूर्णतः आत्मनिर्भर स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया, 1962-65 के युद्ध, 1984 के सिख विरोधी दंगों और हर संकट में बिना स्वार्थ के लोगों की मदद की। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि संघ व्यक्ति के धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण के आधार पर लोगों को जोड़ता है। यह एकरूपता नहीं, बल्कि एकात्मता की बात करता है। यह 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' और 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत पर चलता है। राजनाथ ने संघ के योगदान पर कहा कि कश्मीर के भारत में विलय, दादरा-नगर हवेली और गोवा की मुक्ति में स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में संघ की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने 1950 में प्रेस की स्वतंत्रता और 1975 के आपातकाल का उदाहरण दिया।

पति से टूटा नई स्कूटी का इंडिकेटर, पत्नी ने चाकू से किया लहूलुहान

जागरण संवाददाता, चंपावत: शिक्षिका ने हाल ही में नई स्कूटी ली थी। शिक्षक पति बिना पूछे स्कूटी बाजार ले गए और उसका इंडिकेटर तोड़ लाए। घर पहुंचे तो कहासुनी इतनी बढ़ी कि पत्नी ने चाकू से उनके हाथ, गर्दन व पीठ पर वार कर दिए। लहूलुहान पति को पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में पति-पत्नी ने एक-दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है।

चंपावत के शिक्षक सुंदर नाथ गोस्वामी की पत्नी भी सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं। दंपती के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। बृहस्पतिवार को पत्नी की नई स्कूटी लेकर सुंदर नाथ बाजार से लौटे तो स्कूटी का इंडिकेटर टूटा हुआ मिला। इसके बाद पत्नी और उनके बीच बहस होने लगी। पड़ोसियों ने दोनों को उस समय शांत कराया लेकिन रात में फिर उनके बीच विवाद हो गया। गुस्साई पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पड़ोसी घायल सुंदर नाथ को लोहाघाट उप जिला अस्पताल ले गए।

मप्र में नरवर किले से 400 साल पुरानी 10 क्विंटल वजनी अष्टधातु की तोप चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी

- मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है नरवर किला, कचहरी महल के आंगन में रखीं थी 14 तोपें
- ऊंचाई से तोप को घसीटकर बाहर लाए फिर बेयरिंग लगी लकड़ियों की फ्रेम के सहारे नीचे ले गए

नरवर किले के कचहरी महल में इस स्टैंड पर रखी थी अष्टधातु की तोप। नईदुनिया

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर स्थित पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित नरवर किले के कचहरी महल में रखीं 400 साल पुरानी 14 तोपों में से एक तोप चोरी हो गई। 17वीं शताब्दी की अष्टधातु से बनी करीब 10 क्विंटल वजनी इस तोप को अज्ञात लोगों ने गत चार जुलाई को स्टैंड से नीचे गिरा दिया था, तब से यह नीचे ही पड़ी थी। उसके बाद मौका देखते ही 14 व 15 जुलाई की रात चोर इसे चोरी कर ले गए। मौके पर मिले साक्ष्यों के अनुसार, ऊंचाई पर बने किले और अधिक वजन के कारण चोर तोप को बेयरिंग लगी लकड़ी की फ्रेम पर रखकर घसीटते हुए ले गए। कुछ जगह लकड़ियों में रस्सी बांधकर उसे टांगा गया। गद्दों से लपेटा भी गया। किले के पिछले दरवाजे यानी उरवाई गेट की ओर ले जाकर नीचे उतारा और वाहन में लादकर ले गए।

शिवपुरी के एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि तोप को जिस रास्ते से ले जाया गया है, उसकी जांच की जा रही। किले की सुरक्षा में छह गार्ड हैं। रात में जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे वो करीब आठ बजे घर चले गए थे, इसके बाद तोप चोरी हुई है। जांच के लिए एक एसआइटी गठित की है।

सोने के लालच में चोरी की आशंका: बता दें कि पांच फीट 10 इंच लंबी और 30 इंच मोटी तोप कचहरी चौक के दाहिने कार्नर पर रखी थी। ये तोपें अष्टधातु की बनी हैं। अंदेशा है कि इस धातु में सोना भी शामिल है। इसी लालच में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इतनी बड़ी तोप को बेचने की अपेक्षा गलाने की योजना हो सकती है।

कचहरी महल में ऐसी 15 से 18 फीट तक की तोपें रखी गई हैं। 2011 में भी किले के पास एक तोप नरवर पुलिस ने बरामद की थी। यह तोप भी उसी तरह की है जैसी कचहरी चौक में रखी हुई हैं। इस तोप को पुलिस ने थाने के गेट पर रखवा दिया था।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण शनिवार, 18 जुलाई, 2026
आजकल
14
www.jagran.com

नादिया ने रचा ओलिंपिक इतिहास, बनाया पहला परफेक्ट 10

1976 में आज ही कनाडा के ओलिंपिक में 14 वर्षीय जिम्नास्ट नादिया कोमानेची ने अनइवन बार्स स्पर्धा में पहला परफेक्ट 10 स्कोर बनाया। स्कोरबोर्ड 10.00 दिखाने में सक्षम नहीं था, इसलिए 1.00 प्रदर्शित हुआ। इसी दौरान उन्होंने 7 परफेक्ट 10 और तीन स्वर्ण पदक जीते।

बांबे विश्वविद्यालय की स्थापना से आधुनिक शिक्षा युग शुरू हुआ

1857 में आज ही बांबे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह भारत के प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालयों में शामिल था, जिसे वुड्स डिस्पैच (1854) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय ने देश में आधुनिक उच्च शिक्षा व पेशेवर शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कादंबिनी गांगुली ने भारतीय महिला चिकित्सा को नई दिशा दी

कादंबिनी गांगुली का जन्म 1861 में आज ही वर्तमान बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनके पिता ब्रजकिशोर बसु महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कादंबिनी 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक बनने वाली पहली भारतीय महिलाओं में शामिल रहीं। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कालेज से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की व आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षित भारत की पहली महिला चिकित्सकों में स्थान बनाया। आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गईं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में ख्याति हासिल की। उन्होंने अनेक महिलाओं को उच्च शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 3 अक्टूबर 1923 को उनका निधन हो गया।

खोपड़ी की हड्डी देख चेहरा तैयार करेंगे विशेषज्ञ

उत्तर पश्चिम भारतीय आबादी पर शोध के दौरान मिली कामयाबी, आसान होगी अज्ञात शवों की शिनाख्त

पीजीआइ चंडीगढ़ में फोरेंसिक रेडियोलाजी विभाग में कार्यरत डा. मोहिंदर शर्मा व टीम ने किया शोध

हंसराज सैनी ● जागरण

डा. मोहिंदर शर्मा, फोरेंसिक रेडियोलाजी विभाग पीजीआइ चंडीगढ़। सौ. स्वयं

चेहरे की पहचान में क्यों खास है नाक?

किसी भी इंसान के चेहरे को पहचानने में उसकी नाक की केंद्रीय भूमिका होती है। चेहरा दोबारा तैयार करते समय नाक का सही आकार ढूंढना ही सबसे मुश्किल माना जाता है। इस खोज के बाद खोपड़ी की हड्डियों को देखकर ही नाक की सटीक चौड़ाई का पता चल जाएगा, जिससे स्कैच या 3डी माडल इंसान जैसा दिखेगा। शोध का सीधा फायदा देश की जांच एजेंसियों, पुलिस और फोरेंसिक मानवविज्ञानियों को मिलेगा। इससे चेहरे की सटीक पहचान की जा सकेगी। वर्षों पुराने अनसुलझे हत्या के मामले, लावारिस शवों की शिनाख्त का संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय मिलने वाले नरकंकालों की पहचान अब इस स्वदेशी तकनीक के जरिए बेहद आसानी से की जा सकेगी। इसके जरिये वर्षों पुराने कंकालों की पहचान आसानी से हो सकेगी, जिसका उपयोग शोध या अन्य चीजों में किया जा सकेगा।

नाक की हड्डी की बनावट पर किया गया शोध। सौ. शोधकर्ता

मंडी : फोरेंसिक विशेषज्ञ अब खोपड़ी की हड्डियों की बनावट को देखकर मृत व्यक्ति का चेहरा तैयार कर सकेंगे। इससे अज्ञात शवों की शिनाख्त में मदद मिलेगी। पीजीआइ चंडीगढ़ में फोरेंसिक रेडियोलाजी विभाग में कार्यरत डा. मोहिंदर शर्मा व टीम ने उत्तर पश्चिम भारतीय आबादी पर शोध के दौरान आधुनिक व स्वदेशी फार्मूला विकसित किया है।

इससे उन पेचीदा आपराधिक मामलों को हल करने में सफलता मिलेगी, जिनमें शव पूरी तरह गल चुका है और पहचान के पारंपरिक साधन जैसे डीएनए या फिंगरप्रिंट पूरी तरह फेल हो जाते हैं। डा. मोहिंदर शर्मा हिमाचल के रहने वाले हैं। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल आफ लीगल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है।

फोरेंसिक मामलों में अब तक भारतीय चेहरों का खाका खींचने के लिए पश्चिमी देशों के डाटा या फार्मूलों का सहारा लिया जाता था, जिससे अक्सर नतीजे सटीक नहीं आते थे। इस कमी को दूर करने के लिए शोधार्थियों ने 18 से 80 वर्ष की आयु के लोगों के सीटी स्कैन डाटा का गहराई से अध्ययन किया। रेडिएंट डीकाम व्यूअर साफ्टवेयर की मदद से मानव खोपड़ी की बनावट, विशेष रूप से नाक के हिस्से की हड्डियों की बारीक पैमाइश की गई। इसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तकनीक से एक सटीक गणितीय समीकरण तैयार किया जो खोपड़ी की हड्डी के आधार पर नाक की वास्तविक चौड़ाई बताने में पूरी तरह सक्षम है। इस शोध की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष की हड्डियों की बनावट में होने वाले प्राकृतिक अंतर का विशेष ध्यान रखा गया है। शोधार्थियों ने पाया कि उत्तर पश्चिम भारतीय आबादी में पुरुषों और महिलाओं के चेहरे की हड्डियों की संरचना अलग होती है। इसलिए, दोनों के लिए अलग-अलग माडल तैयार किए गए हैं, ताकि सटीकता में कमी न रहे। जांच में सामने आया कि इस फार्मूले से अनुमानित की गई नाक और वास्तविक नाक के क्षेत्रफल में मात्र पांच वर्ग मिमी का ही अंतर था जो कि विज्ञान की दुनिया में न के बराबर माना जाता है।

नोलन ने द ओडिसी के प्रीमियर में भारतीय डिजाइनर की टाई पहनी

- यह अजरक फैब्रिक से बनी है जो गुजरात के कच्छ इलाके की परंपरा है
- डिजाइनर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्ममेकर की तस्वीरें साझा कीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : न्यूयार्क में अपनी फिल्म द ओडिसी के प्रीमियर पर फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन, भारतीय डिजाइनर आहन टंडन की डिजाइन की हुई कस्टम टाई पहने नजर आए। यह अजरक फैब्रिक से बनी है, जो गुजरात के कच्छ इलाके की सदियों पुरानी हाथ से ब्लाक-प्रिंटिंग और रेजिस्ट-डाइंग परंपरा है।

डिजाइनर ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्ममेकर की तस्वीरें साझा कीं, जो हाल ही में फिल्म के प्रीमियर के लिए भारत आए थे। इन तस्वीरों में मैट डेमन और ऐनी हैथवे भी नजर आए। टंडन न्यूयार्क में रहते हैं। वह पार्सन्स स्कूल आफ डिजाइन से ग्रेजुएट हैं। नोलन की द ओडिसी शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म की कहानी ग्रीक कवि होमर के महाकाव्य पर आधारित है।यह फिल्म ग्रीक राजा ओडिसियस के बारे में है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने की 10 साल की खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। बदला लेने वाले देवताओं, समुद्री राक्षसों और जादूगरनियों से घिरे होने के बावजूद, वह पत्नी पेनेलोप व बेटे टेलीमैकस से दोबारा मिलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म सिंकोपी इंक के बैनर तले बनी है।

फिल्म 'द ओडिसी' के न्यूयार्क प्रीमियर में क्रिस्टोफर नोलन पत्नी एम्मा थामस के साथ शामिल हुए। फिल्म निर्माता ब्लैक सूट और पैटर्न वाली टाई में आकर्षक लग रहे थे। एएफपी

एआइ आधारित एप खत्म करेगा मूक-बधिरों के संवाद की बाधा

सुमेश ठाकुर ● जागरण

- आइआइटी रोपड़ ने विकसित किया एप, इंडियन साइन लैंग्वेंज पर बनाया नया एआइ एप, शामिल होंगी देश की सभी क्षेत्रीय भाषाएं
- वाटिका स्कूल सेक्टर-19 के 15 विद्यार्थियों पर किया ट्रायल रहा सफल, विद्यार्थियों ने सीखी डिजिटल मार्केटिंग इन एआइ

चंडीगढ़ : भारतीय मूक-बधिर लोगों के साथ संवाद की चुनौती इंडियन साइन लैंग्वेज (आइएसएल) को न समझ पाना है। अब इस समस्या का समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के माध्यम से सामने आ रहा है।

आइआइटी रोपड़ ने ऐसा एआइ आधारित आइएसएल एप विकसित किया है, जो सामान्य व्यक्ति और मूक-बधिर के बीच संवाद को आसान बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। यह एप प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (नेचुरल लैंग्वेंज प्रोसेसिंग) और कंप्यूटर विजन जैसी एआइ तकनीकों पर आधारित है। एप में उपयोगकर्ता जैसे ही हिंदी, अंग्रेजी या अन्य उपलब्ध भाषा में कोई वाक्य टाइप करेगा, सिस्टम उसे भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलकर प्रदर्शित करेगा। इससे आइएसएल नहीं जानने वाला व्यक्ति भी मूक-बधिर से आसानी से अपनी बात सांझा कर सकेगा। वहीं एप में कैमरा आधारित फीचर जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से यदि कोई मूक-बधिर व्यक्ति सांकेतिक भाषा में कुछ बताएगा तो कैमरा उसके हाथों, आंखों की गतिविधियों और संकेतों को पहचानकर उन्हें सामान्य लिखित भाषा में बदल देगा। इससे दोनों ओर से संवाद संभव हो सकेगा।

डिजिटल डिवाइस पर ही होगा इंस्टाल

एप को मोबाइल फोन, लैपटाप और कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइस पर उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है। अभी तक इसमें हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि भविष्य में भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा, ताकि विभिन्न राज्यों के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इस तकनीक का पहला ट्रायल चंडीगढ़ के सेक्टर-19 स्थित बाल वाटिका विशेष विद्यालय के 15 मूक-बधिर विद्यार्थियों पर किया गया। विद्यार्थियों को आइआइटी रोपड़ में डिजिटल मार्केटिंग इन एआइ का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों के बीच हुए सांकेतिक संवाद, सामान्य भाषा के प्रयोग और व्यवहारिक परिस्थितियों से प्राप्त डाटा को एप के एआइ मॉडल में शामिल किया गया। प्रारंभिक परीक्षण सफल रहा और एप ने संवाद को प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया।

हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में कार्य कर रहा एप

आइआइटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा के मार्गदर्शन तथा डीन प्रो. पुष्पिंदर सिंह के नेतृत्व में इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। प्रो. पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि अभी एप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में कार्य कर रहा है। लक्ष्य इसे देश की सभी प्रमुख भाषाओं तक विस्तारित करना है, ताकि किसी भी राज्य का व्यक्ति बिना सांकेतिक भाषा सीखे मूक-बधिर समुदाय से सहजता से संवाद कर सके। उनका मानना है कि यह तकनीक समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

प्रो. राजीव आहूजा, निदेशक आइआइटी रोपड़। स्वतः

प्रो. पुष्पिंदर सिंह डीन आइआइटी रोपड़। स्वतः

त्वचा की नर्व सेल्स गर्मी-ठंड को करेंगी महसूस

- नई अध्ययन ने पहले की खोजों को दी चुनौती, जिसमें कहा गया कि अलग-अलग नर्व सेल्स का करती हैं इस्तेमाल
- चूहों पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने देखा कि हजारों थर्मोरिसेप्टर सेल्स ठंडे और गर्म तापमान पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : नए शोध से पता चला कि त्वचा की संवेदनशील नर्व सेल्स (तंत्रिका कोशिकाएं) तापमान में ठंडक व गर्मी को महसूस कर सकती हैं। यह आम धारणा को चुनौती देता है जिसके अनुसार त्वचा अलग-अलग तापमान का पता लगाने के लिए अलग-अलग नर्व सेल्स का इस्तेमाल करती हैं।

आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी आफ क्वींसलैंड के क्वींसलैंड ब्रेन इंस्टीट्यूट की लेखिका क्लेरिसा व्हिटमायर ने कहा कि खास तरह की नर्व सेल्स जिन्हें थर्मोरिसेप्टर्स कहा जाता है इंसानों के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कोशिकाएं दिमाग तक यह जानकारी पहुंचाती हैं कि शरीर की सतह पर क्या हो रहा है। व्हिटमायर ने कहा कि अध्ययन दिखाता है कि गर्मी और ठंड को महसूस करने के लिए दो अलग-अलग तंत्रिका कोशिकाओं पर निर्भर रहने के बजाय शरीर के थर्मोरिसेप्टर्स दोनों संवेदनाओं को मस्तिष्क तक संकेत भेज सकते हैं, ठंडे परिस्थितियों में गतिविधि बढ़ाते हैं और तापमान बढ़ने पर कम करते हैं। जर्नल न्यूरान में प्रकाशित निष्कर्ष यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने और बीमारियां शरीर के थर्मोरिसेप्टर्स को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। चूहों पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने देखा कि हजारों थर्मोरिसेप्टर सेल्स ठंडे और गर्म तापमान पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह अध्ययन रोजमर्रा के सामान्य तापमान पर केंद्रित था, जैसे ठंडे कमरे में जाना या नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना। लेखकों ने लिखा, ज्यादातर थर्मोरिसेप्टर्स ठंडे तापमान पर सक्रिय होते हैं और गर्म तापमान पर उनकी गतिविधि कम हो जाती है। क्वींसलैंड ब्रेन इंस्टीट्यूट के फिल बोकिनिएक ने कहा कि शरीर के थर्मोरिसेप्टर्स के बारे में नई जानकारी से उन लोगों के इलाज में मदद मिल सकती है जो थर्मल डिसफंक्शन (तापमान से जुड़ी समस्याओं) से जूझ रहे हैं। इंसान अपने शरीर के अंदरूनी तापमान को कंट्रोल करता है, इसलिए सही तापमान का अहसास होना होमियोस्टैसिस के लिए जरूरी है। होमियोस्टैसिस शरीर की वह क्षमता है जिससे वह अंदरूनी माहौल को स्थिर बनाए रखता है। स्पाइनल कार्ड की चोट, डायबिटीज या पेरिफेरल न्यूरोपैथी से पीड़ितों में थर्मल सेंसर्स पर असर पड़ सकता है, जिससे बाहरी तापमान में बदलाव के हिसाब से प्रतिक्रिया देना मुश्किल होता है।

इधर-उधर

... यूं मिला 39 करोड़ वर्ष पुराना उल्कापिंड क्रेटर

कैंप लगाने के लिए शांत जगह तलाश रहे थे लापोंत। इंटरनेट मीडिया

ओटावा, एजेंसी : कनाडा के जोएल लापोंत छुट्टियों में कैंपिंग के लिए एक शांत जगह तलाश रहे थे। इसी दौरान गूगल मैप्स पर स्क्राल करते हुए उनकी नजर क्यूबेक के जंगलों में बनी एक अजीबोगरीब, बिल्कुल गोल आकृति पर पड़ी। उन्होंने जब इसकी तस्वीरें विज्ञानियों को भेजीं, तो भूवैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि यह करीब 39 करोड़ साल पुराना विशाल उल्कापिंड क्रेटर है। लगभग 25 किमी चौड़ा यह क्रेटर इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरा शहर समा सकता है। करोड़ों साल पहले जब विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया होगा, तब इसके प्रभाव से इलाके में भारी तबाही मची होगी।

मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर होने का कोई प्रमाण नहीं

अनुसंधान

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हर जगह मौजूद हैं। इन्हीं की वजह से आप रेडियो पर संगीत सुन पाते हैं, वाई-फाई का इस्तेमाल कर पाते हैं, सेटेलाइट नेविगेशन से रास्ता ढूंढ पाते हैं और मोबाइल फोन पर बात कर पाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक रूप हैं और कम तीव्रता वाले स्पेक्ट्रम में आती हैं, यानी इनमें सबसे कम ऊर्जा और सबसे लंबी वेवलेंथ होती है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत अधिक ऊर्जा वाले रूप (जैसे एक्स-रे) से कैंसर हो सकता है, इसलिए लंबे समय से यह चिंता रही है कि रेडियो तरंगें भी इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

पिछले दो दशकों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ, इस बात को लेकर खास चिंता रही है कि इसे कान के पास रखने से ब्रेन कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है। 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के सेहत पर असर को लेकर 13 रिव्यू करवाए। आज जारी हुए शोध में इन रिव्यू के नतीजों का विश्लेषण किया गया है। इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से दिमाग, सिर या गर्दन में कैंसर होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिव्यू कराने का मकसद यह समझना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से सेहत पर होने वाले असर के बारे में हम क्या जानते हैं और हमें और क्या पता लगाने की ज़रूरत है। विज्ञानियों की टीम ने सेहत से जुड़ी किसी खास समस्या के बारे में मौजूद वैज्ञानिक सबूतों की जांच की और एक रिपोर्ट जारी की। इसमें सेहत से जुड़ी कई अलग-अलग समस्याओं पर रिव्यू किए गए, जिनमें फर्टिलिटी, सिरदर्द या टिनिटस (कान में सीटी बजने जैसा शोर) जैसे लक्षण और कैंसर शामिल थे। (द कन्वर्सेशन)

शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांफ्रेंस

चीन के शंघाई में शुक्रवार को वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांफ्रेंस (डब्लूएआइसी) के दौरान यूनिट्री बूथ पर ह्यूमनाइड रोबोट को डांस करते हुए देखते लोग। यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख तकनीकी मंच है। इसका आयोजन हर साल चीन के शंघाई शहर में किया जाता है, जिसमें वैश्विक टेक कंपनियों, विज्ञानियों और उद्योग के दिग्गजों द्वारा नवीनतम एआइ तकनीकों (जैसे लार्ज लैंग्वेज माडल और ह्यूमनाइड रोबोट) का प्रदर्शन किया जाता है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना, तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करना और सुरक्षित तथा जिम्मेदार एआइ विकास के लिए वैश्विक शासन पर चर्चा करना है। एएफपी

स्क्रीन शाट

दीपिका पादुकोण ने गर्भावस्था में बढ़ाई काम की रफ्तार

आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा में रही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इन दिनों रात की शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। दरअसल, दीपिका दूसरी बार गर्भवती हैं। ऐसे में मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले दीपिका को अपनी फिल्म राका की शूटिंग खत्म करनी है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता अल्लू अर्जुन हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार सात महीने गर्भवती दीपिका इस दौरान कई चुनौतीपूर्ण एक्शन सीन की शूटिंग कर रही हैं। वह मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले फिल्म की शूटिंग पूरी करना चाहती हैं, इसलिए वह रात की शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। फिल्म राका को तय समय पर पूरा करने के लिए दीपिका पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण एक्शन सीक्वेंस की भी शूटिंग वह लगातार कर रही हैं। इन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद, वह अपनी आने वाली फिल्मों को समय पर पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही हैं। इस दौरान उनके काम के प्रति समर्पण देखते बनता है। फिल्म की पूरी टीम दीपिका के इस समर्पण और पेशेवर रवैये से बेहद प्रभावित है। उन्हें इस तरह काम करते देखना सेट पर मौजूद सभी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि घर पर उनकी डेढ़ साल की बेटी भी है, जिसे अपना समय देने के साथ वह अपना काम भी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि इस साल अप्रैल में दीपिका और अभिनेता रणवीर सिंह ने घोषणा की थी कि वे दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। फिल्म राका के अलावा दीपिका फिल्म किंग में शाह रुख खान के साथ भी नजर आएंगी।

दूसरी बार गर्भवती हैं दीपिका। फाइल

गोविंदा की नहीं, सिर्फ अपने बेटे की बात करना चाहती हैं सुनीता

पिछले दिनों जब अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रियलिटी शो लाक अप : सच या सजा अपनी सेहत से जुड़े कारणों की वजह से छोड़ा था, तो गोविंदा खुद उन्हें लेने सेट पर पहुंचे थे। उस वक्त ऐसा लगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि अब फिर सुनीता ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे लग रहा है कि दोनों के बीच रिश्तों में खटास बनी हुई है। दरअसल, पिछले दिनों गोविंदा ने अपने प्रोडक्शन में बनने वाली नई फिल्म रूपा पर जानकारी दी थी। फिल्म में वह अभिनय भी करने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर हाल ही में जब सुनीता से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझसे केवल मेरे और मेरे बेटे (यशवर्धन आहूजा) की फिल्म की बात करिए। एकता (निर्माता एकता कपूर) हमारी फिल्म की निर्माता हैं, उन्होंने (फिल्म पर) बहुत पैसा खर्च किया है। हर जगह आप लोग यशवर्धन और सुनीता की ही बात करें। मुझे बाकी किसी के लिए कोई बात नहीं करनी है। गोविंदा ने रूपा की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके बेटे यशवर्धन उनसे भी आगे जाएंगे। सुनीता ने आगे कहा कि बिल्कुल, मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैंने उन्हें बड़ा किया है। मैंने उनके साथ काम किया है, उनके काम को देखा है। सौ फीसदी वह बहुत आगे जाएंगे।

सुनीता के बेटे यशवर्धन कर रहे हैं एकता कपूर की फिल्म से अभिनय में पदार्पण। इंस्टाग्राम - @officialsunitaahuja

बचपन में डांस क्लास से भाग जाया करती थीं रेखा

बचपन की यादें बेहद खूबसूरत होती हैं। उन्हें याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसी ही यादों में रियलिटी शो इंडियन आइडल के सप्ताहांत एपिसोड में लेकर जाएंगी अभिनेत्री हेमा मालिनी। उन्होंने अभिनेत्री रेखा के साथ अपनी वर्षों पुरानी दोस्ती से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए। दरअसल, शो के होस्ट आदित्य नारायण ने हेमा मालिनी से पूछा कि आपने और रेखा ने लगभग आठ फिल्मों में साथ काम किया है। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? इस पर हेमा मालिनी ने कहा कि मैंने रेखा को तब देखा था, जब वह छोटी थीं। मैं चेन्नई में भरतनाट्यम सीख रही थी और उसी दौरान मैंने कुचिपुड़ी की भी ट्रेनिंग शुरू की थी। मैं गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जी के पास नृत्य सीखने जाती थी। उस समय मेरी फिल्म सपनों का सौदागर रिलीज हो चुकी थी। उस डांस क्लास में रेखा भी आती थीं। गुरुजी कहते थे कि यह डांस रिहर्सल से भाग जाती है, इसे पकड़ना मुश्किल है। वह बचपन में शरारती थीं। हमने गुरुजी का एक डांस बैले (नृत्य नाटक) किया था, जो श्रीकृष्ण, रुक्मिणी व सत्यभामा की कहानी पर आधारित था। उसमें रेखा ने कुचिपुड़ी शैली में नारद मुनि का पात्र किया था। नारद की वेशभूषा में वह प्यारी लग रही थीं। तब अंदाजा नहीं था कि कुछ साल बाद वह बाम्बे (मुंबई) आएंगी और हिंदी सिनेमा की इतनी बड़ी अभिनेत्री बन जाएंगी।

आज भी रेखा और हेमा मालिनी हैं अच्छी सहेलियां। फाइल

अब प्रीतम एंड पेड्रो के सीक्वल की ओर बढ़े राजकुमार

जब कहानी पसंद आती है, तो उसे आगे बढ़ाने के मौके बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ राजकुमार हिरानी निर्मित वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो के साथ भी हो रहा है। शो का अंत कहीं न कहीं सीक्वल की ओर इशारा कर रहा था और अब खुद राजकुमार हिरानी ने इस पर स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि हां, हम इसका सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है कि कहानी को किस दिशा में लेकर जाना है। क्या यह फैसला उन्होंने शो को मिल रही प्रतिक्रियाओं के बाद लिया? तो उन्होंने कहा कि मैं सरसरी निगाहों से देख लेता हूं। दर्शकों के मिलने वाले संदेशों से हमें पता तो चल ही जाता है कि कोई फिल्म या सीरीज उन्हें कितनी पसंद आ रही है। कई लोग सामने से भी सराहना करते हैं, तो भी काफी कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है। जब दर्शकों को कुछ पसंद नहीं आता है, तो वह खामोश रहते हैं। वह केवल शो के किसी एक पहलू की सराहना कर देते हैं, लेकिन पूरी फिल्म या सीरीज की चर्चा नहीं करते हैं। इस शो के मामले में तो यह प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा रही। आगे हिरानी कहते हैं कि मैंने हर बार एक अलग कहानी कहने की कोशिश की है। इस शो की कहानी साइबर क्राइम पर है। इससे पहले मैंने इमिग्रेशन, संजय दत्त की बायोपिक, एलियन व भगवान, मेडिकल कालेज और शिक्षा जैसे अलग-अलग विषयों पर फिल्में बनाई हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि कहानियों को मजेदार अंदाज में पेश करूं। मेरा मकसद दर्शकों का मनोरंजन करना है।

दर्शकों का मनोरंजन करना हिरानी की है प्राथमिकता। टीम राजकुमार

DailyEpaper.in

One Place. Endless Reading.

INDIA'S MOST TRUSTED
DIGITAL READING PLATFORM
Newspapers . Magazines . Editorials

15K+ Happy Users in Paid Plan | **7 Million+** Readers on Websites | **100% Safe** Secure & Ad-Free

CHOOSE YOUR PERFECT PLAN

All Newspapers. All Magazines. All Editorials. One Subscription.

1 ALL HINDI PASS

Perfect For
Hindi Readers, State Govt Aspirants & General Readers

INCLUDES
- 24+ All Hindi Newspapers
- Daily Editorial
- Full Edition - Single Edition (All Major Cities)
- Easy to Read & Download

24+ HINDI NEWSPAPERS

DURATION	PRICE	
1 MONTH	~~₹149~~	₹79
6 MONTHS	~~₹499~~	₹279
1 YEAR	~~₹799~~	₹419

CLICK HERE

2 ALL ENGLISH PASS

Perfect For
UPSC, SSC, Bank, MBA, Professionals & English Readers

INCLUDES
- 25+ All English Newspapers
- Daily Editorial
- Full Edition -Single Edition (All Major Cities)
- Easy to Read & Download

25+ ENGLISH NEWSPAPERS

DURATION	PRICE	
1 MONTH	~~₹169~~	₹89
6 MONTHS	~~₹599~~	₹289
1 YEAR	~~₹899~~	₹429

CLICK HERE

3 PREMIUM NEWSPAPER PASS

Perfect For
UPSC, IAS, Professionals & Editorial Readers

INCLUDES
- The Hindu
- The Indian Express
- Business Line
- The News Indian Express
- Daily Editorial

3-DAY TRIAL
₹19 ~~₹49~~

DURATION	PRICE	
1 MONTH	~~₹129~~	₹69
6 MONTHS	~~₹499~~	₹269
1 YEAR	~~₹699~~	₹399

CLICK HERE

⭐ MOST POPULAR ⭐ 4 ALL IN ONE PASS

Perfect For
UPSC, SSC, Banking, PCS, Judiciary, CUET, Researchers & Journalists

INCLUDES
- All Hindi Newspapers (24+)
- All English Newspapers (25+)
- Daily Editorial
- International Newspapers (Top Global Newspapers)
- Full Edition - Single Edition (All Major Cities)
- 2-Year Backup IN PDF (only in Yearly Plan)

3-DAY TRIAL
₹29 ~~₹69~~

DURATION	PRICE	
1 MONTH	~~₹249~~	₹129
6 MONTHS	~~₹899~~	₹499
1 YEAR	~~₹1299~~	₹749

CLICK HERE

5 MAGAZINE PASS

Perfect For
Current Affairs, Knowledge, Business & Exam Preparation

INCLUDES
- 125+ Indian Magazines
- 150+ International Magazines
- Daily Update (New Magazines)
- Easy to Read & Download
- All Categories Covered

125+ INDIAN MAGAZINES
150+ INTERNATIONAL MAGAZINES

DURATION	PRICE	
1 MONTH	~~₹249~~	₹149
6 MONTHS	~~₹1199~~	₹699
1 YEAR	~~₹1799~~	₹999

CLICK HERE

- **SINGLE EDITIONS** All Papers In One Place
- **DAILY UPDATES** After 6 AM Everyday
- **EASY TO READ** Mobile, Tablet & Desktop
- **DAILY EDITORIALS** Excluded in Every Plan
- **SECURE & AD-FREE** 100% Safe Experience
- **24X7 SUPPORT** Always Here To Help You

PERFECT FOR ASPIRANTS & PROFESSIONALS

UPSC/IAS · SSC · BANKING · PCS/STATE PCS · JUDICIARY · DEFENCE · RESEARCHERS · STUDENTS

LIMITED TIME OFFER!

Save More with 6 Months & 1 Year Plans!
More Duration, More Savings!

100% Safe Payments
Multiple Payment Options
UPI · Paytm · PhonePe · G Pay · VISA · RuPay

Trusted By Thousands | 7Million+ Reader on Website | Daily Updates | Unmatched Collection | One Subscription | Endless Benefits